

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XVIII, Ninth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 8, Wednesday, July 27, 2016/Shravana 5, 1938 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 141 to 145	10-73
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 146 to 160	74-137
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	138-869

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	871-874
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
24 th Report	875
MOTION RE: 33rd REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	875
SUBMISSION BY MEMBER	
Re: Dope Testing in Sports	876-877
LOKPAL AND LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2016	882,936-949
Motion to Consider	936
Dr. Jitendra Singh	936-949
Clauses 2, 3 and 1	942
Motion to Pass	949
MATTERS UNDER RULE 377	909-935
(i) Need to undertake repair of Khalilabad-Bakhira-Mehdawal road in Sant Kabir Nagar parliamentary constituency, Uttar Pradesh	
Shri Sharad Tripathi	910
(ii) Need to provide adequate funds to the Tocklai Tea Research Institute at Jorhat in Assam	
Shri Kamakhya Prasad Tasa	911-912
(iii) Need to conduct proceedings of cases in High Courts in regional languages	
Shrimati Darshana Vikram Jardosh	913

- (iv) Need to curb illegal sand mining by having a National Policy

Shrimati Rakshatai Khadse

914

- (v) Need to probe the shoddy construction work of sewerage and pipe line system under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal System in Kanpur Nagar, Uttar Pradesh
- Shri Devendra Singh Bhole 915
- (vi) Need to construct a railway line between Jalgaon and Solapur in Maharashtra
- Shri Raosaheb Patil Danve 916
- (vii) Need to provide compensation to farmers in Jammu and Kashmir who lost their land due to fencing along the border
- Shri Jugal Kishore 917
- (viii) Need to set up a special group to report on the problems afflicting the hydel sector in Himachal Pradesh
- Shri Ram Swaroop Sharma 918
- (ix) Need to construct school building for Kendriya Vidyalaya at Chitrakoot, Uttar Pradesh
- Shri Bhairon Prasad Mishra 919
- (x) Need to facilitate environmental clearance for construction/development of stretch of National Highway No. 28B passing through Valmiki Nagar parliamentary constituency, Bihar
- Shri Satish Chandra Dubey 920

- (xi) Need to bring civilian areas of various Cantonments under nearby Corporation or Municipality
Shri Laxmi Narayan Yadav 921
- (xii) Need to set up an Agriculture Engineering Institute in Jalaun district of Uttar Pradesh
Shri Bhanu Pratap Singh Verma 922
- (xiii) Need to provide clean and safe drinking water to people in Ballia parliamentary constituency, Uttar Pradesh
Shri Bharat Singh 923
- (xiv) Need to provide land for setting up of a Cancer Research Centre and Hospital at Bhandup in Mumbai
Dr. Kirit Somaiya 924
- (xv) Need to provide broadband connectivity to Post Office, Suwana in Bhilwara parliamentary constituency, Rajasthan
Shri Subhash Chandra Baheria 925
- (xvi) Need to provide assistance to Kerala for completing the seawall along its coastline
Shri Mullappally Ramachandran 926
- (xvii) Regarding rejuvenation and replanting of coconut palms in Tamil Nadu
Shri C. Mahendran 927
- (xviii) Regarding expansion of Salem Steel Plant in Tamil Nadu
Shri V. Panneerselvam 928

- (xix) Need to release funds to Government of Andhra Pradesh for the Panchayati Raj Department of the State
- Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) 929-930
- (xx) Need to include Saudi Arabia among those countries which are exempted from bio-metric visas
- Shri P. K. Biju 931
- (xxi) Need to grant special category status to Bihar
- Shri Kaushalendra Kumar 932
- (xxii) Need to review the decision to handover 12 oilfields to private parties in Assam
- Shri Badruddin Ajmal 933
- (xxiii) Need to address the problems faced by people belonging to Kachari community in Assam to get ST certificate
- Shri Naba Kumar Sarnia 934-935

**BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION)
AMENDMENT BILL, 2015**

	950-1063
Motion to Consider	950
Shri Arun Jaitley	950-953, 1043-1054
Shri S. P. Muddahanume Gowda	954-962
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	963-969
Shri M. Udhayakumar	970-976
Shri Kalyan Banerjee	977-981
Shri Ladu Kishore Swain	982-984
Dr. Ravindra Babu	985-988
Shri Sankar Prasad Datta	989-991
Shri Konda Vishweshwar Reddy	992-998
Shri Y. V. Subba Reddy	999-1001
Shri Prahlad Singh Patel	1002-1007
Shri N. K. Premchandran	1008-1018
Dr. Udit Raj	1019-1022
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	1023-1024
Shri Vinayak Bhaurao Raut	1025-1027
Kumari Sushmita Dev	1028-1029
Shri Prem Singh Chandumajra	1030-1031
Shri Kaushalendra Kumar	1032-1033
Shri C. N. Jayadevan	1034-1035
Shri C. K. Sangma	1036-1038

Dr. Boora Narsaiah Goud	1039-1040
Prof. Saugata Roy	1041-1042
Clauses 2 to 11 and 1	1055-1062
Motion to Pass	1063

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	1064
Member-wise Index to Unstarred Questions	1065-1070

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	1071
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	1072-1073

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, July 27, 2016/Shravana 5, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I will allow you in 'Zero Hour', not now.

11.01 ½ hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 141, Shri Vinod Kumar Sonkar.

(Q. 141)

श्री विनोद कुमार सोनकर: अध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम अपनी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि गांव, गरीब और किसान की चिन्ता करते हुए, उन्होंने देश में पहली बार गांव, गरीब और किसानों के लिए बजट पेश किया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, पोस्टल विभाग भी पूरी तरह से गांव, गरीब और किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विस्तार से जानकारी दी है। इलाहाबाद डाक मंडल में दो जिले हैं - इलाहाबाद और कौशाम्बी। इनका विभाजन वर्ष 1997 में हुआ, किन्तु कौशाम्बी जिले में आज तक प्रधान डाकघर की स्थापना नहीं हो पाई है, जबकि जिले में प्रतिदिन के आधार पर सभी कार्य, जैसे संबंधित डाकघरों को नगदी, योजना, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पोस्ट, पार्सल, मनीऑर्डर आदि कार्य इलाहाबाद से होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में संचार क्रान्ति आई है, संचार के बहुत से माध्यम विकसित हुए हैं। लोग मोबाइल से बात करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन आज भी गांव के गरीब, किसान और मजदूर पोस्ट ऑफिस पर निर्भर हैं। डाक विभाग को कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जोड़ने एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक चलाने की सैद्धान्तिक रूप से अनुमति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं सरकार द्वारा दे दी गयी है। पूरे भारतवर्ष में सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन हेतु जन-धन योजना या प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा की अन्य जितनी योजनाएं हैं, क्या सरकार उन योजनाओं को चलाने की अनुमति पोस्ट ऑफिसेज को देगी?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न पूछे हैं। उनकी मूल चिन्ता यह है कि इलाहाबाद से निकलकर, जो नया कौशाम्बी जनपद बना, वहां मुख्य डाकघर नहीं है। यह सच है कि डाक विभाग ने पहले से कुछ कड़े नियम बनाए हुए हैं कि जब भी नए जनपद बनते हैं तो कम से कम

60 या उससे अधिक सब-पोस्ट ऑफिसेज होने पर ही बाईफर्केशन होता है। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 15 ऐसे नए जिले हैं, जहां पर हेड पोस्ट ऑफिस नहीं बन सके हैं। माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, मैंने उसका संज्ञान लिया है और आगे मैं उनको इस बारे में बताऊंगा।

स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की पहल के आधार पर हमने लगभग 22688 जगहों पर कोर बैंकिंग सेवा प्रारम्भ की है। कुछ जो स्थान रह गए हैं, वहां कोई तकनीकी कारण है या ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें अनुमति दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सितम्बर, 2017 तक लगभग 650 स्थानों पर हम यह सेवा शुरू कर देंगे। जो समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और मनरेगा, इनके ढेर सारे खाते पोस्ट ऑफिसेज में हैं। आने वाले समय में जिन योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है- अटल पेंशन योजना, जन-धन योजना, इस दिशा में भी हमारे जो बैंक खुलेंगे, वह काम हम करेंगे। सामान्य लोगों को अधिक से अधिक पारदर्शी तरीके से लाभ मिले, इसी दिशा में इस सरकार ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। मैं अपने पूर्व मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिस लगन से उन्होंने इस विभाग को आगे बढ़ाया है, उसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे।

श्री विनोद कुमार सोनकर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा देश की विभिन्न कंपनियों में गरीब मजदूरों का लगभग 27000 करोड़ रुपया बकाया था, जिस पर माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा सामान्य यूनिक ई.पी.एफ.ओ. नम्बर बनाकर उस पैसे को वापस करने का काम लगभग पूरा किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि देश के 1,51,000 पोस्ट ऑफिसेज में बहुत सारे साइलेंट एकाउंट्स हैं। उन साइलेंट एकाउंट्स में देश के गरीब, मजदूर और किसानों का हजारों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। किन्हीं कारणों से या तो उनके वारिसों ने उसे क्लेम नहीं किया, उनके घर के लोगों ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया या जिन लोगों ने जमा किया, वे स्वयं भूल गये। ऐसा हजारों करोड़ों रुपया साइलेंट एकाउंट्स के रूप में इस विभाग के पास पड़ा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैसा साइलेंट एकाउंट्स में पड़ा हुआ है, उसे उनके उत्तराधिकारियों को वापस करने के लिए और साथ ही साथ जिनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, ऐसे पैसे को सामाजिक कार्यों पर खर्च करने के लिए क्या सरकार विचार करेगी?

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, वैधानिक रूप से कौन वारिस है, जब तक इसका पता नहीं लगता है, तब तक वह जमा किया हुआ धन किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। यह भी सच है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसे अनेक खाते हैं, जिनके बारे में

अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है और वह पैसा हमारे विभाग में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका निवेश हम सामाजिक कार्यों में करें, इसका फैसला वित्त मंत्रालय करता है।

डॉ. उदित राज: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा लोक सभा क्षेत्र नॉर्थ वैस्ट दिल्ली है, जहां पर पोस्ट ऑफिसेज की बड़ी कमी है। एक असैम्बली कांस्टीट्यूएंसी किराड़ी है, जिसकी पोपुलेशन लगभग साढ़े चार लाख है, जहां पर कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। दूसरी जगह रोहिणी सैक्टर 25 है, मैट्रो विहार फेज-वन और फेज-टू, होलंबीकलां भी है। मैं इस मामले में पत्र भी लिख चुका हूं, कृष्ण विहार, बवाना, रोहिणी सैक्टर 23 और 24 में भी कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। कुतुबगढ़ विलेज, दिल्ली में भी नहीं है। मंगोलपुर कलां, भाग्य विहार और रानीखेड़ा इत्यादि जगहों पर भी नहीं हैं। मैं इसके बारे में काफी लिखता आ रहा हूं। रोहिणी सैक्टर 15 में तो सैंक्शन भी हो चुका है, फिर भी वहां पर अभी बिल्डिंग नहीं बन पाई है। बादली में पोस्ट ऑफिस किराये की बिल्डिंग में चल रहा है। उसकी बिल्डिंग बनायी जानी चाहिए। अन्य जगहों पर जो कम्प्यूटर ऑपरेटर्स रखे गये हैं, वे ट्रेन्ड नहीं हैं, इसलिए डिलीवरी नहीं हो पा रही है तथा ठीक से इवेंट्री भी नहीं हो पाती। प्राइवेट लोगों से डाक डिलीवरी करवायी जा रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस समस्या का समाधान करें।

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने तीन पत्र लिखे थे। एक किरारी, सुलेमनगर, नई दिल्ली के लिए था, जिसको विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। Sub post office was opened in Kirari, Sulemnagar, यह बात माननीय सदस्य के ध्यान में होगी। उनके दो और प्रस्ताव थे, उनमें से एक सैक्टर 22 रोहिणी के लिए था, जिसमें विभाग ने कोशिश की थी और वह जस्टीफाइड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने जगह खोजी थी, लेकिन वहां जगह नहीं मिल सकी। तीसरे, उन्होंने सैक्टर 21, रोहिणी, नई दिल्ली के लिए लिखा था, इसको भी विभाग ने एगजामिन किया और यह पाया कि वह जस्टीफाइड नहीं है। यह सच है कि हमारे पास डाक कर्मियों की कमी है और जो पहले हम प्लान हैड में नये पोस्ट ऑफिसेज खोलते थे, मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज करीब डेढ़ लाख से ज्यादा हमारे देश में ही हैं, लेकिन अब हमने रीडिप्लॉयमेंट करके नये डाक घर पिछले तीन वर्षों में खोले हैं। सरकार से हमने अनुरोध किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम यह कोशिश करेंगे कि यह सुविधा हम और लोगों तक पहुंचा सकें। हमने अपनी जो सेवाएं थीं, उनको भी दूसरी दिशा में डाइवर्ट किया है ताकि फाइनेंशियली हमारी स्थिति सैल्फ सफिशिएंट हो सके। यह सच है कि शहरी क्षेत्र में जो नॉर्म्स हैं, उनके आधार पर नये डाक घर खोलने में अभी कठिनाई है, लेकिन माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करके जो भी उचित कार्यवाही होगी, उसके बारे में मैं उन्हें शीघ्र सूचित करूंगा।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: Thank you Madam. I am quite happy to note that the post offices in our country are undergoing a rejuvenation process following the introduction of core banking system in post offices.

Madam, these are really revolutionary changes taking place in the post office sector. Besides this, the Government have linked post offices with many other financial and welfare activities. The very success of all these depends upon the infrastructure development of post offices such as building, ICT and connectivity issues. For example, in my constituency, there are seven post offices having its own land but we have not constructed buildings. We are paying Rs. 65,000 as rent every month. I am asking the Minister whether the Government will have any programme of action to develop the infrastructure facilities in the post offices.

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है- टैक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना और कोर बैंकिंग सेवा शीघ्रताशीघ्र शुरू हो, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं देश में चल रही हैं, उनका अधिक से अधिक सामान्य जन को लाभ मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 25493 डाक घरों में से लगभग 22688 डाक घरों में हमने काम पूरा कर लिया है। आने वाले दिनों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी हम शुरू करने जा रहे हैं। जहां तक इन सात पोस्ट ऑफिसेज का सवाल है, निजी तौर पर उनके बारे में मैं उनको विवरण उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन यह सच है कि ग्रामीण इलाकों में अब भवन नहीं हैं और नीति है कि जिसको हम डाक सेवक नियुक्त करते हैं, उसी के मकान में काम चलता है। उसको हम कुछ फिक्स्ड सैलरी भी देते हैं, लेकिन सब-पोस्ट ऑफिसेज और जो हैड-पोस्ट ऑफिसेज हैं, वहां कई स्थानों पर हमारे भवन हैं, जैसे जैसे वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, हम आने वाले दिनों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेंगे।

SHRI M. CHANDRAKASI: I would like to know from the hon. Minister the details of number of post offices – banks sanctioned and functional in Tamil Nadu and the details of such banks with ATM facilities in the State. I also request that the post office in Veppur block in my constituency be upgraded as a Taluk Post Office with all facilities.

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने लोक सभा क्षेत्र के विषय में जानना चाहा है जिसका आंकड़ा मैं उन्हें लिखित रूप से उपलब्ध करा दूंगा। उन्होंने डाक सुविधाओं के उन्नयन हेतु आग्रह किया है तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारा विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में हम कोशिश करेंगे।

(Q. 142)

श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया: अध्यक्ष महोदया, हमारा देश पूरे विश्व के अंदर युवाओं का देश है, जहां 35 वर्ष से कम आयु के लगभग 65 प्रतिशत और 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के लगभग साढ़े सत्ताईस प्रतिशत युवा हैं। पिछले दस सालों में जितने भी घोटाले हुए हैं, उनमें से एक घोटाला खेल मंत्रालय में भी हुआ। आज देश में करीब 50 फैंडरेशंस काम कर रही हैं। ये फैंडरेशंस शहरों में ज्यादा काम करती हैं और वहां सिफारिशी बच्चों को ही मौका मिलता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन फैंडरेशंस को आदेश दें कि ग्रामीण अंचलों के जो बच्चे हैं, उन्हें भी मौका मिले और उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उन्हें संवारने का काम भी फैंडरेशंस करें।

मैं इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले 15-20 साल से लोग अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। मंत्री जी ने अपने जवाब में अनियमितता की बात भी कही है। इनके चुनाव में पारदर्शिता लानी पड़ेगी, ताकि नए लोगों को भी मौका मिले। मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि युवा अवस्था में खेल के कारण बच्चों में बैक पेन, घुटनों में दर्द या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है, लेकिन उनके लिए भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे कि वे अपने बुढ़ापे के समय अपने परिवार पर बोझ न बनें।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बुढ़ापे के समय खिलाड़ी अपने परिवार पर बोझ न बनें, इसके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है?

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत-से प्रश्न एक साथ पूछे हैं। स्पोर्ट्स राज्य का विषय है। स्पोर्ट प्रमोशन करना राज्य का काम है, लेकिन स्पोर्ट्स में एक्सिलेंस करना केंद्र का काम है। यह खुशी की बात है कि स्पोर्ट्स को देश में बढ़ावा मिल रहा है और इस समय ओलम्पिक में 119 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे देश में अभी 49 फैंडरेशंस ऐसी हैं, जिन्हें हमने रिक्मनाइज किया है। ऐसी बात नहीं है कि उन पर अंकुश नहीं रखा गया है। 14 मामलों में हमने अनियमितताएं पाई हैं, हमने उनकी रिक्मिशन को भी रोका है, चाहे वह इलैक्शन के कारण है, चाहे उन्होंने हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया हो।

यह बात कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा कि सिफारिश से लोग आते हैं। मैरिट के आधार पर काफी चयन किया जाता है। सदन को जानकार खुशी होगी कि जितने खिलाड़ी हमारे ओलम्पिक्स, दूसरे कॉमन वेल्थ गेम्स आदि में जाते हैं, उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और नार्थ-ईस्ट से आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नार्थ-ईस्ट में खेलों को हमें और ज्यादा बढ़ावा देना है। इसके साथ-साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। यह बात भी सही है कि थोड़ी फंड्स की

कमी है। मैं कल राज्य सभा में उत्तर दे रहा था, तब मैंने कहा था कि जो एम.पी.जे. स्पोर्ट्स के किसी भी प्रोजेक्ट में अपना 50 परसेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए खेल मंत्रालय उतनी ही राशि मतलब 50 परसेंट ग्रांट उन्हें देगा। आपको जानकर खुशी होगी कि राज्य सभा के कई एम.पी.जे. इस बात के लिए तैयार हैं।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: महोदया, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि पचास परसेंट सांसद दें, इसके लिए मेरा निवेदन है कि सांसद पचास परसेंट दे देंगे, लेकिन इसके लिए सांसद निधि पांच करोड़ रुपए से पच्चीस करोड़ रुपए करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि अभी-अभी भारतीय कुश्ती संघ ने अपनी देख-रेख में भारतीय पहलवानों की तैयारी कराई थी। उसके बावजूद खाने में मिलावट का मामला सामने आया है। पहलवान नरसिंह यादव और एथलीट इंद्रजीत सिंह डोप टेस्ट में फेल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, क्योंकि ये बच्चे डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। इससे देश का बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा हो सकता था कि वे गोल्ड मैडल जीतकर आते या कई दूसरे मैडल जीतकर आते। इसमें भारतीय कुश्ती संघ की कहीं न कहीं लापरवाही रही है, जिसकी वजह से इन बच्चों के खाने में मिलावट का मामला आज टीवी पर दिखाया गया है।

मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि भारतीय कुश्ती संघ जिस तरह से इन दो बच्चों को ओलम्पिक में भेजने का काम कर रही थी, उसी के पैरलल दूसरे नम्बर के बच्चे जैसे परवीन राणा है, ऐसे बच्चों को भी तैयारी कराई जाती, ताकि उनके अंदर यदि डोपिंग का मामला सामने आता, तो दूसरे बच्चों को वहां भेजा जा सकता।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। इस विषय पर भाषण नहीं देना है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: माननीय मंत्री जी बताएं कि भारतीय कुश्ती संघ में जो अनियमितता पाई गई है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे?

मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि हमारे जिलों और ब्लाक्स में स्टेडियम बनने थे, पूर्व में इस बात की घोषणा की गई थी, क्या इस बारे में कोई प्रोग्रेस हुई है?

श्री विजय गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य महोदय को पहले तो यह स्पष्ट कर दूँ कि मैंने पाँच करोड़ रुपये का 50 परसेंट यानी ढाई करोड़ रुपये नहीं माँगे। आप अपनी कंस्टीट्यूएन्सी में जो प्रोजेक्ट लगाएंगे, उस प्रोजेक्ट में 50 परसेंट आप लोग क्लीयर कर दीजिए। ... (व्यवधान) श्री जौनापुरिया जी ने जो बात कही है, नाडा (नैशनल एंटी डोपिंग एजेंसी) वाडा (वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी) के अंतर्गत काम करती है।

हमारी रिपोर्ट्स तुरंत उनके पास पहुंचती हैं। जब खिलाड़ियों में ऐसा पाया जाता है, तो हम जो एंटी डोपिंग पैनल नियुक्त करते हैं, उसकी रिपोर्ट के बाद ही कोई कदम उठाया जाता है। एक खिलाड़ी के बारे में साफ हुआ है। इस संबंध में उनका सस्पेंशन प्रोवीज़नल है। फाइनल रिपोर्ट एक-दो दिन में आ जाएगी, तो वह आपके सामने आ जाएगी।

SHRIMATI MAUSAM NOOR : Madam, India, despite its demographic dividend and young population, is yet to find a space in global sports and athletics map. Sensing this critical achievement gap, the UPA Government introduced Rajiv Gandhi Khel Abhiyan in February, 2014 which replaced Panchayat Yuva Krida and Khel Abhiyan. Along with the same, two other sports projects were launched by UPA – Urban Sports Infrastructure Scheme and National Sports Talent Search Scheme. These programmes were merged and rechristened as *Khelo India*.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government has been able to identify exceptional talents from rural and tribal areas and other backward areas under *Khelo India* scheme. If yes, what progress is shown by these individuals in their chosen field of sports.

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष जी, हम लगातार टैलेंट हंटिंग का काम करते हैं। यह आज से नहीं, कई सालों से चलता है। आपने ये जो तीन योजनाएँ बनायीं, इनके अंदर स्टेट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होना होता था, जो नहीं होता था। इसलिए अब हम 'खेलो इंडिया' की स्कीम के अंतर्गत इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे टैलेंट हंटिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टेडियम हों, कॉम्प्लेक्स हों, गांव-गांव तक या दूसरी जगहों तक हमें खेलों को ले जाना है, हम उनको 'खेलो इंडिया' स्कीम में ले जा रहे हैं। उसके लिए हम कंपीटिशन लेवल को नीचे से लेकर ऊपर तक आएं, ताकि हम सही खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर सकें। इस समय हमारे 59 साई (एसएआई) ट्रेनिंग सेन्टर हैं, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस 15 हैं, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी पाँच हैं। हम अभी इंडिविजुअल डिसिप्लिन में आठ एकेडमी और बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी देंगे और टैलेंट भी ढूँढ पाएंगे।

श्री राघव लखनपाल: अध्यक्ष महोदया, पिछले दो-तीन दिनों से चिन्ता और चर्चा का विषय चल रहा है, जिसे आदरणीय सदस्य श्री जौनपुरिया जी ने भी रखा है। हमारे खिलाड़ियों पर डोपिंग का जो आरोप लग रहा है, क्या यह उनके खिलाफ एक साज़िश है या रेसलिंग फेडरेशन या खेल संगठनों के खिलाफ साज़िश है, यह जाँच का विषय है। मेरा कहना यह है कि जो ऐनाबोलिक स्टेरॉयड्स हैं, जो मार्केट में फ्रीली

एवलेबल है, जिनका दुरुपयोग खेल के मैदान में किसी न किसी स्तर पर हो रहा है। ऐसे मैन्यूफैक्चरर्स और सप्लायर्स को रोकने के लिए, क्योंकि मेरा आज का तारांकित प्रश्न संख्या 159 भी इसी से संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष : इसीलिए मैंने आपको अलाऊ किया गया है।

श्री राघव लखनपाल: उसका मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि NADA does not have any legal authority over manufacturers and suppliers. नाडा की अथॉरिटी तो शायद न हो, लेकिन सरकार की अथॉरिटी है कि वह ऐसे मैन्यूफैक्चरर्स और सप्लायर्स को चेक करे, जो इन ऐनाबोलिक स्टेरॉयड्स को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट में फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं और खिलाड़ियों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाएगी?

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदया, सदस्य महोदय ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी।

HON. SPEAKER: Shri Prasun Banerjee.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Only the question of Shri Prasun Banerjee will go on record.

Interruptions ... *

SHRI PRASUN BANERJEE: Madam, I thank you for giving me a chance to ask a question.

Madam, I am also an Olympian. I am also the first footballer to come as a Member of Parliament. So, I give thanks to all my colleagues. मैं सभी को फुटबाल में फर्स्ट आने पर बधाई देना चाहता हूँ। मैं मिनिस्टर साहब को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन्स हैं, वह सब बेकार हैं, यूज़लैस हैं।

HON. SPEAKER: Please do not say something like that.

SHRI PRASUN BANERJEE : Why are our Ministers not interfering? This Government should intervene immediately. I will tell you about our football fraternity. I was a footballer and also the Captain of my team. पहले हम लोग टॉप 90 में थे। आज हम फुटबाल में फीफा रैंकिंग में 155 पर पहुंच गए हैं। यह हालत आज फुटबाल की हो गयी है। The Football Federation is doing nothing about football. टैलन्ट की कोई सर्चिंग नहीं हो

* Not recorded.

रही है, खेलने वाले बच्चों को गांव से नहीं लाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि देश में फुटबाल बर्बाद होता जा रहा है। The Mohun Bagan Team and the East Bengal Team are our national teams. वर्ष 1911 में इन क्लब्स से हम इंग्लिश फुटबाल टीम को हरा चुके हैं। लेकिन इन टीमों को कोई सम्मान नहीं मिलता है। The football game, which is a popular game in India, is going down. इसलिए हमें फुटबाल को बचाना होगा। फेडरेशन में बैठे लोग घर पर बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। मैंने आपको इसीलिए अलाऊ किया कि आप एक खिलाड़ी हैं।

श्री प्रसून बनर्जी : मैडम, मैं मिनिस्टर साहब को यह कहना चाहता हूँ कि आप इन फेडरेशन्स के माध्यम से फुटबाल को बचाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? The Sports Minister must take responsibility. मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे देश में फेडरेशन्स क्या कर रहे हैं?

श्री विजय गायल : महोदया, माननीय सदस्य ने अच्छा किया जो फुटबाल से संबंधित प्रश्न उठाया। आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा था कि क्रिकेट के अलावा भी... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL: What about NADA's issue? ... (*Interruptions*)

SHRI VIJAY GOEL: Please address your issue to the Chair. प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि क्रिकेट के अलावा फुटबाल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो इत्यादि खेलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि अगले साल तक पूरे देश में फुटबाल का बुखार होगा। इस साल हम ब्रिक्स फुटबाल का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद वर्ष 2017 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है, जो कि छः बड़े शहरों में आयोजित होगा। अभी से हम लोगों ने तैयारी की है कि गली और कस्बों में भी अगर कोई क्लब है तो उस तक भी फुटबाल पहुंच जाए, इसको हमारी सरकार करने वाली है।

SHRI C.K. SANGMA: Madam, I read the answer of the hon. Minister saying that the guidelines are not very specific. The guidelines are only to certain areas of election and monitoring. It is important that the Government should intervene and should put guidelines on the way they will function. As the Member had earlier said, there should be more involvement of rural areas and States. That is my first point.

Secondly, the Government has put up a very good scheme where it is saying that it is going to put 50 per cent for districts and all these areas. My first

point is that 50 per cent is not enough. I think we need to put more. My request to the hon. Minister and also the hon. Prime Minister who is here is that they should give more funds for this. Also, instead of having bigger stadiums in big cities, I think we should have small, small stadiums in all areas. I would request the Minister to look into that aspect as well.

श्री विजय गोयल : आपका सुझाव अच्छा है और इसमें राज्य सरकारों को भी अपने बजट बढ़ाने होंगे। अकेले गुजरात में पांच सौ करोड़ का स्पोर्ट्स के लिए बजट है...(व्यवधान) आप लोग सुनते नहीं हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप आंसर दीजिए।

श्री विजय गोयल : इसी तरह से हम राज्य सरकारों और कारपोरेट सेक्टर के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हमने एसोचैम और फिक्की के प्रतिनिधियों से भी बात की है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फण्ड नेशनल स्पोर्ट्स फण्ड में ला सकें। जितना भी फण्ड हमें कोई कारपोरेट देता है, उसकी मैचिंग ग्रांट हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलती है। हमारा काम यही है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलें।

SHRI K.C. VENUGOPAL: What has happened to Narsingh Yadav's issue? ...
(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इस संबंध में दो प्रश्न हो चुके हैं। आप इस पर चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं।

(Q. 143)

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam, I thank you very much for allowing me an opportunity to ask a question about the AMRUT Scheme. Our hon. Prime Minister has declared the AMRUT Scheme in the month of June 2015. Under this, 500 cities are going to be benefited and developed and Rs.50,000 crore will be spent on AMRUT Scheme. It was the declaration. The Scheme is very nice. Money is also there. But the implementation part is very poor. My question, through you, is this. How many States have submitted the State Annual Action Plan under AMRUT? What is the real expenditure? Is there any mechanism to monitor this important project, if not, whether the Government is ready to constitute an Expert Joint Committee to monitor this Scheme for speedy implementation?

RAO INDERJIT SINGH: Madam, there seems to be some misconception. Rs.5,000 crore is not the amount that has been earmarked for AMRUT. Over five years, in Mission Mode, the Government of India will spend Rs.50,000 crore and not Rs.5,000 crore. The Mission was launched only in July last year. Already, the Annual Action Plans of all States and Union Territories, where this Mission is applicable, have already been approved by the Ministry of Urban Development. For the next year, which is the current year, fifty per cent of the States have already had their Annual Action Plans submitted to the Government of India. Out of that, fifty per cent of the amount that has been undertaken under the Annual Action Plan has already been earmarked for these States that have submitted their Annual Action Plans. I think, within this time period of one year, a great achievement has been made under Mission Mode conceived by the Prime Minister wherein the Annual Action Plans of all the States for the year 2015-16 have already been approved. Hereafter, if there are any deformities or dysfunctions, they will be addressed as time comes along.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam, my second question is this. Kannur Corporation in my constituency is also included under the AMRUT

Scheme. The Kannur Cantonment area is not included under the Scheme, even though it comes under the Defence. The Kannur Cantonment is the only cantonment near the Arabian Sea which is the headquarters of Defence Security Corps and Territorial Army. The population is below 5000. Most of the civilians are poorest of the poor. Most of them are Anglo-Indians. I would like to know whether the Government and the hon. Minister is ready to include the small part of that Kannur city under the AMRUT Scheme.

RAO INDERJIT SINGH: Madam, there is a clearly defined criteria by which these 500 cities have been selected. The civil areas of cantonments are part and parcel of the cities that have been selected if their population is one lakh and above.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam, this is in the middle of the city.

RAO INDERJIT SINGH: The civil area has to be part and parcel of a city whose population is over one lakh. The other criterion is that the capital towns of all States have been included. The third criteria is that the HRIDAY cities where there is heritage involved, have been selected and also towns on the main stems of rivers with a population of 75,000 but less than one lakh have also been selected. Apart from that, there are other criteria as well. Cantonments if they fall within the criteria that have been laid down by the Government of India will be part and parcel of this Mission. If the criteria do not apply, then they will not be. On the issue of the city that Madam has asked for, I will let her know separately whether her city falls within the criteria or not.

श्री ओम बिरला: अध्यक्ष महोदया, अमृत योजना के माध्यम से पहली बार सरकार ने 500 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की योजना बनाई है। निश्चित रूप से 10 लाख से कम आबादी वाले और 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शहरों का विकास होगा। मंत्री महोदय, हमने यह फैसला किया था कि हम इन शहरों के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी शहरों का विकास करेंगे। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने शहरों में हमने पब्लिक प्राइवेट

पार्टनरशिप के माध्यम से विकास की योजना बनाई है और कितने लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विकास में भागीदारी निभाई है? कई छोटी नगरपालिकाओं के अंदर जब राज्य सरकार 2/3 का 1/3 हिस्सा देंगी तो कई नगर पालिकाएं, नगर निगम या लोकल बॉडीज़ आर्थिक रूप से कमज़ोर हालात में रहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और देश में पहली बार किसी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की योजना बनाई है। राज्य सरकारों के साथ प्रयास कर के राज्य और केंद्र सरकार मिल कर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसके विकास की योजना बनाएं तो उचित रहेगा।

राव इंद्रजीत सिंह : मैडम, अमृत मिशन के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का प्रयास नहीं होता है, बल्कि जो बल दिया जा रहा है, वह सीवरेज के ऊपर दिया जा रहा है। वॉटर सप्लाई सिस्टम्स को ऑगमेंट करने के लिए बल दिया जा रहा है, सीवरेज़ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया जा रहा है। रीहैबिलिटेशन ऑफ ओल्ड वॉटर सप्लाई सिस्टम्स ठीक हो जाएं, उनके ऊपर दिया जा रहा है। जो वॉटर बॉडीज़ ड्राई हो गई हैं, खत्म हो गई हैं और जो ड्रिंकिंग वॉटर सप्लाई के अंदर आज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनके ऊपर दिया जा रहा है। जब कोई राज्य अपना एन्युअल एक्शन प्लान भारत सरकार को और शहरी विकास मंत्रालय को देता है, तो उसको हम एप्रूव कर देते हैं। एप्रूव करने के बाद वह राज्य अपने तरीके से, जो निर्धारित माध्यम है कि कितना राज्य का खर्चा होगा, कितना केंद्र का खर्चा होगा, जो कि 50% से ले कर और 90% केंद्र द्वारा अनेक स्थानों पर दिया जाता है तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक पैसा उन राज्यों को वितरित कर दिया जाता है। जो बकाया 50% है, वह राज्यों को अपने माध्यम से खुद-ब-खुद खर्चना पड़ता है। इसके अंदर 20% राज्यों का खुद का पैसा होना चाहिए और उसके अलावा जो 30% बचता है, उसके अंदर पीपीपी मोड से भी वह धन इकट्ठा कर सकता है या फॉरन फंडिंग एजेंसीज़ के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा कर सकता है। हरेक प्रांत के अंदर अनेक जगहों पर फॉरन फंडिंग से या पीपीपी मोड से काम चल रहे हैं। इसकी लिस्ट बहुत लंबी-चौड़ी है, इनके विषय के अंदर जो है, वह मैं अलग से बता दूंगा।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं यहां से बोलना चाहूंगा।

महोदया, भारत की ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है, लेकिन अध्ययन किया जा रहा है कि आने वाले समय में आधी आबादी शहरों में आ जाएगी। लगभग 50 करोड़ लोग शहरों और नगरों में आ जाएंगे। आज शहरों और नगरों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, चाहे स्मार्ट सिटी योजना हो या अमृत योजना हो। लेकिन देखा जा रहा है कि ये सारी स्कीम्स उन्हीं नगरों और शहरों में जा रही हैं, जो कि पहले से ही विकसित हैं। उन्हीं राज्यों के पास जा रही हैं, जिनके पास पहले से ही ज्यादा रेवन्यू है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले ही प्रश्न में आदरणीय मंत्री विजय गोयल जी ने

कहा कि प्रधान मंत्री कहते हैं कि उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों में ज्यादा महत्व देना चाहिए। लेकिन उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों को इस अमृत स्कीम के द्वारा सिर्फ 12 नगर मिले हैं। अगर उसी की तुलना में आप गुजरात राज्य को देखें तो 31 नगर गुजरात को मिले हैं।

मैडम, हम चाहते हैं कि उत्तर-पूर्वांचल को इस स्कीम के द्वारा कैसे और ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। उत्तर-पूर्वांचल के क्राइटेरिया को देख कर हर राज्य को क्या दस-दस नगर दिए जा सकते हैं? नहीं तो वही होगा कि जो वैस्टर्न स्टेट्स हैं, जो ऑलरेडी ज्यादा विकसित हैं, उनको ही ज्यादा नगर इन योजनाओं के लिए दिए जाएंगे।

राव इंद्रजीत सिंह : महोदया, वर्ष 2011 के सेन्सस के मुताबिक देश की 31 फीसदी आबादी शहरों के अन्दर रहती है, जो तकरीबन 4,041 शहर और कस्बे वर्ष 2011 सेन्सस के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं। आने वाले समय के अन्दर वर्ष 2050 तक अनुमान यह है कि देश की 60 फीसदी आबादी शहरों के अन्दर रहने लग जाएगी, गाँवों से माइग्रेट करके शहरों के अन्दर आ जाएगी। जिन शहरों पर आज के दिन बोझ बढ़ता जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है, लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की पानी की सुविधा को, सीवरेज को पूरे तौर से स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक तो हमारा यह अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटीज का मिशन है, अनेक और मिशन भारत सरकार ने, नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने चालू किए हैं। मेरा यह कहना है कि हमें आने वाले समय के अन्दर शहरों के अन्दर ज्यादा बल देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की आबादी रोजाना बढ़ती जा रही है। यह सिर्फ हमारे देश की ही बात नहीं है, यह ग्लोबल फिनोमिना है, जहाँ पर भी देश आगे बढ़ा है, विकसित हुआ है, वहाँ पर लोग माइग्रेट करके शहरों के अन्दर आ गए हैं। हमारे यहाँ पर भी आने लग रहे हैं। जहाँ तक इनका प्रश्न मूल रूप से अपने खुद के नॉर्थ-ईस्ट एरिया का था, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार में पूरे तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि उनको औरों की बनिस्बत ज्यादा महत्व दिया जाए।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not interrupt like that.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। मंत्री जी, आप अपनी बात पूरी करें।

...(व्यवधान)

राव इंद्रजीत सिंह : अमृत की स्कीम के तहत 50:50 के अनुपात में धन अनेक प्रान्तों को दिया जाता है यानी कि 50 परसेंट देश की सरकार का और 50 परसेंट प्रान्त की सरकार का होता है। जहाँ तक नॉर्थ-

ईस्ट का सवाल है, वहाँ 90 फीसदी धन हमारी भारत सरकार देती है और केवल 10 फीसदी उनको देना पड़ता है।..(ब्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)... *

SHRI SHIVKUMAR UDASI: First of all, I would congratulate the hon. Prime Minister for starting this ambitious project of developing 500 cities in the country and making improvement in the infrastructure facilities. My question is this. ... (Interruptions)

In Annexure-II, the hon. Minister has given an answer regarding the fund-sharing pattern under AMRUT. For cities/towns with a population up to ten lakh, the Centre and the State are sharing 50 per cent each. But in Karnataka, when it comes to the 50 per cent share of the Government of Karnataka, they are saying that 30 per cent would be borne by the urban local bodies and 20 per cent by the State Governments. It will be very unfortunate to say this. The urban local bodies are not being financially strengthened. They do not have that much of money. I would like to know whether the Government has given any mandatory direction to them that 50 per cent should be given by the State Government. The Government of Madhya Pradesh is funding 40 per cent from the State Government and ten per cent from the urban local bodies. My question to the hon. Minister is whether they are giving any mandatory instructions to the State Government so that the urban local bodies are not strained. Otherwise, they should also allow municipal bonds and the funds could also be taken from other financial institutions on long-term basis.

RAO INDERJIT SINGH: Madam, the direction that has been issued to the States is that they must themselves contribute at least 20 per cent of the 50 per cent that has been allocated to their share. Fifty per cent is given by the Government of India; 50 per cent will have to be given by the urban local bodies and the State

* Not recorded.

Governments whose share is defined and mandated to be at least 20 per cent. If the urban local bodies do not have funds, they are free to enter into public-private partnership. They are also free, as was earlier answered on the Question previous to this one, to get foreign funding as well. The Government of India cannot give directions on how a State should make up its 50 per cent share. We have approved our Annual Action Plan. We are funding 50 per cent. Thereafter, the States must contribute their 50 per cent for the Mission to be successful.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Madam, this Scheme is very well-intentioned but it has two flaws which I would like to bring to the hon. Minister's attention. Firstly, he refers to 31 per cent urbanization as per the 2011 Census but there are many studies which show that if we follow the Chinese norms and other norms which are common world-wide, we have about 50-55 per cent urbanization already. There is one flaw in this. If you simply go by the population criteria, the cities and the towns which already exist are getting these funds. The reality is that States like Bihar and Odisha which have much more population in rural areas with small towns are getting excluded from this.

I urge the hon. Minister to reconsider the norms so that some of these towns where a lot of urbanization is happening will get considered in this scheme.

RAO INDERJIT SINGH: Madam, this 31 per cent that I mentioned was according to the 2011 census, which was five years ago. The rate of urbanization is quite dramatic and I may not be able to substantiate how much it is because we do not really have the figures but I think there is a substantial increase in the population of towns and cities.

What I wish to answer the hon. Member is that we are looking at first strengthening those cities which have a large population. Thereafter we will go down to the smaller ones. In the first mode, up to 2020, 500 of these cities have been taken up. But the *Swachh Bharat Mission*, which has an all encompassing

view, has taken up all 4,041 cities which have been urbanized even though they may not have urban local body. So, I think this is a process which needs to be continuously monitored and we will consider his suggestions as sympathetically as possible.

(Q.144)

KUMARI SUSHMITA DEV: Madam, Speaker, the answer of the hon. Minister is clear that when it comes to telecom tariffs or the price of mobile data, all these matters are under the purview of TRAI, being regulated by TRAI, and it is not necessary that the Ministry interferes in it. That is the nature of the answer.

I would like to point out that Section 11 of the TRAI 1997 Act says that TRAI can recommend licensing terms, tariffs etc. to the Government of India.

We always remember our late Prime Minister Rajiv Ji when we talk of IT revolution and the idea was to make it inclusive and affordable to all, especially the marginalized class. But this Question specifically is addressing about the price of what we commonly call the data packs and its validity period to make it more affordable.

My specific question to the hon. Minister is that whereas TRAI plays a role of recommending to the Government of India, but it is the Government of India which actually decides on the terms and conditions of licensing. So, can the Government of India think of inserting a clause or a condition in the terms and conditions that for the marginalized class and remote areas like the North-Eastern States a certain tariff, a certain criteria must be followed to show some leeway to them?

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने जो बात कही है, यह सच है कि यह ट्राई के परव्यू की बात है। अभी हाल ही में 5 जुलाई को ट्राई ने इस विषय पर विचार किया है और टैलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट (10) अपनी वेबसाइट पर डाला है और लोगों की राय ले रहे हैं। इस पर 2 अगस्त तक लोगों की राय मांगी गई है। सामान्यतया राय आने के बाद तीन-चार हफ्ते में ट्राई निर्णय करती है। मंत्रालय भी ट्राई के संपर्क में है। जो बात माननीय सदस्या ने उठाई है कि 90 दिन का जो वैलिडिटी पीरियड है, उसे बढ़ाकर 365 दिन किया जाए, ताकि कंज्यूमर को राहत पहुंच सके और लाभ मिल सके, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से माननीय सदस्या की भावना का भी ख्याल रखा जाएगा और कंज्यूमर के हितों का संरक्षण निश्चित रूप से किया जाएगा।

KUMARI SUSHMITA DEV: Madam, the hon. Minister has talked about 10th amendment which is regarding a draft policy and it is in the public domain. But I believe that the functioning of the TRAI and the powers of the TRAI have been called into serious question in the light of recent judgement of May 2016 with regard to call drops. In the month of October 2015, the TRAI had passed a regulation to impose a fine or a penalty on telecom companies for call drops up to Rs.1 to a maximum of three call drops in a day. But that has been struck down by the Supreme Court saying that the TRAI does not have the power to impose penalties. यह सही है कि देश के जो यूज़र्स हैं, उनके साथ कंसल्ट करके आप 10th Amendment लाएंगे, पर मेरा सरकार से प्रश्न है कि अगर आप ट्राई को पेनाल्टी का, फाइन करने का पावर नहीं देंगे, तो फिर इस अमेंडमेंट और इन कंसल्टेशन पॉलिसीज का कितना फायदा कंज्यूमर्स को हो पाएगा, इसके बारे में मुझे संदेह है।

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदया, डिसइंसेंटिव का क्लॉज़ पहले से टेलीफोनी के लिए है और यह डेटा में भी हो, यह माननीय सदस्या का मूल कंसर्न है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन, यह निश्चित रूप से टी.आर.ए.आई. (ट्राई) का अधिकार क्षेत्र है और ट्राई उस पर विचार कर रही है। मंत्रालय और ट्राई सदैव इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

कुमारी सुष्मिता देव: ट्राई की पावर्स बढ़ाइए। एक्ट को अमेंड कीजिए।

श्री मनोज सिन्हा : अगर उसकी जरूरत होगी तो हम जरूर बढ़ाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। इस देश में टेलीकॉम सेक्टर की एक सक्सेसफुल स्टोरी रही है, जिस पर कुछ काले धब्बे पिछले दिनों में लगे हैं। लेकिन, जिस कॉल ड्रॉप की बात कही गयी है, उसके बारे में मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उस काले धब्बे को हमारी सरकार मिटाएगी। दो दिन पूर्व ही हमने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बुलाया था और जो वैधानिक अधिकार सरकार के पास है, उसके अंतर्गत उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं। मैं सदन को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं, वह प्रेस में भी आया है। उन्हें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले एक वर्ष में करना है और एक लाख से ज्यादा बी.टी.एस. लगाने हैं। पिछले 45 दिनों की जो प्रगति है, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि जो लक्ष्य उन्हें दिया गया था, उसको उन्होंने पूरा किया है और भविष्य में भी उन्हें पूरा करना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि जब कंज्यूमर सैटिसफाई होगा, तभी हम मानेंगे कि वास्तव में सरकार काम कर रही है और विभाग ठीक काम कर रहा है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, आज देश की असली शक्ति सूचना और प्रौद्योगिकी के आधार पर है। इस सरकार ने स्वयं कहा है - 'हर हाथ को हुनर।' मेरे सहभागी का जो प्रश्न है कि वर्तमान में जो कॉल ड्रॉप की सिचुएशन है, उसमें हम कहीं भी जाते हैं तो दस सेकन्ड के अन्दर कॉल ड्रॉप हो जाती है। फिर लोगों को सूचना कैसे मिलेगी? आज देश में सूचना सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बारे में सरकार ने आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है और न ही कार्य किया है।

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: हम मंत्री से यह जानना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी ही इस विभाग का प्रभार संभाला है, कि ये सदन को आश्वस्त करें कि यह कॉल ड्रॉप की स्थिति, जो पूरे देश में उत्पन्न हो चुकी है, उसका निराकरण ये कब तक कर पाएंगे?

इसी के साथ डेटा का मामला जुड़ा हुआ है क्योंकि डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है। आई.आई.टी., दिल्ली ने एक स्टडी की थी। आई.आई.टी., दिल्ली की स्टडी के आधार पर झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में बताया गया है कि नेटवर्क की क्षमता कई क्षेत्रों में केवल 35% तक है और 2G और 3G में फ्रीक्वेंट स्विचिंग होती है। जहां तक बैंडविड्थ की बात है तो वह बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान में, जहां ऑपरेटर्स ने कहा है कि उनकी क्षमता 100% है, उसके बारे में आई.आई.टी., दिल्ली की स्टडी ने कहा है कि वहां वास्तव में केवल 60% क्षमता है। मध्य प्रदेश में, जहां ऑपरेटर्स ने कहा है कि उनकी क्षमता 99% है, वहां इस स्टडी के अनुसार वह केवल 35% से 60% तक है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो डिस्कैपेंसीज निकली हैं, इसके विरुद्ध आपका मंत्रालय और टी.आर.ए.आई. क्या कदम उठाएंगे, इससे सदन और देश की जनता को आश्वस्त कराएं।

ऑपरेटर्स के बारे में जो विज्ञापन दिए जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि 14 से 16 एम.बी.पी.एस. की कनेक्टिविटी है, जो वास्तव में नहीं मिलती है तो उन विज्ञापनों के विरुद्ध भी क्या कदम यह मंत्रालय और यह सरकार उठाना चाहती है, इससे सदन को आश्वस्त कराएं।

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, ट्राई ने पहले से ही डेटा को लेकर एक ऐप जारी किया हुआ है। एंड्रॉयड और आईफोन आपरेटिंग सिस्टम, दोनों पर कोई भी कंज्यूमर चाहे तो डेटा स्पीड क्या है, उसकी सूचना उसे मिल सकती है। यह सच है कि कठिनाइयां हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन को बताया है। आई.आई.टी., दिल्ली ने जो अध्ययन किया है, उसका संज्ञान विभाग ने भी लिया है और ट्राई ने भी लिया है। हम उनसे निरंतर सम्पर्क में हैं। जैसा मैंने पहले ही उन्हें आश्वस्त किया कि अभी दो दिन पूर्व ही जितने टेलीकॉम आपरेटर्स हैं, उनकी बैठक हमने बुलाई है और उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं।

मैं सदन को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग जिम्मेदारी से इस काम को देख रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है कि इसमें आने वाले तीन-चार महीने में गुणात्मक सुधार सदन के सदस्यों को भी महसूस होगा।

श्रीमती रीती पाठक: अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न बहुत सामान्य सा है, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता और सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बहुत आवश्यक प्रश्न है। विगत कुछ वर्षों से इंटरनेट पैक, काल रेट्स और टॉप अप की वैल्यू में निरन्तर वृद्धि हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसके नियन्त्रण के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है, अगर बनाई है तो क्या बनाई है और अगर नहीं बनाई है तो क्यों नहीं बनाई है?

श्री मनोज सिन्हा : जहां तक मूल्य निर्धारण का प्रश्न है तो वह पैक पर लिखा रहता है और वे सूचना ट्राई को देते रहते हैं। अगर जरूरत होगी तो सरकार भी उसमें दखल देगी और उपभोक्ता के साथ अन्याय न हो, इसकी चिंता विभाग पूरी तरह करेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्रकांत खैरे : उपस्थित नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण।

(Q. 145)

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण: महोदया, मंत्री जी ने उत्तर के 'ख' और 'ग' में लिखा है कि भारतीय महिलाओं को झांसा देकर धोखे से उनसे शादी कराने के दोषारोपण पर अनिवासी भारतीयों की गिरफ्तारी के संबंध में आंकड़े मंत्रालय के पास नहीं हैं। गोपनीयता के आधार पर विदेशी सरकारें ऐसी जानकारी भारतीय मिशनों या मंत्रालयों के साथ साझा नहीं करतीं। भारत में की गई गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में जानकारी मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। यदि ऐसा है, तो भारतीय महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि आज तक जिन महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, उनमें ज्यादातर किस कम्युनिटी की हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, आप सहित पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि विदेशों में संकट में फंसे भारतीयों की मदद करना इस सरकार की उच्च प्राथमिकता बन गया है। एन.आर.आई. शादियों के विवाद भी इसी श्रेणी में आते हैं। मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि यह समस्या जितनी गंभीर है, उतनी विकट भी है। इस तरह के विवादों को सुलझाने में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने अपने लिखित वक्तव्य में उन तमाम बाधाओं का जिक्र किया है। जो 'ख' भाग की बात सांसद महोदय कर रहे थे, वह सच है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह आती है कि दूसरे देशों में जो लॉज ऑफ प्राइवैसी है, उसके अनुसार वे हमारे साथ सूचना साझा नहीं करते। उससे भी बड़ी समस्या है कि विदेशी कोर्ट्स कौटुम्बिक परम्परा को उस तरह नहीं समझते हैं, जैसे भारत में समझते हैं। वहां अगर एक्स पार्टी डिक्री भी डाइवोर्स के लिए दे दी जाए, तो वे इसे कोई बहुत बड़ा संगीन अपराध नहीं मानते और इसलिए वे तुरन्त तलाक दे देते हैं। अगर भारत में वह केस डालें तो सम्मन की तामील होने में यह दिक्कत आती है कि जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे खिलाफ सम्मन आया है, तो वह पता बदल लेता है, तो सम्मन की तामील नहीं हो पाती है। इसीलिए मैंने इन दोनों चीजों के बारे में यह लिखा था कि हम लोगों को ये दिक्कतें आती हैं। बाकी यह पूछना कि वे किस कम्युनिटी की हैं, यह आंकड़ा तो मेरे पास ही नहीं सकता। कम्युनिटी से इसमें क्या ज्यादा फर्क पड़ जाता है? जब मैं कहती हूँ कि मैं विदेश में फंसे हुए व्यक्ति की मदद करती हूँ, तो जाति, भाषा, प्रान्त, कम्युनिटी, ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। वह मेरे लिए शुद्ध भारतीय होता है और वह महिला शुद्ध भारतीय होती है। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि सांसद इससे क्या हासिल करेंगे, अगर उनके पास यह आंकड़ा आ जाए कि वे किस कम्युनिटी की हैं।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : अध्यक्ष महोदया, एन.आर.आई. झूठी शान एवं झूठे बयानों से भारतीय महिलाओं से शादी कर लेते हैं और दहेज के नाम पर लड़की वालों से काफी धन भी लेते हैं। शादी करने के बाद पत्नी का वीजा विदेश में बनवाने का लालच देकर विदेश लौट जाते हैं।

12.00 hours

उसके बाद नहीं लौटते और अगर लौटते हैं तो दूसरी शादी करके लौटते हैं। वे इसी तरह करते हैं। इस तरह एनआरआई द्वारा भारतीय महिलाओं के साथ शादी करके धोखे हो रहे हैं। अगर महिलाएं विदेश भी पहुंच जाती हैं तो पति द्वारा पहले रखी हुई पत्नी के बारे में पता चलता है। विदेश में उस महिला पर कई अत्याचार किए जाते हैं। अत्याचार होने पर भारतीय महिलाओं को राहत देने के लिए 13 देशों के साथ भारत ने संधि कर रखी है। इस प्रकार के मामलों को देखने के लिए एक पार्लियामेंट्री फोरम गठित किया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आज तक इस फोरम के माध्यम से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, हमने एक पोर्टल बनाया है। उसे 21 फरवरी, 2015 को शुरू किया है और उसका नाम ही 'मदद' रखा है। मैंने लिखित वक्तव्य में भी कहा है कि उसमें हमारे पास 246 शिकायतें आईं, जिनमें से हमने 172 का समाधान कर दिया। पोर्टल के अलावा डाक और ई मेल से हमारे पास 362 शिकायतें आईं जिनमें से हमने 344 का समाधान कर दिया। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि केवल विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग, इनकी भी एनआरआई मैरेजिस में चीजों का समाधान करना प्राथमिकता बन गई है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई है जिसमें विदेश मंत्रालय के दो अधिकारी हैं, उनका अपना एक अधिकारी है। हमने उन्हें यह कहा है कि इसमें आप एक राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधि और एक लॉ एंड जस्टिस का प्रतिनिधि भी रख लें। वे इकट्ठे बैठकर इन चीजों को भी देख रहे हैं कि अभी प्रावधानों में कहां कठिनाइयां हैं और कहां ढिलाई देने की जरूरत है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पांच सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और चार सदस्यीय सब कमेटी बनाई है। उनकी भी सिफारिशों का हम इंतजार कर रहे हैं। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगी कि राज्य सभा की पिटीशन कमेटी के पास भी एक याचिका आई है जिसकी सुनवाई वे लोग कर रहे हैं। हम उनकी सिफारिशों का भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर जिस तरह समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं, हमें नियमों में जो भी ढील देनी होगी, परिवर्तन करना होगा, वह करके हम इसका प्रभावी समाधान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री दीपेंद्र हुड्डा, जय प्रकाश नारायण यादव, पी. करुणाकरन, प्रो. सौगत राय, प्रो. के.वी. थॉमस, राजेश रंजन, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, राजीव सातव, के.एच. मुनियप्पा, तारिक अनवर और कोडिकुन्नील सुरेश से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं परन्तु इनके लिए सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों पर उठाए जा सकते हैं।

इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.03 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now Papers to be Laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): On behalf of Shri M. Venkaiah Naidu, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O.1544(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th April, 2016, appointing the 1st day of May, 2016 as the date on which the provisions, mentioned therein, of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 shall come into force under sub-section (3) of Section 1 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 4942/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.
 - (ii) Annual Report of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4943/16/16]

- (3) A copy of Notification No. S.O.1265(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st March, 2016, continuing to assign the additional charge of the post of Claims Commissioner for Delhi Metro Rail Corporation Limited to Shri Satish Chandra, General Manager (Legal), DMRC for a further period upto 3rd July, 2016 or until further orders, whichever is earlier, for the purpose of adjudicating upon claims for compensation in respect of accidents involving the death of, or bodily injury to person, or damage to any property arising out of the working of the Delhi Metro issued under Section 48 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 4944/16/16]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24की उप-धारा (4) के अधीन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 673 (अ) जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं,की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4945/16/16]

- (2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :-
- (एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 21 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2016, जो 21 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन नियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 29 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन नियम, 2016, जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 7 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (ज्येष्ठता सूची का विनियमन) संशोधन नियम, 2016, जो 10 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4946/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): महोदया, मैं श्री मनोज सिन्हा की तरफ से भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2016 जो 28 मई, 2016 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4947/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy of the 26th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the Recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, June, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4948/16/16]

12.04 hours**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'
BILLS AND RESOLUTIONS****24th Report**

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to present the Twenty-fourth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.04 ½ hours**MOTION RE: 33rd REPORT OF BUSINESS
ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): I beg to move:

“That this House do agree with the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26th July, 2016.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Thirty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 26th July, 2016.”

The motion was adopted.

12.05 hours**SUBMISSION BY MEMBER****Re: Dope Testing in Sports**

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): अध्यक्ष जी, कल से सारे टीवी चैनलों में कुश्ती फेडरेशन और नरसिंह यादव जी के बारे में चर्चा हो रही है, देश को उम्मीद थी कि वह रियो आलंपिक में मेडल लेकर आएंगे, हम लोग गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे। जिस तरह से उनको डोपिंग में फंसाया गया या उन्होंने खुद लिया, यह सब हम नहीं जानते लेकिन जिस तरह से यह खबर आ रही है कि अब प्रवीण राणा जी का नाम चला गया है। कुश्ती के एक इंटरनेशनल प्लेयर के नाम को हटाकर इनके नाम का सजेशन दिया गया था और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे थे। आज एक तरफ नाडा का फैसला आना है और दूसरी तरफ यह क्लीयर हो गया कि प्रवीण राणा जाएंगे। एक खिलाड़ी कई सालों तक मेहनत करके ओलंपिक का सपना देखता है अब उसको फिर से चार साल बाद चांस मिलेगा। यह एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद लॉन टेनिस की प्लेयर रही हूं। लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। प्लेयर डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज जिस तरह का भ्रष्टाचार दिख रहा है उससे दो बातें सामने आ रही हैं या उसने खुद ली या किसी ने दी। यह दिखाया जा रहा है कि इसमें एक इंटरनेशनल प्लेयर के भाई का हाथ है, रसोइया उसको पहचान भी रहा है, उसके फुड में काला मिलाया गया। मैं चाहती हूं कि सरकार इसकी सीबीआई से जांच कराए, अगर इस तरह की हरकत करके किसी प्लेयर को आलंपिक जाने से रोका गया तो यह जघन्य अपराध है, उसको सख्त सजा होनी चाहिए। यह पूरे देश के साथ और प्लेयर के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज जिस तरह से बॉक्सिंग फेडरेशन और कुश्ती फेडरेशन में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है, मैरी कॉम मुवी भी बनी थी वह भी एक सच्चाई है। आज बहुत जरूरी है कि सरकार उन प्लेयर की तरफ ध्यान दे जो देश का झंडा ऊंचा करने के लिए इतना मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस तरह का धक्का लगता है कि वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वह कुछ भी करने के लिए आतुर हो जाते हैं। मैं फिर से सीबीआई जांच के लिए आग्रह करती हूं और जिसने भी इस जघन्य अपराध को किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिले।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री राजेश श्री पी.के.बिजू, श्री पी.करुणाकरन, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. संजय जायसवाल को श्रीमती रंजीता रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सत्यपाल सिंह

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विद्युत वरन महतो

...(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, आज सुबह ही प्रश्नकाल में यह विषय आया था और उसका जवाब दिया गया है किंतु जो सवाल अभी माननीय सदस्य ने उठाया है इससे मैं सरकार को अवगत कराऊंगा और एक स्टेटमेंट देने के लिए कहूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विद्युत वरन महतो

...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, कल हमने मंत्री जी को बताया है, वह स्टेटमेंट देंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एकदम तुरंत नहीं होता है, उन्होंने बोला न, आपने सुना नहीं होगा।

...

...(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत की आवोहवा वायु प्रदूषण के कारण इसके दूरगामी परिणाम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। घटते वन सम्पदा और बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण, आज देश की आवो हवा पर व्यापक असर डाल रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से लिए गए आंकड़ों के अनुसार ग्रीन पीस का दावा है कि बीते सदी में पहली बार चीन की तुलना में भारत की आवोहवा ज्यादा खराब हुई है। ग्रीनपीस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बीस सबसे प्रदूषित शहरों में तेरह शहर भारत के ही हैं।

अध्यक्ष महोदया, प्रदूषण का सीधा असर मानव जीवन, पशु, पक्षी और वनस्पति पर पड़ता है। भारत में आवोहवा की शुद्धता नापने के लिए फिलहाल केवल 39 निगरानी स्टेशन हैं, जबकि चीन में इनकी संख्या 1,500 है। वायु प्रदूषण के कारण गड्ढों और कुओं में जहरीली गैस बनती है। प्रदूषित जहरीली गैस के कण इन स्थानों पर जमे रहते हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में लोग प्रदूषित जहरीली गैस का शिकार हो रहे हैं। वैसे तो अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में मलपुर जन्तू गांव पड़ता है। वहां दिनांक 24 जुलाई, 2016 को ग्राम बिलारी की कुइया में प्रदूषित गैस के अधिक होने के कारण तीन मौतें हो गईं। उस कुइया में जो नीचे जाता गया, उसकी मृत्यु होती गई।

महोदया, आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि भारतीय आबोहवा को सही करने के लिए यथाशीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं और इस हेतु नए-नए निगरानी स्टेशन बनाए जाएं। निगरानी प्रणाली और दीर्घकालिक नीतियों पर काम कर के मनुष्य के साथ-साथ पशु-पक्षियों और पौधों को बचाया जा सकता है। मेरी आपके माध्यम से एक और प्रार्थना है कि ग्राम बिलारी की कुइया में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता यथाशीघ्र प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को शीघ्र निर्देशित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : मैं सर्वश्री भैरोंप्रसाद मिश्र, अजय मिश्रा टेनी, सुधीर गुप्ता, रोड़मल नागर, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. मनोज राजोरिया, को माननीय सदस्य, श्री सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान करती हूँ।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, झारखंड प्रदेश एक अकूत खनिज सम्पदा का भंडार है। मैं आपके माध्यम से सदन में सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचना चाहता हूँ। जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जादूगड़ा नरवा यूसीएल, जहां न्यूक्लियर पॉवर प्लांट स्थापित करने के लिए मैंने पूर्व में भी आपके माध्यम से इसी सदन में अनुरोध किया था। उस क्षेत्र का गत 18 फरवरी, 2016 को भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. शेखर बसु ने भ्रमण किया। उन्होंने जादूगड़ा नरवा के आसपास यूरेनियम का विपुल स्रोत पाया। यह यूरेनियम केवल झारखंड और आंध्र प्रदेश में ही मिलता है। 1,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 160 टन यूरेनियम की जरूरत होती है, जबकि देश में 500 से 900 टन यूरेनियम का उत्पादन होता है। एएमडी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि वहां इतनी पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है, जिससे 1,000 साल तक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के जादूगड़ा और नरवा के आसपास जितनी यूरेनियम की मात्रा पाई गई है, उसे देखते हुए श्री शेखर बसु ने यह कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करादे, तो वहां न्यूक्लियर पॉवर प्लांट की स्थापना की जा सकती है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वहां न्यूक्लियर पॉवर प्लांट की स्थापना की जाए।

माननीय अध्यक्ष : मैं सर्वश्री भैरोंप्रसाद मिश्र, कंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, सुधीर गुप्ता, सी.पी. जोशी, रोड़मल नागर को माननीय सदस्य, श्री विद्युत वरन महतो द्वारा सदन में प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान करती हूँ।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आज सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करना चाहता हूँ और वह यह है कि कश्मीर पर पाकिस्तान चारों तरफ से हमले कर रहा है, फिर चाहे वह इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, वहाँ के युवाओं को बरगलाने का सवाल हो, आतंकवाद हो और चाहे घुसपैठ का सवाल हो। उसी तरह से आर्थिक तौर पर कश्मीर कैसे कमजोर होगा, इसकी भी वह व्यवस्था कर रहा है।

महोदया, एक तुलबुल नेवीगेशन प्रोजेक्ट है। उसी प्रोजेक्ट को पाकिस्तान वूलर बराज प्रोजेक्ट कहता है। वर्ष 1960 में जब हमने पाकिस्तान के साथ नदी जल समझौता किया, तो उसमें हमने चार पाइंट दिए कि हम ये-ये काम कर सकते हैं। यदि आपको ध्यान हो, श्रीनगर में अभी जो बाढ़ आई, उसके पीछे भी इस तुलबुल नेवीगेशन प्रोजेक्ट का पूरा होना नहीं है। तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी के ईस्ट और वेस्ट तट पर है। वूलर का मतलब होता है, वॉल। झेलम नदी जब श्रीनगर से जाती है, तो वह वूलर लेक में जाती है और वहाँ से वह सोपोर और बारामूला जिले में जाती है। इस कारण भारत सरकार ने वर्ष 1984-85 में इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और वर्ष 1987 में इसका टेंडर हो गया और टेंडर होने के बाद यह काम शुरू हुआ।

अध्यक्ष महोदया, यदि आप इस पूरे के पूरे एरिये को देखेंगी, जिसमें श्रीनगर, सोपोर और बारामूला हैं, तो इन्हें आप सेब के बागान के तौर पर पाएंगी। यदि इस एरिये का नेवीगेशन सिस्टम बढ़िया होगा, तो इस एरिये में सेब का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। जब वहाँ सेब का उत्पादन ज्यादा होगा, तो वहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण वे आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं या देशद्रोह का रास्ता अपनाते हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे नेवीगेशन के कारण सेब के उत्पादन की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और नेवीगेशन कास्ट भी बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान को जब यह समझ में आ गया कि तुलबुल नेवीगेशन प्रोजेक्ट होने से कश्मीर के लोगों में प्रासपेरिटी आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा विकास का रास्ता अपनाया जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया।

महोदया, वूलर लेक की स्थिति ऐसी है कि यह डल लेक से बहुत बड़ी है। आप समझिए कि डल लेक उसका दसवां हिस्सा भी नहीं है। इससे डल लेक में टूरिस्ट का फ्लो बहुत हो जाएगा, सेब का नेवीगेशन ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1987 यानी 30 साल से लगातार भारत सरकार पाकिस्तान के साथ नेगोसिएट कर रही है लेकिन अभी तक नेगोसिएशन कहीं नहीं पहुंचा।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने डैम बना दिया। नथपा-झाकड़ी के कारण बाढ़ आ गई, चीन को भारत सरकार नहीं रोक पाई। भारत सरकार पाकिस्तान के रोकने

से न रुके और तुलबुल नेवीगेशन प्रोजेक्ट हो हर हालत में जल्दी से जल्दी पूरा करे जिससे वहां के युवाओं को रोजगार मिल जाए और लोग मुख्यधारा में आ पाएं।

माननीय अध्यक्ष: श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, डॉ. मनोज राजोरिया, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सी.पी. जोशी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री भैरो प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री निशिकान्त दूबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

12.16 hours**LOKPAL AND LOKAYUKTAS (AMENDMENT) BILL, 2016***

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Madam Speaker, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.”

The motion was adopted.

DR. JITENDRA SINGH: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 27.07.2016

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Madam Speaker, I thank you very much for permitting to raise a matter of urgent public important pertaining to the State of Assam.

The preparation of National Register of Citizens (NRC) is in progress in Assam. It is a very commendable work. Here, I would like to bring to the notice of the Government of India, through you, that the minorities, especially Muslims are being harassed in the name of preparation of NRC on flimsy reasons. Our party, AIDUF demands that no Bangladeshi should stay in Assam. But genuine citizens should not be harassed.

Secondly, I would like to bring another important factor to the notice of this august House that overnight, devastating floods have totally destroyed the houses in Assam. In such a situation, people would rush to save their children and other family members rather than saving documents. So they are without documents now. But officers do not give them copies and these are genuine citizens of Assam are labeled as foreigners.

So, I would like to request the Government, through you, that these people should not be harassed while preparing the National Register of Citizens. This is our express demand.

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam Speaker, I want to associate with him.

HON. SPEAKER: You can associate.

कुमारी सुष्मिता देव, श्री राधेश्याम बिश्वास, श्री मोहम्मद सलीम, श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री एम.बी. राजेश और श्री पी.के. बिजू को श्री सिराजुद्दीन अजमल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनूप मिश्रा (मुरैना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मध्य प्रदेश की तरफ और विशेष कर टूरिज्म की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नीति आयोग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। मेरा अपना क्षेत्र बीहड़ों का क्षेत्र है, चम्बल, कुंवारी, आसन नदियों के किनारे

का क्षेत्र है। इसके बारे में सब जगह एक अलग तरह की चर्चा होती है। यह क्षेत्र महाभारतकालीन राजा भोज की राजधानी कुन्तलपुर रहा, यहां कुन्ती का निवास स्थान था। यहां हरीसिद्धी देवी का मंदिर है। आठवीं और दसवीं सदी में मितावली, पडावली, सिहोनिया में विभिन्न प्रकार के मंदिर और भवन थे। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इनके संरक्षण का काम नहीं कर रहा है। इन सब स्थानों को टूरिज्म के मेन सर्किट से जोड़ने का काम होना चाहिए। काकनमठ खजुराहो के ही पैटर्न पर बना हुआ है, लेकिन यहां आवागमन की व्यवस्था नहीं है। मैंने सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से रोड बनाने का निवेदन किया है। जब तक यह सेंट्रल सर्किट से नहीं जुड़ेगा तक तक यहां टूरिस्ट नहीं आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हम लोक सभा के सदन में बैठे हैं। सर लुटियन जब मितावली में मंदिर देखने गये, तो उन्होंने लोक सभा का पूरा डिजाइन उसी योगिनी मंदिर के अनुसार किया। दूसरी खासियत यह है कि यहां जो पत्थर उपयोग में लाया गया, वह भी मुरैना, ग्वालियर का ही सैंड स्टोन है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मितावली, पडावली, सिहोनिया, काकनमठ के साथ-साथ पहाड़गढ़ में भीमबेटका वर्ल्ड हैरिटेज है, तो महाभारत कालीन गुफाएं और उन पर चित्रकारी पहाड़गढ़ के पास लिखिछज में हैं। मेरा निवेदन है कि इसे मेन टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाये। इसके साथ-साथ वहां पर लोगों को रोजगार और उस स्थान की महत्ता को बढ़ाने का काम तेज गति से हो, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सी.पी.जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोडमल नागर, श्री शरद त्रिपाठी, डॉ. मनोज राजोरिया और डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री अनूप मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you Madam Speaker. The State Bank of Travancore is the backbone of Kerala's economy. It is known as Kerala's own bank with 850 branches across the State. It has a deposit of more than Rs. 1 lakh crore and an advance of Rs. 67,000 crore. Its CD ratio is 67 per cent while that of State Bank of India it is only less than 55 per cent. It has given more than 60 per cent of Education Loan in the State. It tops the list of priority sector lending in the State also.

It is evident from these statistics that the State Bank of India has a crucial role as far as the Kerala's economy is concerned. It caters to the needs of small

business, small and marginal farmers, traders and students. This shows the importance of State Bank of India. The decision to merge the State Bank of Travancore with the State Bank of India will have serious implications on the Kerala's economy. Now, the entire process of merger itself is not transparent. A provision of more than Rs. 1,170 crore have been made for the merger and now there is an attempt to create an impression that the State Bank of Travancore is in debt which is not proper.

Therefore, the Kerala Assembly has adopted a near unanimous Resolution against the merger of State Bank of Travancore with the State Bank of India.

Hence, I would like to urge upon the Union Government to respect the sentiments of the people of Kerala and the unanimous Resolution adopted by the Kerala Assembly and withdraw the decision to merge the State Bank of Travancore with the State Bank of India.

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shri P. Karunakaran, Shri K.C. Venugopal, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, Shri Mullappally Ramchandran, Shri M.K. Raghavan, Shri M.I. Shanavas, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Jose K. Mani, Shri N.K. Premachandran, Shri Md. Badaruddoza Khan and Shri Sankar Prasad Datta are permitted to associate with the issue raised by Shri M.B. Rajesh.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदया, हरिद्वार पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब लिखित में एसोसिएट कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: अध्यक्ष महोदया, उत्तराखंड धरती का स्वर्ग है। पूरी दुनिया से लोग उसके दर्शन और विश्व धरोहर गंगा के स्पर्श और स्नान के लिए आते हैं। मेरा निवेदन है कि मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून, हरिद्वार से ऋषिकेश और रूडकी से देहरादून के राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत खराब स्थिति में हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग आधे-अधूरे बने हुए हैं, जिसके कारण काफी एक्सीडेंट होते हैं। इन राजमार्गों में काफी गड़दे पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तीन-चार बार मीटिंग करके उन राजमार्गों पर युद्ध स्तर पर काम कराने की कोशिश की, अब तो कुंभ का मेला भी चला गया, लेकिन वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि हरिद्वार में आठ-आठ घंटे जाम लगता है। पूरे विश्व से वहां लोग आते हैं, इसलिए मोनो रेल होनी चाहिए या यहां से वहां तक एक ओवरब्रिज बनना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा यह भी अनुरोध है कि मोतीचूर तक ओवरब्रिज बने। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशंक जी, शून्य काल में इतना लंबा-चौड़ा नहीं बोला जाता।

...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, मुझे मालूम है।

...(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : वहां आठ-आठ घंटे जाम लगा रहता है। वहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसलिए वहां मोनो रेल या ओवरब्रिज बनाया जाये।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सी.पी. जोशी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री रोडमल नागर और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री शरद त्रिपाठी को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजू शेटी (हातकणंगले) : अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। किसानों ने भी इस योजना का काफी अच्छा साथ दिया है। पिछले तीन-चार सालों से महाराष्ट्र में गंभीर सूखे की परिस्थिति है। इस साल भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान था कि महाराष्ट्र में मानसून देर से आयेगा, तो वह सही निकला। महाराष्ट्र में मानसून देरी से आने की वजह से, वहां किसान अभी तक खरीफ की बुवाई कर रहे हैं, लेकिन फसल बीमा योजना में प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। महाराष्ट्र में, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा में जो किसान अकाल से जूझ रहे थे, वहां बैंकों ने किसानों के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करने का निर्णय लिया और यह काम अभी भी जारी होने की वजह से किसान 30 जुलाई तक प्रीमियम जमा नहीं कर सकते हैं।

इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी विनती है कि 30 जुलाई तक मोहलत को 15 अगस्त तक बढ़ाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री धनंजय महाडीक, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजू शेटी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शून्य काल में उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ।

गुजरात राज्य में मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाइवे संख्या आठ पर सूरत जिले की सावा क्रॉसिंग, धामदोड़ क्रॉसिंग और नन्दाऊ क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज या अंडरपास नहीं होने की वजह से बहुत सी जानलेवा अकस्मात् दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ये तीनों स्पॉट डिपार्टमेंट द्वारा ब्लैक स्पॉट भी घोषित किए गए हैं। इसलिए जानलेवा अकस्मात् दुर्घटनाएं रोकने हेतु एवं लोगों की सुविधा हेतु जल्द से जल्द इन तीनों क्रॉसिंग्स पर फ्लाईओवर ब्रिज या अंडरपास बनाने के लिए, मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : अध्यक्ष महोदया, आज हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि देश में अगर कहीं भी कोई अनुचित घटना घटती है, तो उसका परिणाम मेरे संसदीय क्षेत्र में दिखाई देता है। चाहे वह घटना जातीय हो, अत्याचार संबंधी हो, उसके लिए बन्द, मोर्चा, पत्थरबाजी, झगड़ा, गांव बन्द आदि मेरे क्षेत्र में होता है। अगर उधर कोई एक व्यक्ति एक्सपायर हुआ हो तो यहां दस आदमी मारे जाते हैं। इसके ऊपर देश और सदन को सोचने की आवश्यकता है। बन्द होने से लोगों को असुविधा होती है, पथराव होने से लोगों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए मेरी विनती है कि इसके बारे में एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाकर विचार किया जाए। ठीक है, अगर किसी पर अन्याय हुआ हो तो उसके लिए शांतिपूर्वक मोर्चा या आमरण उपवास आदि करें। आज अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो पांच मिनट में मीडिया की वजह से उस घटना की जानकारी पूरे देश में पहुंच जाती है। अलग-अलग पार्टी वाले देखते हैं कि अगर अपना फायदा हो तो उसके लिए बन्द आयोजित करते हैं। इसके बारे में कुछ अच्छा और सख्त कानून लागू करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोडमल नागर, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री सुधीर गुप्ता को प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Madam Speaker, I would like to draw the attention of the Ministry of HRD, Government of India through this august House that Kendriya Vidyalaya was established in Khammam district during the year 2007. The following problems are being faced by the students and I would request them to solve the problems immediately.

Out of 45 teachers in the Kendriya Vidyalaya, as per the staffing pattern, only five regular teachers are working after transfer of 15 regular teachers during this academic year. Therefore, the quality of education in the Kendriya Vidyalaya is badly affected due to the inadequate strength of teaching staff.

The other important problem is this. It is not known whether the reimbursement of expenditure towards uniform, cost of transportation and books was made to the students admitted under RTE Act. If the expenditure is reimbursed and the funds are available in the Vidyalaya, there will be a lot of help for the Vidyalaya for regular maintenance of the school.

I therefore urge upon the Government to take necessary action for recruitment of regular teaching staff and also release of sufficient funds for providing the basic amenities to the students as per the Right to Education Act, 2009. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Sharad Tripathi is permitted to associate with the issue raised by Shri P. Srinivasa Reddy.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र चुरू, जो राजस्थान में बहुत सूखा जिला है, जिसमें 80 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। उस 80 प्रतिशत आबादी में भी 75 प्रतिशत से अधिक लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं। पिछले साल भी बारिश के समय मूंगफली की फसल, जो सुजानगढ़, बीदासर क्षेत्र में होती है, उसमें सफेद लट्ट का प्रकोप हुआ था। उस वक्त मैंने यहां कृषि मंत्री जी से मिलकर, वहां पर कुछ वैज्ञानिकों को ले जाकर पूरी स्थिति उनको दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई रिलैक्सेशन

नहीं मिली। इस बार अब फिर बरसात हुई है, लोगों ने खेती की और दुबारा सफेद लट्ट मुंगफली पर लगी है। मुंग की बहुत बड़ी फसल है, इस बार हमने दाल को इम्पोर्ट से क्लब करने के लिए काफी प्रमोट भी किया। मुंगफली की फसल में इस बार रेडहेड कैटरपिलर, जिसे हम गांवों में कातरा बोलते हैं, की जबर्दस्त मार पड़ी है। आपके माध्यम से कृषि मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वैज्ञानिकों की एक टीम भेजकर वहां सर्वे कराया जाए और उनको सब्सिडाइज्ड रेट्स पर पेस्टीसाइड्स दिलवाए जाएं, जिससे किसानों का भला हो सके।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री अर्जुन लाल मीणा, श्री हरीश मीना, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री रामचरण बोहरा को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में किसानों की जो 70 प्रतिशत आबादी है, जिन्हें अन्नदाता भी हम कहते हैं तथा जिनके संबंध में मैं सवाल उठाना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे आपके संरक्षण की भी जरूरत है। औद्योगिक क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र को भी विशेष ज़ोन बनाने की आवश्यकता है, जहां कृषि एवं उत्पाद संबंधी सम व्यवहार की ही अनुमति हो तथा किसानों को अपने कृषि उत्पाद का विक्रय मूल स्वयं तय करने का अधिकार हो। आज के किसान आत्महत्या एवं कई अन्य भीषण समस्याओं से बुरी तरह से प्रभावित हैं। इन किसानों को स्थायी रूप से इन प्राकृतिक प्रकोपों से निजात दिलाने की आवश्यकता है। किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण इत्यादि अन्तरिम उपाय हैं। इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

कृषि एक असंगठित क्षेत्र है। यद्यपि कृषि पर 70 प्रतिशत से अधिक आबादी की निर्भरता है, लेकिन इसको संस्थागत रूप देते हुए, जमीनी स्तर पर, लघु एवं सीमान्त किसानों के साथ साथ, वास्तविक किसानों की पहचान कर, उन्हें कृषि उत्पाद के विक्रय मूल्य को तय करने का अधिकार दिया जाए। इससे देश में कृषि उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा तथा कृषि के क्षेत्र में देश की प्रधानता कायम रहेगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि देश हित में, कृषि को औद्योगिक क्षेत्र की तरह विशेष ज़ोन बनाया जाए जहां किसानों को अपने कृषि उत्पादों का विक्रय मूल्य स्वयं तय करने का अधिकार हो। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Chandra Prakash Joshi, Shri Rodmal Nagar, Shri Sudheer Gupta, Shri Devendra Singh Bhole, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Chhedi Paswan.

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): This is a very important issue. It has been two years since Telangana got separated from Andhra Pradesh. Yet the court remains the same for both the States though it should have been bifurcated immediately as per section 31 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act.

Recently, 906 Judicial Officers of undivided Andhra Pradesh have been distributed among the two new States. As per the provisional list of allotment of subordinate judicial officers issued in the first week of May, 366 judicial officers were allotted to Telangana and 540 to Andhra Pradesh.

Of these, 142 Judicial Officers were appointed recently to Telangana, though their district of origin as mentioned in the application form is Andhra Pradesh. The Registrar General of the Hyderabad High Court failed to follow the 40:60 allocation guidelines between Telangana and Andhra Pradesh. The Department of Personnel and Training (DoPT) should have issued allocation guidelines for Judicial Officers and the Union Law Minister should have appointed a Committee as per 80(2) of the Andhra Pradesh Reorganisation Act instead of arbitrarily posting people from Andhra Pradesh in the Telangana Judiciary.

Accordingly, 94 Judges should have been allotted to Telangana and 140 to Andhra Pradesh. However, the High Court gave only 84 District Judges to Andhra Pradesh and left 46 vacancies, while appointing 102 District Judges instead of 94 to Telangana. Of these 102 Judges, 72 Judges are from Andhra Pradesh and the remaining 30 are from the State of Telangana.

So, in this regard, I urge the Central Government to look into this matter and give Telangana a separate High Court for proper judicial functioning.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष जी, कल एक घटना सारे सदन के ध्यान में आई है। एक बस ड्राइवर कान में ईयरफोन लगाकर स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा था और रेलवे क्रॉसिंग पर उसके कारण 8 बच्चों की मौत हो गई। मुझे लगता है कि सरकार और सदन को आगाह करने के लिए यह घटना पर्याप्त है। कल मैं टी.वी. पर भी देख रहा था। दुनिया में जितने भी देश हैं, उन्होंने भी कहा कि स्मार्ट फोन

के कारण जो एक्सीडेंट रेट है, वह 62 प्रतिशत से ऊपर है। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि सारा सदन भी इस बात से सहमत होगा कि जब भी हम इस संबंध में कानून बनाएं तो उसमें इस बात को सुनिश्चित करें कि जो ड्राईवर चाहे वह कमर्शियल हो, चाहे प्राइवेट हो, अगर वह हाईवेज पर चलता है, या खासकर बच्चों को लेकर जाता है तो ड्राइविंग के समय ईयरफोन का इस्तेमाल न करें, उन पर सख्ती के साथ यह प्रतिबंध होना चाहिए। यह राज्य का विषय है लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो सरकार को सख्ती के साथ कानून बनाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आप बिलकुल सही कह रहे हैं।

डॉ. मनोज राजोरिया, श्री सी.पी. जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री बोध सिंह भगत को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदया, देश में सरकारों बैंकों के साथ कई प्राइवेट बैंक भी काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने बड़ी संख्या में प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिए, जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटेक महिन्द्रा, एक्सिस बैंक, यस बैंक आदि। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जैसे जन-धन योजना, जो इकोनोमिक इन्क्लूज़न की योजनाएं हैं, मुद्रा योजना आदि दूसरी योजनाएं हैं, इनसे इन बैंकों का कोई सरोकार नहीं है और न ही ये बैंक राजभागा अधिनियम का पालन करती हैं। ये बैंक सौ प्रतिशत अंग्रेजी में काम करती हैं। इनकी बहुत सारी छुपी हुई शर्तें भी होती हैं। वास्तव में ये बैंक सूदखोरों का संगठित उपक्रम हैं। हमारा प्रयास है कि गरीब लोग मुख्य धारा में आएँ लेकिन इन बैंकों के कारण इस काम में बाधा आ रही है। इन बैंकों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन्हें लागू करें और ग्रामीण इलाकों में भी अपनी अधिकतम शाखाएं खोलें या फिर इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि देश का विकास तेजी से हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री सी.पी. जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और डॉ. मनोज राजोरिया को प्रो. चिंतामणि मालवीय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Madam, I thank you for the opportunity given to me to speak on an important subject.

The nation has just heaved a sigh of relief provided by above normal monsoon rainfall all this year across the country. For the present there is no threat

of drought or famine even in vulnerable pockets like southern districts of Maharashtra, Rayalaseema in Andhra Pradesh and Vidarbha in Marathwada region which are prone to suffer by natural calamities.

Tamil Nadu has long been subjected to vagaries relating to denial of its share in river waters as a lower riparian State. Tamil Nadu has been waging a running struggle with its neighbours, Karnataka and Kerala, over sharing of river waters. Even with the provocative stance by both Karnataka and Kerala over release of waters from Cauvery and Mullai Periyar, Tamil Nadu is consistently known to have exercised utmost restraint in securing legitimate share of river waters as borne out by the fact that the hon. Supreme Court had passed orders upholding the rights of Tamil Nadu over its share of river waters as a lower riparian State.

In the backdrop, the Government of Tamil Nadu under the astute stewardship of Puratchi Thalaivi Amma, feels that the mega inter-linking of river projects should be revived. Tamil Nadu had good neighbourly relations with Telangana and Andhra Pradesh and with their active support an attempt could be made by the Centre to take up the project in phases.

HON. SPEAKER: Please conclude.

SHRI M. UDHAYAKUMAR : I will conclude in a minute.

To start with, a Southern Regional River Grid could be taken up to link up Mahanadi-Godavari-Krishna and Pennar river and diversion of surplus water of the west flowing Pamba and Achankovil rivers to Vaippar in Tamil Nadu.

On behalf of the Government of Tamil Nadu and our hon. Chief Minister, I urge the Centre to consider this proposal in the right earnest.

HON. SPEAKER: Shrimati V. Sathyabama is permitted to associate with the issue raised by Shri M. Udhayakumar.

Now Shri C. Mahendran.

How many pages do you have? Is it one page or two pages? You people bring in writing. Do not read everything.

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Hon. Speaker Madam, in my Pollachi parliamentary constituency, broad gauge conversion work has been going on for more than a year from Pollachi to Podanur. I request the hon. Railway Minister through this august House that the ongoing gauge conversion work should be completed at the earliest.

I also request that the electrification work to be carried out from Pollachi to Podanur. This will enable the railway authorities to extend all the trains operating from Pollachi to Chennai.

I further request the hon. Railway Minister to introduce a new train by naming 'Amma Express' from Pollachi to Chennai and another train by naming 'Anaimalai Express' from Pollachi to Bengaluru.

Hence, I urge the hon. Minister of Railways to complete the broad gauge conversion work along with electrification work from Pollachi to Podanur and also take necessary action to operate all the trains to Chennai from Pollachi.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार हरेक जिले में अपने कर्मचारियों के लिए ईएसआई हॉस्पिटल बनवाती है। मेरे कोल्हापुर जिले में भी वर्ष 1997 में एक ईएसआई हॉस्पिटल बनाया गया था। उस वक्त इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। नौ एकड़ भूमि में यह हन्ड्रेड बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने 50 बेड का परमिशन दिया हुआ है। इस हॉस्पिटल में 120 कर्मचारी अप्वाइंट किये गये हैं। इससे करीब 1210 कंपनियाँ और शॉप्स जुड़े हुए हैं। लगभग 17000 कर्मचारी इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। इनकी सैलरी से पचास लाख रुपये का कंट्रीब्यूशन हर साल जमा होता है। फिर भी, आज 18 वर्षों के बाद भी यह हॉस्पिटल बंद है। इसकी वजह यह बतायी जाती है कि इसके बिल्डिंग का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, वह नहीं हुआ है। इसे बनाने वाली भी सरकार है, परमिशन देने वाली भी सरकार है, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों है? यदि आज हम इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन करेंगे, तो लगभग सौ करोड़ रुपये के ऊपर यह है। पिछले सत्र में भी मैंने यह सवाल उठाया था। इससे संबंधित जो कमेटी है, आदरणीय सांसद श्री खैरे जी इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी दो बार इसकी मीटिंग ली है। उन्होंने भी बहुत कोशिश की है। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी यह हॉस्पिटल क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है? इस पर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाकर इसे कर्मचारियों के लिए खोलना चाहिए।

यदि आप देखेंगे तो 17 हजार कर्मचारी अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जा रहा है। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रेडी है, उसी में इलाज होना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity. I am grateful to you.

Madam, I want to raise an important point. The Tea Board of India has been set up under the Tea Act to act as an intermediary between the Ministry of Commerce and the tea industry. It would collect cess from the industry and distribute the same as subsidies to tea gardens. It would also promote Indian tea overseas with office in European Union Headquarters in Brussels.

The headquarters of Tea Board was in Kolkata. Recently, in the name of decentralization, Tea Board headquarters is being denuded of all powers. A large number of employees have been transferred to all over India. Recently, 11 Group D staff were transferred to Delhi, which is against all norms.

It seems that there is a conspiracy to shift the head office of the Tea Board from Kolkata to some place in Assam.

माननीय अध्यक्ष : इसमें कांसपिरेसी नहीं है।

PROF. SAUGATA ROY : Twenty-nine Tea Board employees were transferred from Kolkata to Assam recently. The ruling party in its manifesto for Assam election had promised shifting of the head office of Tea Board. Such a move will be opposed by the people and Government of West Bengal.

Before the West Bengal elections, the Commerce Minister had announced that seven tea gardens of Duncan Group would be taken over by the Tea Board.

माननीय अध्यक्ष : आपकी यह बात प्रश्नोत्तर काल में हो गयी है।

PROF. SAUGATA ROY: Nothing has happened in the matter while workers are starving. I urge upon the Central Government to take immediate steps in the matters.

Thank you. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, nothing else.

Shri Rajeev Satav.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

Interruptions ... *

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

जब से भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है।

HON. SPEAKER: Please, no personal allegations.

श्री राजीव सातव: उनके नेताओं के द्वारा गैर-जिम्मेदाराना वर्तन की चर्चा रही है। इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र का एक मामला सामने आया है। पिछले आठ दिनों से मीडिया में यह मामला चल रहा है। जो जानकारी सामने आयी है, जो ऑडियो मीडिया में चल रहा है, उसके मुताबिक एक दलित परिवार पर भारत सरकार की एक मंत्री दबाव डाल रही है और धमका रही है कि अगर आप न्यायालय में लड़ोगे, अगर मामला वापस नहीं लगे, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर भारत सरकार की मंत्री इस प्रकार की धमकी देगी, तो यह बहुत ही चिन्ता का मामला है। उसमें माननीय मंत्री यह भी कहती हैं कि दलित परिवार को गांव छोड़ना पड़ेगा और उस पर हमले होते रहेंगे अन्यथा वह प्रकरण को न्यायालय से वापस ले। यदि मंत्री इस प्रकार की बात करेंगे, यह एक गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि न ही सरकार की तरफ से इसका खंडन आया है और न ही मंत्री की तरफ से इसका खंडन आया है और पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास जो कम्प्लेंट की है, उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

इसलिए सरकार से मेरा यह सवाल है कि आपकी चुप्पी साधने की जो आदत है, वह आदत कब छूटेगी और कब इसके बारे में सरकार की तरफ से और मंत्री की तरफ से स्पष्टीकरण आएगा?

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र में दो-तीन प्रमुख नदियां हैं, जिनमें राप्ती और नारायणी है। दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कटाव हो रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ पहाड़ी नाले हमारे क्षेत्र में हैं, जिनमें रोहिन, चंदन, झरई और महाव है। मैं इस विषय को पहले भी यहां उठा चुका हूँ। आज इनकी वजह से सैकड़ों गांव पानी से घिर चुके हैं। लोगों का आना-जाना बंद हो गया है। हजारों हेक्टेयर में फसलों का नुकसान हो गया है और गांवों में पशुओं के चारे की समस्या खड़ी हो गयी

* Not recorded.

है। हालांकि यह विषय प्रदेश का है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ पानी में डूबे एरियाज़ के लोगों को बचाने की व्यवस्था की जाए, उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाए। जितने मकान बाढ़ के कारण गिर गए हैं, उनका सर्वे कराकर उनको पुनः बनाने का कार्य किया जाए और लोगों की हर तरह से मदद की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरो प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री शरद त्रिपाठी को श्री पंकज चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI PRAKASH B. HUKKERI (CHIKKODI): Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity to raise a very important issue about construction of bridges in my parliamentary constituency.

Heavy rains in the northern region of the State have submerged many roads and bridges, disrupting the normal life in my parliamentary constituency, Chikkodi in Belagavi District. As many as 13 low-lying bridges and roads have been submerged due to swelling of Krishna and Doodhganga Rivers in Chikkodi, Raibag and Athani Taluks of the District.

Therefore, there is an immediate need to construct five bridges on some important State Highways and MDR's connecting Karnataka State with Maharashtra to put an end to this recurring problem.

The important bridges to be constructed are:-

1. Construction of Bridge across Krishna River at Kallol – Yadur Village;
2. Construction of Bridge on Bhoj – Karadga – Rendal road across Doodhganga River at Km. 1.75 near Karadga;
3. Construction of Bridge across Krishna River between Jungle (Athani Taluk) and Khadrapura (Shirol Taluk), Maharashtra State (MDR);
4. Construction of Bridge across Krishna River at Alagawadi Chinchali *via* Marob (MDR); and

5. Construction of Bridge on Mangasuli – Laxmeshwar SH 73 across Markandeya River.

Construction of these bridges is very significant for vehicular and public movement in the affected region.

Therefore, I urge upon the hon. Minister of Road Transport and Highways to consider my request on priority and grant approval for construction of all bridges without any further delay. Thank you.

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदया, देश के आधे से अधिक भू-भाग में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण लगभग हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लाखों गरीब बेघर-बार हो गए, कई गांवों में आवागमन का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है और कई जगहों के बड़े पुल-पुलिया बह गए हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में 6,7 और 8 जुलाई, 2016 को आयी बाढ़ से ऐसी भयावह स्थिति बनी कि कई गांवों का सम्पर्क टूट गया, सतना शहर में बाढ़ आ गयी और राहत शिविरों में लोगों को ले जाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। हजारों लोग कई दिनों तक राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए। बड़ी संख्या में लोगों के मकान गिर गए हैं और कई गांवों में किसानों को बुआई का नुकसान हुआ है। जिले में 1173 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 14845 मकान गिर गए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 102 रिलीफ कैम्प खोले गए थे। प्रदेश सरकार ने लोगों के बचाव और राहत के लिए 93 करोड़ रुपये दिए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाढ़ से बचाव के लिए एनडीआरएफ की एक टीम हमने सतना बुलायी थी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उन सुझावों के आधार पर हमारी सहायता करे और एक टीम भेजकर उसका अध्ययन करवाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. मनोज राजोरिया और श्री शरद त्रिपाठी को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मेरे लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावा की समस्या पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

यह क्षेत्र जनपद हरदोई की बिलग्राम तहसील के सड़ियापुर गांव से जनपद उन्नाव की बांगरमऊ तहसील के गहरिपुरवा गांव तक है, जिसकी लम्बाई लगभग 25 किलोमीटर है। यहाँ दैवीय आपदा जैसी बाढ़ की समस्या हर वर्ष आती है और यह मुद्दा मैंने वर्ष 2014 में भी उठाया था, क्योंकि बाढ़ और आंधी-तूफान

पर हमारा बस नहीं है, लेकिन उस पर बांध बनाने का मैटर मैंने पहले भी उठाया था। इस बार भी पूरे के पूरे स्कूल बह गए। जहां कभी घर या मकान थे, आज वहां पानी ही पानी है, कुछ दिखायी नहीं दे रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जनहित में बाढ़ की समस्या से निबटने के लिए गंगा नदी के किनारे तटबंध का निर्माण अविलम्ब कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती अंजू बाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र धौरहरा के विधान सभा हरगांव और धौरहरा शारदा नदी में आयी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लखीमपुर से बहराइच और चटलाटी घाट तक दोनों तरफ तटबंध का निर्माण न होने से और घाघरा नदी में ईशानगर से हसनपुर कटौली तक दोनों तरफ तटबंध का निर्माण न होने से समस्या हो रही है। महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कृपा करके इस पर शीघ्र ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Madam, I am really grateful to you for giving me a chance to speak on this occasion. It is a grim situation throughout the country, but I would like to apprise that Arunachal Pradesh is now under the heavy flood especially in the areas of East Siang, Lower Dibang Valley, Lohit, Namsai and Changlang. There are two Rivers – Noa Dehing and Dibang – which have entered into the villages of Namsai and Madepur and especially five villages have been completely destroyed.

I would urge the hon. Minister for Home Affairs and also the Finance Minister in this regard. We are a non-revenue earning State. You must really help us and we depend on you.

SHRI C.K. SANGMA (TURA): Madam, I am also part of the flood affected group. My constituency has also been hit badly and especially the areas of Phulbari, Rajabala, Haripur, Shilkata, Singimari have been hit very badly.

I only have two points to make. I think, the whole of Assam and Meghalaya has been hit. Yesterday, a lot of MPs from North-East had met the hon. Home Minister. If a delegation could go headed by the Home Minister to survey that area, it would be of great help.

The second point that I have is that if we can think of proactive measures rather than reactive measures, I think it would help in future because Assam, the North-East and the Garo Hills areas have always been affected by floods.

I just want to make one last point. My constituency faced the entire brunt because once the water comes out, it lands up in my constituency in the lower part. There is a project called Rongai Valley Project. I would urge the Minister of Water Resources to take up that Project in right earnest. If this is not done, as you were mentioning earlier, maybe we might not have pineapple in future that you like so much from Meghalaya State.

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री आर.पी.सरमा, श्री कामाख्या प्रसाद तासा एवं श्री रामेश्वर तेली को श्री सी.के.संगमा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदया, पिछले दो सालों में असम में जितनी बाढ़ नहीं आई, वह इस साल आ रही है। सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इस साल इतनी बारिश हो रही है कि हम अभी तक बाढ़ का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। हम बाढ़ के एंड पर नहीं हैं, बल्कि अभी बीच में हैं, अभी एक और महीना बाढ़ का आने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर अगले हफ्ते एक कॉलिंग अटेंशन दीजिए। हम सरकार की तरफ से इस पर राय चाहते हैं, सरकार हमें तुरंत सहायता दे। असम में जिस प्रकार से इस बार बाढ़ आ रही है, काजीरंगा में पशु भी सुरक्षित नहीं हैं।

इसलिए हमारी मांग है कि आप इस विषय पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का समय दीजिए, ताकि हम इस मामले पर सरकार की तरफ से राय ले पायें।

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए आपको नोटिस देना होगा। दीपेन्द्र जी, आपका कौन सा मामला है?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों, खास तौर पर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संदर्भ में मैं एक मामला सदन में उठाना चाहूंगा। दिल्ली में तीन नगर निगम हैं - पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। इन निगमों में तकरीबन डेढ़ लाख सफाई कर्मचारी, ए.एन.एम.नर्स और ग्रुप सी. और डी. के कर्मचारी कार्यरत हैं। मेरे

लोक सभा क्षेत्र तथा हरियाणा राज्य के कुछ लोग भी यहां कार्यरत हैं। वे लम्बे समय से बारी-बारी से अपनी समस्याओं के लिए दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। इस बारे में हड़तालें भी हुई हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, हम सबको दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, हजारों करोड़ रुपये का सैस इकट्ठा करती है और दूसरी तरफ स्वच्छ भारत के सैस से एकत्र इतने हजारों करोड़ रुपये में से दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एक रुपये का भी प्रावधान नहीं किया गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इन कर्मचारियों को बैकडेट से पक्का किया जाए, दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। मेरा निवेदन है कि सरकार उपरोक्त समस्याओं पर तुरंत ध्यान दे। ... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपने विषय को बदलकर आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कोसी नदी में बाढ़ की स्थिति काफी भयानक हो चुकी है। नेपाल के माओवादियों ने धमकी दी है कि वे बांध को उड़ा देंगे। जब नेपाल में पानी बढ़ता है तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। बिहार में सुपौल और नौहट्टा के इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गये हैं।

मेरा आपसे आग्रह है कि वहां एनडीआरएफ की एक टीम और भारत सरकार के मंत्री जाएं। वहां के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया केन्द्र सरकार की ओर से वहां के लोगों को राहत देने की उचित व्यवस्था तुरंत की जाए। धन्यवाद।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, अंडमान और निकोबार की धरती के लिए आपको बहुत दर्द है। मैं कालापानी का सांसद हूँ। 29 मई, 2015 को बाबुल सुप्रीयो जी ने मंत्री के नाते अंडमान का दौरा किया। पोर्टब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर - 2 में प्रधान मंत्री आवास योजना के नाम पर लैण्ड आइडेंटिफाई किया था। 11 दिन बाद हमारे लैफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको बॉटैनिकल गार्डन के नाम पर परिवर्तन कर दिया। उस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, मॅबर ऑफ पार्लियामेंट, वार्ड काउंसिलर ने विरोध किया था। स्टैंडिंग कमेटी, होम ने कहा था कि एम.पी. को कंसल्ट करना जरूरी है। स्टेक होल्डर्स बोलिए, म्युनिसिपल काउंसिल बोलिए, एम.पी. बोलिए, किसी को कंसल्ट नहीं किया। म्युनिसिपल काउंसिल ने रेजोल्युशन पास कर के बॉटैनिकल गार्डन बनाने का विरोध किया, तथा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने भी उसका विरोध किया, लेकिन एल.जी. मनमानी कर के जबरदस्ती वहां पर बॉटैनिकल गार्डन बना रहे हैं। जबकि उससे थोड़ी दूरी पर एक

बॉटनिकल गार्डन है। मैं आग्रह करता हूँ कि इस बॉटनिकल गार्डन को तुरंत बंद कर दिया जाए।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री बिष्णु पद राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों से हो रहे बहुसंख्यक समाज के पलायन के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदया, यह गंभीर प्रकरण है, मुज्जफरनगर शामली का कैराना हो, चाहे कांधला हो, चाहे अलीगढ़ में बाबरी मंडी से जुड़ा हुआ मामला हो, यह ठीक उसी प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है, जैसे सन् 1980-90 के दशक में कश्मीर घाटी के अंदर पैदा किया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उसी का दुपरिणाम है कि वहां गुंडे और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व, एक वर्ग विशेष के तत्व वहां व्यापारियों को, आम नागरिकों को और परेशान करते हैं और वहां पर सामान्य जन-जीवन को पूरी तरह ध्वस्त कर के रख दिया है। प्रत्येक कस्बे में बहुसंख्यक हिंदु समाज के लोगों को निशाना बना कर वहां से पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय शासन मौन बना हुआ है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्बों में हो रहे पलायन को सख्ती के साथ रोकें एवं उन आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही करें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री शरद त्रिपाठी को योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Now, Matters under Rule 377.

... (Interruptions)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : मैडम, हमारी क्या गलती है?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया? अब बाकी जो बचा है, वह कल लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : मैडम, मैं लगातार पांच दिन से आपके पास आ रहा हूँ। ... (व्यवधान) यह गलत बात है। ... (व्यवधान) मैडम, पंजाब में इलैक्शन है। ... (व्यवधान) इसलिए आप बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रवनीत जी, ऐसा नहीं है, आपको बोलने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रवनीत जी, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

12.58 hours**MATTERS UNDER RULE 377***

HON. SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. The Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today, and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to undertake repair of Khalilabad-Bakhira-Mehdawal road in Sant Kabir Nagar parliamentary constituency, Uttar Pradesh.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : मेरे संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर अंतर्गत खलीलाबाद-बखीरा होते हुए मेहदावल जाने वाली सड़क इस इलाके की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है। लेकिन इसकी दशा इतनी खराब है कि बरसात के मौसम में सड़कों पर 3-4 फीट पानी भर जाता है। यह ऐतिहासिक कस्बा है। यहाँ हज़ारों साल पहले कांच के बर्तन बनाने की तकनीक उपलब्ध थी। बखीरा कस्बा पूरे देश में हैंडलूम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसी समय प्रदेश की मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती सुचेता कृपलानी इस क्षेत्र की विधायिका हुआ करती थी। मैं इस सड़क को दुरुस्त करने के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। कई बार इस संबंध में प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस कस्बे की ऐतिहासिकता और वर्तमान में अति जरूरत को देखते हुए इस पर तत्काल काम शुरू कराया जाये।

**(ii) Need to provide adequate funds to the Tocklai Tea
Research Institute at Jorhat in Assam**

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): The State of Assam is the world's largest tea-growing region, lying on either side of the Brahmaputra River and bordering Bangladesh and Myanmar and all the tea estates are running under the guidelines of Tea Board of India. The Tea Board of India is a state agency of the Government of India established to promote the cultivation, processing and domestic trade as well as export of tea from India.

I would like to bring to the notice that Assam is the largest tea-producing State of India and the set-up of Tea Board is in Kolkata, West Bengal. It is a long standing demand of the people of Assam, Tea Board should be re-located to Guwahati, Assam. I request the Government of India to take an immediate action in this regard.

Apart from that, Tea Board of India is responsible for funding to Tocklai Tea Research Institute, Jorhat and it is the oldest and the largest research station of its kind in the world. Since inception, Tocklai has been serving the industry and has become synonymous with research on tea in the country. It has unfurled technological knowledge in tea segment from time to time. The phenomenal increase in production of tea in N.E. India, from 234 million kg in 1951 to about 619 million kg in 2002, clearly undermines the impact of R&D. The average productivity of TRA member estates covering 75% of the total tea growing area of the N.E. India is about 56% more than that of Non-members in the region which is an outcome of effective implementation of technology developed at Tocklai.

Now, there is no funding to Tocklai Tea Research Institute neither by Tea Board of India nor Government of India. The situation of Tocklai Institute is very bad, there are no research works going on.

I request the Government of India to provide sufficient funds to Tea Board of India and instruct the concerned department to make sure Tocklai Tea Research Institute is allocated necessary funds for research and development of tea in India.

(iii) Need to conduct proceedings of cases in High Courts in regional languages.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : हिन्दी हमारी राजभाषा है और देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली व समझी जाने वाली सर्वमान्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए ज़ोर दिया था।

कई राज्यों की हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में आज भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है। अभी शिक्षा का स्तर काफी आगे बढ़ चुका है। मीडिया की वजह से लोगों की जागरूकता के साथ ही साथ न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का रुझान और जागरूकता काफी बढ़ गई है। ऐसे में वे ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि उनके राज्य की भाषा में हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग करने की अनुमति उन्हें प्रदान की जाए, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके बारे में अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है।

भारतीय संविधान की धारा 348 (2) में केंद्र सरकार आवश्यक संशोधन करके संबंधित राज्यों की हाईकोर्ट को उनके राज्य की भाषा में हाईकोर्ट का कामकाज करने की अनुमति दिलाने की व्यवस्था करें जिससे लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के बारे में और अपने केस के निपटारे की पूरी जानकारी उनकी भाषा में उपलब्ध हो सके।

(iv)Need to curb illegal sand mining by having a National Policy

SHRIMATI RAKSHATAI KHADSE (RAVER): Sand is the soil of the river providing and sustaining virtually all life that exist in the river. Due to boom in real estate and construction activities, there has been a major spike in the sand (both Beach & river) requirement which has resulted in unscientific and indiscriminate sand mining. This has affected the river ecology, polluted the rivers, low PH mix of various metal oxides, reduced oxygen from water and thus increased BoD, this badly affects river biota. Stream sand mining results in the destruction of aquatic and riparian habitat through large changes in the channel morphology. The impacts include bed degradation, bed coarsening, lowered water tables near the steam bed and ultimately channel instability. This further results in polluted water and also reduced water levels. Sand mining critically leads to drinking water shortage and also agrarian distress in the vicinity which in turn leads to exodus of people to urban clusters upsetting the economic and cultural balance of a society and creates social tension. This indiscriminate mining has also destroyed hills, eroded biodiversity spheres, denuded forests and degraded fertile soil. Largely this has changed the physical characteristics of river basins, impacting heavily the socio-economic condition of the local people. Due to sand mining extra vehicular traffic has generated which has negatively impaired the environment. Sand Mining should not be permitted where there are fractures in underground aquifers which help in ground water recharge. Hence the need is to better implement legislative mechanisms and various judicial pronouncements for sustainable sand mining. I request to develop, design and create a National Policy for sustainable sand to arrest the illegal mining which is effective. I request further to look for quality & affordable alternatives to sand to meet the increasing demand for sand without compromising riverine ecology.

(v) Need to probe the shoddy construction work of sewerage and pipeline system under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal System in Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मैं सरकार का ध्यान लोक महत्व से जुड़ी कानपुर नगर की एक अति विषम समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

यह मुद्दा कानपुर शहर में सड़कों की बेतरतीब खुदाई का है जिसने करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व को चोट तो पहुँचाई ही है, नागरिकों के सामान्य जीवन को नारकीय हालत में पहुँचा दिया है। इतना ही नहीं जन-धन की व्यापक क्षति की आशंकाएँ प्रतिपल मुंह बाए रहती हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के तहत कानपुर में विगत आठ वर्षों से उच्च क्षमता की सीवर और पानी की पाइप लाइन डाले जाने का कार्य किया गया है लेकिन इनके ऊपर बनायी गयी करोड़ों रुपये की लागत की सड़कें पाइप लीकेज के चलते नष्ट-भ्रष्ट हो गयी हैं। कानपुर नगर में इस योजना पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उनका प्रभावी उपयोग तो दूर, निम्न स्तर के निर्माण कार्य ने इतनी ही लागत से बनी सड़कों को तबाह करके रख दिया है। खुद कानपुर के नगर आयुक्त ने विगत दिनों पूर्व समाचार पत्रों को बयान देकर यह तथ्य उजागर किया है कि कैसे सीवर और पाइप के घटिया काम के चलते करोड़ों के निर्माण पर पानी फिर चुका है। उक्त कार्य में आर्थिक अनियमितताएँ इस कदर की गयी हैं कि कई स्थानों की मिट्टी खोदकर एवं बिना पाइप डाले मिट्टी को पुनः भर दिया गया एवं जहां पर पाइप डाले भी गए उस स्थान पर बेस के लिए न तो गिट्टी का इस्तेमाल किया और न ही बालू से भराई की गयी। कार्यों को अधूरा छोड़े जाने के कारण शहर भर में लीकेज की समस्या है जिसके चलते एक ओर जहां पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है वहीं दूसरी ओर पाइप लाइन लीकेज होने के कारण करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं एवं कई स्थानों पर जल भराव हो गया है जबकि विभाग द्वारा उक्त कार्य का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत दिए गए धन का उपयोग नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। नौबत यहां तक आ गयी है कि उक्त लीकेज को बंद किये जाने के लिए कई करोड़ रुपए भी विभाग द्वारा खर्च कर दिए गए। उक्त योजना के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों का परीक्षण न होने के कारण योजना से सम्बद्ध विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक घटिया किस्म के पाइपों का इस्तेमाल किया गया है। जनपद कानपुर में गहरी सीवर लाइन एवं पेयजल परियोजना में सभी नियम-कायदों को ताक पर रखकर एवं मानकों के विपरीत तथा गुणवत्ता न होने के कारण 1 वर्ष पूर्व डाली गयी पाइप लाइन की लीकेज हो रही है एवं पूर्ण भूमिगत न किये जाने के कारण टूट रही है। उक्त योजना के अंतर्गत कराये गये समस्त कार्यों की जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है।

अतः आपसे निवेदन है कि आम जन मानस की मूलभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजना के अंतर्गत कराये जा रहे तथा कराये गए समस्त कार्यों की उच्च स्तरीय (सी.बी.आई.) जांच कराये जाने हेतु आवश्यक आदेश/निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

(vi) Need to construct a railway line between Jalgaon and Solapur in Maharashtra.

श्री रावसाहेब पाटील दानवे (जालना) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र जालना में जलगाँव-सोलापुर रेल मार्ग की बहुत पुरानी मांग है। यह रेल मार्ग उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को जोड़ता है। इसके अलावा कर्नाटक तक यह सीधी रेलवे लाइन हो सकती है जिससे इस क्षेत्र का विकास तेजी से होगा।

इस मार्ग के सर्वे के लिए बजट भी आवंटित किया गया था परंतु इसके बावजूद भी इस मार्ग के निर्माण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस रेल मार्ग का निर्माण क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि जलगाँव से सोलापुर रेल मार्ग का सर्वे जल्द से जल्द कराकर इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाय।

(vii) Need to provide compensation to farmers in Jammu and Kashmir who lost their land due to fencing along the border.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर राज्य के उन सीमावर्ती स्थानों की ओर दिलाना चाहता हूँ जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण, तारबंदी के दूसरी ओर की खेती की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं।

उन गरीब किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, उनकी भुखमरी की नौबत आ गई है। इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है। न ही उन्हें कोई रोज़गार मिला और न ही उन्हें उस जमीन का मुआवजा अभी तक मिला है, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में सीमा पर स्थित जिन किसानों को तारबंदी की वजह से अपनी जमीन से वंचित होना पड़ा है, उन किसानों को शीघ्र उचित मुआवजा दिया जाए।

(viii) Need to set up a special group to report on the problems afflicting the hydel sector in Himachal Pradesh.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : हिमाचल प्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जो समस्त भारत की जल विद्युत क्षमता का 25 प्रतिशत दोहन करने की क्षमता रखता है। प्रदेश की सभी नदियों की कुल विद्युत क्षमता 27,436 मेगावाट आंकी गई है लेकिन अभी तक केवल 8,415 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का ही दोहन हो पाया है और इस क्षमता का 7.6 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है तथा शेष केन्द्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने जल विद्युत दोहन को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन इन योजनाओं का सकारात्मक परिणाम देश और प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पाया है।

हिमाचल प्रदेश देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जो पर्यावरण की दृष्टि से देश का एक आदर्श राज्य बन सकता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ वित्तीय साधन सीमित हैं। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर्यटन और जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्भर करती है। प्रदेश में इन प्रोत्साहनों के चलते 655 लघु विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें अधिकांश परियोजनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र में है। इन परियोजनाओं में अधिकांश परियोजनाएं केंद्र सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए कई वर्षों से लटकी पड़ी हैं। यही नहीं इसके अतिरिक्त कुछ संचालन सम्बंधी समस्याएं ऐसी हैं जो केंद्र और राज्य सरकार में उचित तालमेल न होने के कारण कई वर्षों तक सुलझ नहीं पाती। ट्रांसमिशन लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण पर कम मुआवजा, आवश्यक वनीकरण के लिए कम जमीन की उपलब्धता और वन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सुरंगों के लिए भूमि के परिवर्तन का प्रमाण-पत्र, अधिग्रहण क्षेत्र के सुधार आदि ऐसी कुछ विशेष समस्याएं हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार को समय-समय पर विचार करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि हिमाचल में जल विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय का एक विशेष दल गठित किया जाए जो प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करे ताकि इन परियोजनाओं का संचालन बिना किसी व्यवधान के हो सके।

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर हिमाचल की आर्थिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। जिससे लगभग 85 हजार स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा तथा हिमाचल प्रदेश को करोड़ों-अरबों रूपए का राजस्व भी प्राप्त होगा।

(ix) Need to construct school building for Kendriya Vidyalaya At Chitrakoot, Uttar Pradesh.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चित्रकूट जनपद में केन्द्रीय विद्यालय रैनबसेरा चित्रकूट में चल रहा है, जिसमें जगह की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उसे भी नगर पालिका द्वारा खाली करने का दबाव है। केन्द्रीय विद्यालय बनाने हेतु जिला प्रशासन ने जमीन भी केन्द्रीय विद्यालय के नाम कर दी है। लेकिन अभी तक उसमें निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है। जमीन दिए काफी समय हो गया है। इस बाबत कई बार लिखने व कहने पर भी विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है। अस्तु सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय विद्यालय चित्रकूट जनपद हेतु भवन का निर्माण यथाशीघ्र शुरू कराकर पूर्ण कराया जाए जिससे शिक्षण कार्य बाधित न हो।

(x) Need to facilitate environmental clearance for construction/development of stretch of National Highway No. 28B passing through Valmiki Nagar parliamentary constituency, Bihar.

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर) : मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर (बिहार) से होकर गुजरने वाले एक मात्र नेशनल हाईवे 28बी का 97 किलोमीटर से 112 तक का एन.ओ.सी. अभी तक पर्यावरण विभाग से नहीं मिला है जिसके कारण उस नेशनल हाईवे पर विकास कार्य व यातायात नहीं हो पा रहा है। इसके चलते लाखों यात्री रोजाना परेशान हो रहे हैं और राजस्व की भारी क्षति हो रही है।

मैं माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दो प्रदेशों को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण हाईवे के निर्माण/विकास के लिए माननीय पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार से समन्वय बैठकर शीघ्र ही एन.ओ.सी. जारी करवाएं या दूसरा कोई वैकल्पिक हल निकालने की कृपा करें।

(xi) Need to bring civilian areas of various Cantonments under nearby Corporation of Municipality.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर) : देश के विभिन्न स्थानों पर 62 केन्टोनमेंट बोर्ड हैं। इनमें जो जमीन है, उसका विभाजन सिविल लैण्ड तथा डिफेन्स लैण्ड के रूप में किया गया है। सिविल लैण्ड वह जमीन है जिस पर सघन मात्रा में सिविलियन रहते हैं तथा डिफेन्स लैण्ड वह जमीन है, जिस पर कम मात्रा में सिविलियन बंगले बने हैं तथा इसका प्रशासन सीधे सेना की देख-रेख में होता है। सिविल लैण्ड के निवासियों की सभी प्रकार की सुविधाओं का संचालन केन्टोनमेंट बोर्ड के अधीन रहता है। इसके चुने प्रतिनिधि इस पर नियंत्रण रखते हैं।

अनुभव बतलाता है कि सिविल लैण्ड जिसे बोलचाल में सदर एरिया भी कहा जाता है, में नगर निगम, नगर पालिका के निवासियों को जिस प्रकार की सभी सुविधाएँ मिलती हैं, वहीं सुविधाएँ केन्टोनमेंट एरिया में रहने वाले सिविलियन लोगों को नहीं मिलती है। अधिकांश बोर्डों के पास भूमि का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक अमला भी उपलब्ध नहीं होता है। देखा यह भी गया है कि सिविल नागरिकों के साथ छावनी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है। जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में छावनी बोर्ड के अधिकारियों के कार्यों से तनाव रहता है, जिसको दूर किया जाना चाहिए।

अतः मेरी शासन से माँग है कि सभी केन्टोनमेंट बोर्डों की सिविल लैण्ड, सदर एरिया को समीप में स्थित नगर निगम, नगर पालिका में शामिल कर दिया जाये, जिससे उन्हें अन्य नागरिकों को उपलब्ध होने वाली सुविधाएँ मिल सकें।

**(xii) Need to set up an Agriculture Engineering Institute in
Jalaun district of Uttar Pradesh.**

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जालौन, गरौठा, भोगनीपुर, बुंदलेखंड क्षेत्र में आते हैं। बुन्देलखण्ड के अस्सी प्रतिशत निवासी मुख्यतः कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है, जो निश्चित ही एक स्वागतयोग्य कदम है। इस विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसके दो केन्द्र क्रमशः टीकमगढ़ व ललितपुर जनपद में प्रस्तावित हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में भार, कावर, पडुआ, राकड चारों किस्म की मिट्टी पाई जाती है, परन्तु उच्च मृदा गुणवत्ता होने के बावजूद भी यहां पर कृषि सुधार की आवश्यकता है। जनपद जालौन का कृषि वैज्ञानिक केन्द्र भी कानपुर से संबद्ध है, जिसे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाये।

मेरी केन्द्र सरकार से माँग है कि जनपद जालौन में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की जाये तो निश्चित ही जनपद का सर्वांगीण विकास हो जायेगा।

(xiii) Need to provide clean and safe drinking water to people in Balia parliamentary constituency, Uttar Pradesh.

श्री भरत सिंह (बलिया) : हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बलिया मुख्य रूप से गंगा एवं घाघरा नदी के तट पर बसा हुआ है तथा सैकड़ों तटवर्ती गांवों के भू-गर्भीय जल में भारी मात्रा में आर्सेनिक तथा अन्य रासायनिक पदार्थ मिला हुआ है, जिसके कारण इन गांवों के निवासियों एवं पशुओं को पेयजल के संकट से जूझना पड़ रहा है। आर्सेनिक युक्त जल पीने से हजारों की संख्या में लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं तथा विगत वर्षों से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से बीमार होकर, घुट-घुट कर मर चुके हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तब से मैं इस अत्यंत गंभीर मुद्दे को सदन में कई बार उठा चुका हूँ कि आर्सेनिक प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार पहल करे, जिससे कि ग्रामवासियों के जीवन की रक्षा हो सके। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर इस अत्यंत गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही की जाये।

(xiv) Need to provide land for setting up of a Cancer Research Centre and Hospital at Bhandup in Mumbai

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): There is a proposal by Ministry of AYUSH for establishment of Cancer Research Centre and Hospital at Bhandup, Mumbai. For establishment of this Hospital they need a piece of land bearing survey no. 246, measuring 13456 sq. yd. at Bhandup which is a vacant land. This land belongs to CPWD, Mumbai under the Ministry of Urban Development. The Ministry of UD has now proposed for construction of GPOA instead of OPRA on this piece of land. But till date the piece of land that is required by M/o AYUSH from the M/o UD has not been handed over for establishment of Cancer Research Centre and Hospital at Bhandup. I request the Hon'ble Minister of UD for early handing over the piece of land to AYUSH so that they can open the Hospital.

(xv) Need to provide broadband connectivity to Post Office, Suwana in Bhilwara parliamentary constituency, Rajasthan.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : देश में सभी पोस्ट ऑफिसों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जा रहा है। पोस्ट ऑफिसों को इसके लिए कॉपर मीडिया के माध्यम से कनेक्शन देने के अधिकार दिये गये हैं परंतु कॉपर मीडिया से एक्सचेंज से 3 कि.मी. की दूरी तक ही कनेक्शन किये जा सकते हैं। इस कारण से मेरे लोक सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के पोस्ट ऑफिस सुवाणा (पिन कोड नं.-311011) सहित राजस्थान में लगभग 93 पोस्ट ऑफिस ब्रॉडबैंड कनेक्शन से वंचित है इन्हें फाइबर मीडिया से कनेक्शन लेने की अनुमति देकर ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय ने भी पिछले सत्र में आश्वस्त किया था कि सभी पोस्ट ऑफिस ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़े जायेंगे। मेरा आग्रह है कि यदि फाइबर मीडिया से कनेक्शन लेने की स्वीकृति नहीं दी गयी तो तकनीकी रूप से यह संभव नहीं होगा। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूँ कि ब्रॉडबैंड सेवा से जुड़ने से वंचित रहे सभी पोस्ट ऑफिसों को फाइबर मीडिया से कनेक्शन लेने की स्वीकृति देकर जोड़ा जाये।

(xvi) Need to provide assistance to Kerala for completing the seawall along its coastline

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Kerala has a 580 km long coastline with hundreds of families living along the coast itself. These families mainly depend on fishing for their livelihood and it is almost impossible to relocate them without hampering their means of subsistence. These poor fisher folk are constantly exposed to the rough seas and consequent land erosion and their life and property are always at risk more so during the monsoons. Several stretches of stone seawall have been attempted. But this is not a permanent solution or sure remedy. Hutments are being washed away and the people live in deep and constant fear. I urge upon the Government to make a scientific study in consultation with other coastal nations that have been successful in coastal management and work out a solution befitting India and especially Kerala, which is vulnerable to the onslaught of strong monsoon winds. As for now, since monsoon has already set in, I request the Government to extend all possible assistance to the state of Kerala for completing the seawall along the entire length of its long coastline so that the poor fisher folk are duly protected.

(xvii) Regarding rejuvenation and replanting of coconut palms in Tamil Nadu

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Tamil Nadu stands first in the production of coconuts (6917.25 Million Nuts). Tamil Nadu comes third in terms of area under cultivation of coconut. However, the State faces challenges in maintaining the productivity of coconut groves due to severe pest and disease attacks and senile and unproductive palms. To increase yield, coconut palms have to be replanted.

Government of Tamil Nadu has proposed a special package with a total outlay of Rs. 3397.80 crores including subsidy of Rs. 757.95 crores (25% of the outlay) to improve existing gardens, remove old and senile palms and replant coconut seedlings. The project covers 161 lakh palms in 92,000 hectares. This proposal is under consideration of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. As this scheme would raise yield and increase edible oil production, the Government of India may kindly consider early sanction of scheme for the Rejuvenation and Replanting of Coconut Palms in Tamil Nadu as requested by our Hon'ble Chief Minister.

(xviii) Regarding expansion of Salem Steel Plant in Tamil Nadu

SHRI V. PANNEERSELVAM (SALEM): I would like to draw the attention of Hon'ble Minister of Steel towards some of the issues pertaining to Salem Steel Plant.

The Salem Steel Plant (SSP) has enormous potential for expansion and for increasing the production line of that plant. Expansion of the Salem Steel Plant is also one of the long-felt need of the industrial-associations, business-associations and people of my Constituency. Setting up of a manufacturing unit for the production of house-hold-articles and an exhibition centre for the same will definitely increase the business volumes of the plant. The SSP shall use its rich experiences and material resources for setting up a separate manufacturing unit for the production of Rail/Metro-train coaches in collaboration with Railways/ICF. Production of Metro-rail coaches will help in saving foreign exchange. These measures will not only bring more profits for the plant but also generate employment opportunities for people.

Further, I also wish to submit that the SSP should take necessary steps for providing proper road facilities to more than one lakh people in eight villages in the 16 Kilometres stretch of land from Muniampatti to Poolanpatti. This will solve the problem of the people of these villages who now have to take circuitous route to travel to Poolanpatti. This may be undertaken as part of the Corporate Social Responsibility of the SSP of the local people.

Hon'ble Minister of Steel may kindly consider my above requests and suggestions favourably and issue instructions to concerned authorities in this regard.

(xix) Need to release funds to Government of Andhra Pradesh for the Panchayati Raj Department of the State

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI)(ANAKAPALLI): The 14th Finance Commission has recommended that the States' share in the net proceeds of the Union tax revenues be 42%. The recommendation of tax devolution at 42% is a huge jump from the 32% recommended by the 13th Finance Commission. The transfers to the States will see a quantum jump. This is the largest ever change in the percentage of devolution. In the past, when Finance Commissions have recommended an increase, it has been in the range of 1-2% increase. As compared to the total devolutions in 2014-15, the total devolution of the States in 2015-16 will increase by over 45%.

The 14th Finance Commission has recommended distribution of grants to the States for local bodies using 2011 population data with weight of 90% and area with weight of 10%. The grants to States will be divided into two, a grant to duly constituted Gram Panchayats and a grant to duly constituted Municipal bodies, on the basis of rural and urban population.

14th Finance Commission has recommended grants in two parts; a basic grant, and a performance grant, for duly constituted Gram Panchayats and Municipalities. The ratio of basic to performance grant is 90:10 with respect of Panchayat and 80:20 with respect to Municipalities.

14th Finance Commission has recommended a total grant of Rs. 2,87,436 crore for five year period from 1.4.2015 to 31.3.2020. Of this, the grant recommended to Panchayats is Rs. 2,00,292.20 crores and that to municipalities is Rs. 87,143.80 crores. The transfers in the year 2015-16 will be Rs. 29,988 crores. But the Panchayati Raj Department, Government of Andhra Pradesh has not received any amount. As a result they are not able to devolve funds to Panchayati

raj institutions in the villages and no development work is taking place. I want to know from the Ministry of Panchayat Raj how many Panchayati raj institutions are there in India, particularly in Visakhapatnam and Anakapalle? What is the allocation of funds in the last two years?

I urge upon the Government to release funds to the Andhra Pradesh Panchayati Raj Department at the earliest for further devolution.

(xx) Need to include Saudi Arabia among those countries which are exempted from bio-metric visas

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Kerala is an established tourist destination for both Indians and non-Indians alike. Tourism is a very important source of revenue for the state's economy. The Centre's recent decision making bio-metric data compulsory for citizens of Saudi Arabia would adversely impact the state's tourism prospects. Every year around five lakh holidayers visit Kerala from Saudi Arabia. The Centre has made bio-metric data compulsory at a time when the state is eyeing more tourists from Saudi Arabia. The applicant has to appear directly to get the bio-metric visa issued. But it is not a must for e-visa. There are chances that the Saudi tourists may opt for other countries, including neighbouring Sri Lanka, in view of the complexities in applying for bio-metric visas. This will adversely impact the state's tourism revenue.

I urge the Government to include Saudi Arabia among those countries which are exempted from bio-metric visas and should be issued e-visas.

(xxi) Need to grant special category status to Bihar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार अत्यंत ही पिछड़ा राज्य है। पिछड़े राज्यों की श्रेणी में दूसरे पायदान पर है, जैसा कि रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। उस कमेटी का सुझाव था कि बिहार समेत उड़ीसा को अन्य राज्यों के समानान्तर लाने के लिए केंद्र सरकार को बहुत कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहले बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देकर वहां उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है और केन्द्र से आग्रह करती आ रही है, किन्तु न तो पिछली सरकार और अब न ही मौजूदा सरकार राज्य के हित की बात कर रही है। राज्य की करीब 11 करोड़ आबादी को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। वैसे ही राज्य का आधे से अधिक

भू-भाग प्रतिवर्ष बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है और शेष भाग में सूखे की स्थिति बनी रहती है। बिहार में पिछले 30 वर्षों से मात्र बाढ़ पॉवर प्लांट एवं नालंदा में एक आयुध फैक्ट्री व रेल कारखाना के अलावा कोई भी कल-कारखाने नहीं लगे हैं। विगत आम चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य की जनता को पूर्ण भरोसा दिया था कि बिहार को अगर किसी में विशेष राज्य का दर्जा देने की ताकत है, तो वह सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है फिर भी बिहार जैसे अति पिछड़े राज्य के प्रति उदासीनता समझ से परे है।

अतः पहले की तरह मैं फिर केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देकर यहां भी टैक्स की छूट मिले, जिससे कि राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके और हम भी देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर राज्य एवं देश को आगे बढ़ाने में सरकार को मदद कर सकें।

(xxii) Need to review the decision to handover 12 oilfields to private parties in Assam

SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): I on behalf of people of Assam strongly oppose the Central Government's decision to bid 12 oil fields of Assam to the private and foreign companies. The decision of Government has triggered agitation in the state as privatization of the field would take away the people's right over the resources. In Gujarat, the Centre handed over the oil field to the state-run Gujarat state petroleum corporation. But in Assam, the oil field is being given to private parties.

The Government is arguing that Government companies have no capacity or required manpower for this purpose but we know well that both Oil India and ONGC are exploring oil in other places of India as well as in Arab and African countries. In his statement, the Petroleum Minister said that approximately Rs. 78000 crore can be earned by exploration at the cost of only Rs. 4000 crore. If the Government spends the amount of 4000 crore for making exploration, then it will bring profit to the Government thereby denying opportunities to the private and foreign companies. Moreover the state Government is also yet to receive royalty of 10,000 crore from Central Government and release of this amount will help State Government to make Assam Hydro Carbon and Energy Company Limited (AHCCL) capable for this purpose.

100% FDI (Foreign Direct Investment) is allowed in oil sector for which the Central Government will lose its control over pricing and marketing of explored oil and gas. I urge upon the Government of India to roll back its decision to hand over the 12 oilfields of Assam to private or foreign companies for exploring oil and give it to Government companies or State owned Corporations.

(xxiii) Need to address the problems faced by people belonging to Kachari community in Assam to get ST certificate

SHRI NABA KUMAR SARNIA (KOKRAJHAR): In Assam Kachari community enjoys ST status but some of them who adopted Hinduism and took titles (Surnames) of high caste community have been denied ST Certificate.

I would like to express my deep feelings of anguish, discrimination, alienation and deprivation as they have been denied the Scheduled Tribe (ST) Certificate. They have been members of Kachari community which is a major tribal community living in Assam, since time immemorial and they are recognized as Scheduled Tribe community of Assam by the Constitution of India since Independence.

Since time immemorial, their village is under tribal belt and block. Under Bodoland Territorial Council included under Sixth Schedule every village is a tribal village. All are having Scheduled tribe certificate and get all facilities. Their Father and Grandfather are also having a Scheduled Tribe certificate issued by the All Assam Tribal Sangha and counter signed by concerned DC or Civil SDO of area as per laid down procedure in Assam. The Scheduled Tribe Certificate, in general, is being issued by the State Government in most of the States in our country. But in the State of Assam, the All Assam Tribal Sangha, an NGO, has been authorized to issue the Scheduled Tribe Certificate to the eligible communities and the same is countersigned by civil SDO or DC). Because of political influence and alleged vested interest of a dominant tribal group and some irresponsible persons with the interference from All Assam Tribal Sangha, the scheduled tribe certificates have been denied to the Community on the pretext that they have adopted Hinduism and taken the titles (surnames) of some upper caste community of Assam. For more than a decade, they are facing this problem. This is grossly against the natural justice as the Schedule Tribe Certificate cannot be denied to a Community as they have exercised their fundamental right to freedom of religion.

Therefore, I request the Central Government to take suitable action immediately to issue ST certificate to the Kachari Community so that they can also avail the benefits extended to the Scheduled Tribe community of the country.

12.59 hours**LOKPAL AND LOKAYUKTAS (AMENDMENT) BILL, 2016**

HON. SPEAKER: Now, we will take up Item No. 9(A).

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): I beg to move:

“That the Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, be taken into consideration.”

Hon. Speaker Madam, the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2013 became an Act from January 2014. ... (*Interruptions*) After the Government took over in May 2014, we went through the details of the Bill and opinion came up that certain more modifications were required in order to make it more feasible and workable. ... (*Interruptions*) So, the amendment to the Lokpal and Lokayuktas Bill was brought in the Lok Sabha in December 2014. There was a brief discussion following which the hon. Members across the party lines were of the opinion that the Bill needed to go to the Standing Committee for further deliberations. So, considering the sense of the House, the Bill was sent to the Standing Committee. The report of the Standing Committee was received in December 2015. The Bill became a law in January, 2014. Now, the Bill as we know, was passed by the Parliament on the recommendations of the Standing Committee and the amendments to the provisions of the Act have been introduced by the Government and reconsiderations are being made by the Standing

Committee which is already there. But some of the provisions of this Act are there.

13.00 hours

Some of the provisions of this Act have created certain issues. For example, the Act requires that all public servants should file their declarations of assets including assets of their spouses and children. That is one issue which has raised considerable amount of discussion. The date for that was April, which later on extended and currently the deadline or the last date is 31st July, 2016.

Similarly, Speaker Madam, the provisions of the Act also relate to another issue which has generated considerable amount of discussion. This is the declaration of assets by several persons connected with non-government organizations which receive funding from foreign sources or get direct or indirect funding from the State. Some of the NGOs, as all of us are aware, could also be running certain educational institutions; some of them are also running some media houses, both electronic and print. Therefore, while there are amendments which are pending consideration by the Standing Committee, the need for the public servants and the NGOs to file their asset declaration has raised quite a lot of debate.

In the meanwhile, on the 25th July, that is Monday, a delegation of hon. Members of Parliament from different parties met the hon. Prime Minister and requested him to delete the provisions with regard to the declaration of assets and also the provision requiring that these assets be made public. The Prime Minister assured them that the Government would look into the matter.

Considering all these, the Government has done some exercise on this and is of the opinion that since this law was framed after detailed consideration by the Standing Committee, the same would require to be considered in depth by the Standing Committee itself. The Government is open to the idea of amending the law but the same could be done only after it is considered by the Standing Government. The Government hopes that since the Standing Committee which is

already seized of the matter on a larger review of the Act as has been suggested from across the sections of the society and across the sections in both the Houses, the mentioned provisions would be considered in entirety and the Standing Committee would endeavour to make its recommendations expeditiously and if possible before the next Session of Parliament.

In the meanwhile, I propose an amendment in Parliament today in order to substitute the provision of section 44 which precisely deals with the declaration of assets and the provision of making the assets public. I do so, so that the present or the immediate impasse which has happened with regard to the declaration of assets could be overcome and the same in relation to the public servants which include the Government officials as well as the political functionaries and the other category of NGOs could be deferred.

With these few words, I propose to the hon. House that the amendment may kindly be accepted. Thank you.

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, be taken into consideration.”

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Is it to be deferred in perpetuity or deferred for a year?

HON. SPEAKER: Let him complete.

DR. JITENDRA SINGH: As I said, since we would refer it to the Committee we would request that the Report is available to us by the next Session, as is usually the norm. But in the meanwhile since this entire text is based on the sense of the House, I hope without discussion we could pass it since we also have the urgency of the date, 31st July which is the deadline.

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Wherefrom has the sense of the House emerged? Maybe, I was not present. This is an important Bill and is being discussed in entirety in the Standing Committee. You are expecting that the Report would come in the next Session. How do you arrive that immediately this one section has to be amended and why are you saying this is the sense of the House? When was the sense of the House arrived at?

DR. JITENDRA SINGH: As pointed out by the hon. Member, although the amendment Bill, which was introduced initially in December 2014 in the same House, had a long list of amendments these amendments were of a different nature. I will not be able to go into the details. For example, one of the provisions there was that the Selection Committee ought to have the Leader of the Opposition and since in the present House we did not have an acknowledged Leader of the Opposition we thought we could bring in an amendment accepting the Leader of the largest Opposition Party as the Leader of the Opposition. Similarly, in the Selection Committee we had a provision for having jurist members but somehow when the Bill was passed in January 2014 and became an Act, the duration or the term of the jurist was not specified. So, we thought that was also one technical amendment.

What I am trying to say is that though this is not the only amendment but the urgency, as the hon. Member is rightly pointing out, of bringing an amendment pertaining to Section 44 arises from the fact that this has put a binding on us to

stick to the deadline of July 31st for filing your assets, including the assets of the spouses and children and also making them public, and, not only the assets of the public servants but also assets of the NGOs. So, in order to overcome that technicality this amendment is being brought in. Of course, there are other amendments which can be taken up later on.

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Madam, may I just say one sentence that this is a sensible move on the part of the Government and I hope that the Standing Committee will make sure that genuine philanthropic and charitable work does not get adversely affected by the provisions of the Act. The phrase public servant has to be properly defined when the larger amendment comes. Thank you very much Madam Speaker.

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

SHRI MOHAMMAD SALIM: Madam, I have raised an issue and I have not got the answer.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

SHRI MOHAMMAD SALIM : Why are we not discussing the Bill?

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बुलाऊँगी, अभी पूरा कहाँ हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill ”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने का मौका दूँगी।

...(ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वहाँ तक पहुँचने तो दो।

...(ब्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

“That Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill. ”

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

DR. JITENDRA SINGH: Madam, I move:

“That the Bill be passed.”

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill be passed.”

SHRI MOHAMMAD SALIM: Madam, the Minister has talked about the urgency. I accept it. Without putting in the List of Business, without circulating any Supplementary Business, he is bringing this Bill before the House. It is a wrong parliamentary practice. I am asking you a question.... (*Interruptions*) क्या अर्जेन्सी है? आप मेरी बात सुन लीजिए।

HON. SPEAKER: Ahluwalia Ji, let him complete.

SHRI MOHAMMAD SALIM: It is a wrong practice.

Secondly, the Minister himself while introducing this Bill and asking for passing it, said in entirety the Standing Committee is seized of the matter but we have to amend Section 44. There are two reasons for that. One is, a delegation met the Prime Minister and the Prime Minister has said it. Secondly, there is the deadline of 31st July for declaration of assets. This is with retrospective effect from

2014. We know that this country has debated Lokpal and Lokayukt not only in Parliament, not only in the Standing Committee but outside also. इस पर बहुत चर्चा हुई। यह करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है और बेनामी के साथ भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2012 में जो रिपोर्ट आई थी, ब्लैक मनी के बारे में जो व्हाइट पेपर आए थे, तब से सरकार इस इश्यू को एड्रेस कर रही है। इसके बारे में बहुत-से कानून भी बने हैं। एल.ओ.पी. के मामले में जब जरूरत पड़ी, तब हमने लोकपाल बिल को अमेंड किया। लेकिन, इस तरह का आभास हो रहा है कि आप पब्लिक सर्वेत्स को इस क्रैद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम संसद सदस्य खुद इसके दायरे में आते हैं। क्या हम अपने आप को बचाने के लिए फिलांथ्रोपिक काम या एन.जी.ओ. बनाएंगे? हम जानते हैं कि सरकार एन.जी.ओ. के साथ क्या कर रही है और उनका किस तरह से ह्रासमेंट किया जा रहा है। उस वक्त इस एसेट डिक्लेरेशन के बारे में कहा गया था कि कानून में यह प्रोवीजन है कि यहां जो कम्पीटेंट ऑथोरिटी हैं, उनके पास आपको यह डिक्लेयर करना पड़ेगा। लोक सभा के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आपकी बुलेटिन के बाद भी, आपके निर्देश के बाद भी अपनी एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं, न्यूज मीडिया के लोग हैं।

सरकार इतने प्यार से क्यों अचानक पब्लिक सर्वेन्ट इन्क्लूडिंग मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को इससे क्रिफायत देने के लिए इस बिल को बिना चर्चा के पास कराना चाहती है, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया है। सरकार को बताना पड़ेगा कि वह किसके दबाव में यह कर रही है?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मिनिस्टर बोल रहे हैं। आप शोर क्यों कर रहे हैं?

DR. JITENDRA SINGH: Madam, at the outset, I would like to clarify that the Government is not against the Lokpal Bill. Let not the message by any chance go that we are against the Lokpal Bill or we are against eradication of corruption. That is certainly not the message and that is certainly not the intention.

I have heard the hon. Member who has given some good inputs. Now what we are trying to actually facilitate is effective implementation of the Bill. For that only, we brought in the amendment Bill in December 2014 because the Bill as it had been passed and became an Act in January 2014 was not workable for a number of reasons which I have already tried to point out to you. These issues included the issue of Leader of the Opposition, duration of various members, term of the jurists and then certain logistic issues as well. Those amendments are still

there and they were sent to the Standing Committee on the advice of the House. The Standing Committee report has come.

Now out of those amendments, amendment to Section 44 has certainly created an urgency because it pressurised the deadline of July 31. Now since this is a Bill which has already become law, we cannot do it on our own. We have to come back to Parliament. So, specifically for Section 44, we have brought it.

Now as per the second part which the hon. Member has pointed out, it is not that the delegation met the hon. Prime Minister and therefore this is inspired. You are narrating only half truth of what I said... (*Interruptions*). Let me repeat what I said. I said that the opinion was sought to be obtained from different sections of society including the stakeholders as also from hon. Members of Parliament from both the Houses across party-lines. You please read my statement. I had said that 'in the meanwhile'. It is not that the delegation met and overnight we got prompted. So, this is part of a larger process to gather as many inputs as possible from the stakeholders as well as from others.

Thirdly, as far as public servants are concerned, which includes the Government officials, political functionaries including Members of Parliament, nowhere have we tried to say or there is a reflection of the intention that we are trying to do away with the provisions against corruption. At the same time, there are issues which have been raised by the public servants relating to the declaration of the assets of their spouses and their children. For example, you have a Civil Servant, mostly lady officers have also raised this contention that the spouse is working elsewhere and they are not very clear whether they should be asked to make it public and declare the assets. So, we said that let us have a serious, fair, objective thought over it. That is one aspect.

Secondly, as far as the NGOs are concerned, it is not my NGO or your NGO or siding with any NGO. We have NGOs which are doing philanthropic activities; there are NGOs which are running educational institutions, some of them good ones; we have NGOs or Trusts running media houses. Therefore, it is

just to give a space to the inputs received from all of them. We have never negated if the Standing Committee and the opinion later on is to go ahead in the same line as it is today, the Government is ready to go ahead on that. We are committed to work against corruption and to implement the Lokpal as approved by the House...

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : बाद में फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाना ही है, उस समय आप उसको फिर पलटा दो।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, on last Monday in the Business Advisory Committee meeting I said that we need to talk on this and give us time and please do not list it for Tuesday. But the Government said that it was very urgent. We agreed for listing it on Tuesday. But we said we want to have a discussion. We said at that time that we have certain points to raise on this. But we are not getting that opportunity here to discuss it. I can appreciate the urgency.

Hon. Minister, I would like to ask you a question. Is there any concept in the mind of the Government that NGOs should be kept beyond the scope of this Act whether it is running a media house or running an educational institution? Educational institutions have now become commercial. Where is any charity in educational institutions? Only in a very few places there are educational institutions which are doing this charity. It is alright that the Bill is being passed without discussion. But for the benefit of the country please do not make any attempt to dilute the Act itself. There should not be any dilution. NGOs are also responsible. NGOs are taking money. Simply because an NGO is running a media house and therefore they should be kept beyond the scope of this Act is something which we are opposing.

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the suggestions of the hon. Member are very well taken. I do not know how the message has gone that we are trying to spare or bail out any NGO which is at fault.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: It is just an advisory.

DR. JITENDRA SINGH: I do not know how the message has gone that we are trying to spare or bail out any NGO which is at fault. Not at all. Who said that?

श्री मल्लिकार्जुन खडगे (गुलबर्गा) : इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बहुत अर्जेंट है। 31 जुलाई तक इसका टाइम रहने से इसको एक्सटेंशन के लिए आप सैक्शन 44 में लाए हैं। The date from which you want to commence you will notify that date. But...(व्यवधान) 2014 करो या 2015 करो, दुबे जी, वर्ष 2014 में हमने किया। आप थोड़े अमेंडमेंट्स लाए, यह अलग बात है, लेकिन यह डायलूट नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि लोकपाल बिल को यहां पर लाकर सभी एमपीज ने मिलकर इसको डायलूट कर दिया और वे खुद इसके दायरे से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसे क्लेरिफाई करिए।

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Madam Speaker, the point made by Shri Kharge ji, a very senior Member, is very well taken. Certainly, it is neither the intention nor the design to dilute the Act. We are ready to make it even more stringent if that is the recommendation given to us. We are ready to go as far as possible in the endeavour against corruption. If you read the last line of the 44th Amendment, it says:

“On and from the date of commencement of the Act, every public servant which also includes the NGO shall make a declaration of his assets and liabilities in such form and manner as may be prescribed.”

So, certainly, we have not deleted that part. It still exists but, maybe, on the advice of everybody including the stakeholders, we would give an opportunity for another thought to it.

HON. SPEAKER: The Minister may now move the motion to pass the Bill.

DR. JITENDRA SINGH: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. SPEAKER: I think, the matter is clear to everybody.

The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.25 p.m.

13.20 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Twenty Five Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.30 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION) AMENDMENT BILL, 2015*

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we take up item No.10 – Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Benami Transactions
(Prohibition) Act, 1988, be taken into consideration.”

HON. DEPUTY SPEAKER: Do you want to say anything?

SHRI ARUN JAITLEY: I just want to make a brief comment as far as this legislation is concerned. Originally the Benami Transactions (Prohibition) Act was enacted in 1988. The tenor of the provisions of that Act had only nine Sections and any person who wishes to acquire an asset or a property must do it in his own name, with his money. If he acquires it in the name of somebody else, then, it is deemed to be a benami property.

Even though two judgements of the Supreme Court came, as to which is a benami property and which is not a benami property, from 1988 till today, 2016, this law has not been put into effect. And the reason why this law was not given effect was that the law provided for two significant provisions as to the fact that if there is a benami property, benami transactions are prohibited and the State will have the power to acquire the benami property. Further that the person who enters into this benami transaction is liable to be prosecuted. There was nothing else mentioned in the Act.

* Moved with the recommendation of the President.

When this Act went to the Law Ministry thereafter, there was no machinery provided for as to how the acquisition would take place, as to what would be the terms of the acquisition. When this law was framed, it was thought that everything else would take place by virtue of rules. Probably the Law Ministry thought, and rightly so that this could be a case of excessive delegation. There are some vital provisions in every law which have to be provided in the legislation itself, and some non-operational provisions could be operationalised through the rules itself. So the Law Ministry said that rules cannot be framed. So, this Act had to be operationalised through rules, and the rules were never framed.

Thereafter, an effort was made and to begin this particular legislation subsequently, after this legislation was brought in, it was then redrafted in 2011 by the UPA Government in the form of amendment to the 1988 Bill. The reason why we want to amend the 1988 Bill – the original Bill has nine Sections but a large number of Sections were added – one proposal was that it should be repealed and a new Bill should come in. But then if we brought in a new Bill, properties acquired benami between the period of 1988 onwards would have all gone scot-free. So, it was considered necessary that the old law be allowed to remain, and the new amendments be inserted into the old law itself. Now that Bill lapsed with the lapsing of the Lok Sabha, even though it was referred to a Standing Committee, and the Report did come.

In 2015, a fresh amendment Bill was introduced by us, the original Bill has nine Sections, and the amendment Bill has 71 Sections. The reason for incorporating the amendments in the Bill is again the same that we want the Bill to be operationalised from 1988 onwards. A large number of amendments have been introduced. This Bill has been referred to the Standing Committee. The Standing Committee has given a certain set of recommendations and the most important amongst them was that what are the exceptions to the benami principles. One exception which the law provided for was, properties held within an Undivided

Hindu Family. That is, property may be in the name of the Karta but the beneficiaries may be other coparceners.

The second amendment was, in the event of a Trust, Trustee can hold the property as a fiduciary of the principal Trust. So, those would be exempted. Now, there was certain categories of amendments which Members of the Standing Committee itself suggested that there are a large number of properties particularly in the Union Territory and elsewhere where transactions take place on a Power of Attorney and an agreement to sell, people are put into possession and by virtue of the provisions of Section 53(A) of the Transfer of Properties Act the possession is protected. But the property continues to be in the name of the original owner. Will those be treated be as benami? So, Members suggested that a further amendment may be incorporated that properties which are already under some form of arrangement of this kind should really be brought in as far as this legislation is concerned. We considered it appropriate and that key amendment has been accepted by the Government. Therefore, those amendments have also been circulated.

Sir, the principal object behind this Bill is that a lot of people who have unaccounted money invest and buy immovable property in the name of some other person or a non-existent person or a fictitious person or a benami person. So these transactions are to be discouraged. As far as assets held illegally abroad are concerned, from the very beginning the effort of the Government has been, they should be squeezed, the use of cash beyond a certain limit should be discouraged, unaccounted money must make way and, so, the colour of transaction of money itself must change. Therefore, this is an important step in that direction. It is predominantly an anti-black money measure that any transaction which is benami is illegal and the property is liable to be confiscated. It will vest in the State and the entrant of the benami transaction is liable to be prosecuted.

With these few opening remarks, I commend this Bill for discussion and acceptance of the hon. House.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988, be taken into consideration.”

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, first of all I would like to express my sincere thanks to you for having allowed me to initiate the discussion on the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015.

Sir, benami transactions are detrimental to the interest of this nation and benami transactions constitute a serious offence against the State also. It is the bounden duty of the Government not only to prohibit these transactions, but also to prevent any benami transactions from taking place. So, prohibition is needed and prevention is also required equally.

We have been hearing much about Indian black money in foreign countries. We hope that the Union Government is still making its effort to bring back Indian black money in foreign countries. But to our surprise, we have got enormous and sufficient black money on our Indian soil itself.

Sir, as the hon. Minister has rightly pointed out, these haves will make use of have-nots to preserve their ill-gotten money. The haves, who have got a lot of ill-gotten money, will make use of the situation of have-nots and they will keep this money in the name of have-nots.

The easiest way of keeping the ill-gotten money is to invest it in land properties. We have been seeing that throughout the country a lot of valuable, prime properties are being purchased by some people in the name of somebody else. A lot of black money is invested in land properties. We can see a lot of land properties, which are fertile in nature, have been kept barren and vacant. The persons who invest their black money in these lands, they have not purchased for the purpose of agriculture. They have purchased these land properties for the purpose of making use of their ill-gotten money in those properties.

Sir, with utmost responsibility I would like to place on record that in our country, a lot of lands, which are vacant and barren, have been converted into banks of this black money.

I would like to give you one example. Suppose, there is a property worth Rs. 1 crore. Normally, the guidance value of this property would be about Rs. 10 lakh. People will purchase that property, which is worth Rs. 1 crore, for Rs. 10 lakh on paper by paying Rs. 1 crore. In that way, they will safely keep their ill-gotten Rs. 90 lakh in that vacant land. This ill-gotten money is being spread all over the country. This money is also not accountable. These are all white-collared offences. They are investing this black money for two purposes. One is to keep their black money safely on a vacant land and secondly they want to escape from the clutches of law. So, they will make use of this vacant land just to escape from the clutches of law and to keep their money safe. This law is not only detrimental to the economy of this country but it is also detrimental to the food production of this country. It is because these people do not want to make use of such lands for agricultural purposes. They will keep such lands vacant or barren. This is definitely a very good move. This legislation was brought forward by the UPA Government which is now being introduced by the NDA Government. We wholeheartedly support this Bill.

I have also suggested some preventive measures to prevent this black money being used by the people. Normally, in real estate, that is the legal term which the people have started using, there is a lot of black money transaction. I do not say that the entire real estate sector is clubbed with black money. But normally the people who have got a lot of black money, they invest this black money in real estate business. The real estate business means purchasing vacant lands.

We have got the Karnataka Land Reforms Act. That is prevailing in Karnataka. This has been done by the then Congress Government. There, a non-agriculturist or a company cannot purchase or own agricultural land. Section 17

(a) and (b) of the Karnataka Land Reforms Act prohibits any person, who is not an agriculturist, from purchasing agricultural land. That is the way by which we have prevented black money holders from investing this money in agricultural lands. Of course, such kind of laws may be there in some other parts of the country but ultimately, in that perspective, it is the responsibility of the Union Government to bring some stringent legislations to prevent the non-agriculturists, who have no intention of doing agriculture, by encroaching upon the agricultural properties.

Secondly, the Parliamentary Standing Committee has also suggested that the Aadhaar number, PAN and bank account number should be connected to every land transaction. If the Aadhaar number is linked; if the PAN is linked; if the bank account number is linked; and if more details are taken by the registering authorities about the purchaser then it will stop generation of black money. Above all, it is the responsibility of the respective Governments to find out the exact source of money that is going to be used in purchasing land. So, they should ascertain the source of money, not necessarily income. Then only, to some extent, they can prevent fictitious persons. Benami people can invest in agricultural lands. That is why, now the Government of India should bring some legislation with regard to that.

Secondly, how do you collect information about the benami transactions? There are people who are prepared to come and give information about these benami transactions. Benami transactions cannot take place without the knowledge of other individuals. Definitely people are prepared to come and inform the concerned authorities about these transactions. We can say that they are the whistle blowers. But, what is the law you have enacted in this Bill to protect the interest of the whistle blowers? Persons who want to disclose about the illegal transactions or benami transactions are neither protected, given protection here, nor any incentive is being announced. Why should he come and unnecessarily take risk by informing about the illegal transaction of somebody else? So, he should be protected.

In addition to that, some incentive should be given to him also. His identity and other things also may be safeguarded. Then only we can extract more information about the benami transactions.

Now, I would like to mention a few facts, give my individual view about some of the lacunas in the proposed Bill. You are right in saying that the offence committed under this Act is very serious. It is a white-collared offence. It is an offence against the State. You must be extra careful about the people who indulge in these activities. They are doing such activities at the cost of the future of this nation, at the cost of the economy of this nation. The sentence you have prescribed under Section 61 is from one year to seven years – not less than one year and it may go up to seven years. Rightly it is triable by a Sessions Court. But, you have stated that these offences are non-cognizable. I would like to know how an offence of serious nature, an offence which is liable to be tried by a Sessions Court, can be treated as a non-cognizable offence. The moment you say that it is a non-cognizable offence, it takes away the seriousness of this offence. Normally in the country what we feel is, an offence which is triable by a Sessions Court is a serious offence. That is why, that should be made a cognizable offence.

Here, in the appellate court, you have made a provision for right to representation. Principles of natural justice require and demand a person should be given some legal assistance. The same provision is not provided to that person before the adjudicating authority because adjudicating authority is the person who virtually goes to the very root of the case. He gives opportunity of hearing to the person. He records the evidence. He looks into the documents. He hears the arguments and then takes a decision. Virtually the trial will be conducted before the adjudicating authority. But, unfortunately, you have not provided for legal assistance to appear before the adjudicating authority; whereas, before the High Court, of course there is a provision in that regard. Before the appellate tribunal also, you have provided the legal representation. Before the High Court also, one

can definitely be represented by an advocate. But you have not mentioned anything about appearance before the adjudicating authority.

That is why, this is my request. Tomorrow, anything which we enact here will be subjected to scrutiny by the courts. Tomorrow, the courts should not say that an opportunity of hearing is not given, he has not been properly represented and he was not capable of defending his case, such things should not happen. That should not become a problem before any court. That is one thing.

Secondly, regarding these authorities, jurisdiction and procedural aspect appear to be too high, too heavy and too lengthy. You are creating four provisions at the initial stage i.e. initiating officer – one who initiates the cases. Then, why do you want this approving authority? He, as the initiating officer, is a right person who looks in detail about the benami transactions. He will have the first hand information about all these things. But you have also asked him to take approval from the approving authority. Then, there is an administrator. Even the initiating officer can also play the role of an administrator but still you have created one more post, the administrator who manages the land which was confiscated. Then, there is adjudicating authority. Of course, the adjudicating authority has got the original jurisdiction of trying the case and he is the person who declares about the benami transaction and he is the person who actually confiscates these illegal properties after having come to the conclusion that it is a benami transaction. That is one thing.

Secondly, you have provided a provision for this appellate tribunal. But in the appellate tribunal, what happens is that though the matter is being seriously adjudicated before the adjudicating authority, but once again you have made a provision for recording evidence, looking into the documents and verification of the documents. All these things will be done before the appellate tribunal. That is not required. The Appellate Tribunal should hear the appeal on the basis of the evidence which is available, on the basis of the evidence which has been recorded before the adjudicating authority. But you have a made provision to re-introduce

the case here also in the Appellate Tribunal. That means the original jurisdiction still exists before the Appellate Tribunal, which is not correct.

Once again the High Court is there. Naturally, these cases will be taken to the Supreme Court also. That will definitely help the people who indulge in these activities, because they can drag the case for years together. That is how, things are happening. In the Appellate Tribunal also, you have not fixed any time limit. You have used the words “may hear and decide within one year”. Naturally, you are a legal luminary and you know how these courts will use the word ‘may’. I think that will not solve the problem. The seriousness of the whole issue or the concern of the Government is to deal with these cases very stringently. I think that will be taken away the way in which the provision is being made to drag the case for years together. That should not happen.

Finally, before the High Court, it is right that the High Court deals with only the substantial question of law. That is okay. The High Court can hear if there is any error in the substantial question of law, then only they can hear and dispose of the case. I will read Section 49(7).

“The High Court may determine any issue which has not been determined by the Appellate Tribunal.”

Then, the Pandora’s box of litigation is opened. The High Court also, not necessarily on the substantial question of law but even on the facts also, can deal with it. That is once again a hindrance to the very purpose of this law.

So, finally, as I pointed out earlier, there are many flaws which have to be looked into, and by adding only one thing, I will conclude my speech. The Parliamentary Standing Committee has recommended about known source of income. That should not be there. It is only known sources. That should be there. It is because income means a person, who has got income, is different from a person who has got sources. Sources are different from sources of income. ‘Known sources’ are the right words. In spite of the recommendation of the

Parliamentary Standing Committee, that amendment has not been made. So, that is the right thing because income is different from sources. That is why, that should be seriously looked into.

With all these things, I fully support this Bill, and I express my sincere thanks for giving me the opportunity.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष जी, मैं, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 जो बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 1988 का संशोधन करने के लिए लाया गया है, इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी और अपने यशस्वी वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में पारदर्शिता और काले धन को रोकने के लिए एक नया इतिहास रचने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुझे याद आता है कि आदरणीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी ने अपने बजट भाषण, 2015 में कहा था कि जहां तक घरेलू काले धन पर रोकथाम का प्रश्न है, हम एक विस्तृत बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने उस दिन अपने भाषण में यह भी कहा था कि इस बिल के पास होने से हम बेनामी सम्पत्ति जब्त कर सकेंगे और दंडात्मक व्यवस्था द्वारा बेनामी सम्पत्ति, विशेषकर रीयल एस्टेट में जाने वाले धन पर रोकथाम लगा पाएंगे। उन्होंने अपने बजट

भाषण में जो कहा था, आज इस सदन के सामने उस प्रतिबद्धता को निभाने की दिशा में, इस बिल को प्रस्तुत करके, बहुत बड़ा इतिहास रचने की दिशा में काम किया है।

महोदय, वैसे देखा जाए तो लॉ कमीशन की जो 57वीं रिपोर्ट अगस्त, 1973 की है, उस रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि पूरे विश्व के मानस पटल पर इस तरीके का जो काला धन और भारत के प्रति जो उसकी छवि इस देश के लोगों को चिंतित करती थी, उस आधार पर यह रिपोर्ट आई थी, लेकिन वर्ष 1973 के बाद 1988 में राजीव गांधी जी के समय में यह अधिनियम लाया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि विश्व समुदाय और देश के जनमानस और भारत में फैले आर्थिक भ्रष्टाचार से चिंतित होने के बाद इसे दबाव में लाया गया था, लेकिन वह भी व्यावहारिक रूप में नहीं लाया गया था। इससे हमारे देश की सारे विश्व में साख गिर रही थी और हमारे देश में निवेश की संभावनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा था। आर्थिक सुधार और काले धन पर लगाम लगाने के लिए इस बिल को लाया तो गया, लेकिन आधा-अधूरा लाया गया। केवल 9 सैक्शन इसमें लाए गए। इसमें समुचित प्रावधानों की भारी कमी थी। उसमें बेनामी संव्यवहार को सही रूप से परिभाषित तक नहीं किया गया। दोषियों के खिलाफ सजा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसमें बहुत ज्यादा छूट दी गई थी। पारिवारिक सदस्यों के रूप में इसमें स्पष्टता नहीं थी। इसके लिए कौन अधिकारी सक्षम होगा, जो नोटिस देगा, इसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद निर्णय देगा और कौन-सा प्रशासनिक अधिकारी सम्पत्ति का अधिग्रहण करेगा या जब्त की गई सम्पत्ति का कौन प्रबंधन करेगा, इस तरीके का दूर-दूर तक कोई प्रावधान नहीं था। लोग इसमें प्रताड़ना से बचने के लिए कहां जाएंगे, इसके

लिए अपील करने का भी कोई सशक्त प्रावधान इसमें नहीं था। सिविल कोर्ट की सख्तियों की भी व्याख्या नहीं थी और उसके क्रियान्वयन के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

वर्ष 1988 से आश्चर्य का विषय यह है कि उस समय से लगातार इसमें कोई नियम नहीं बने। वर्ष 1988 से वर्ष 2011 में सरकार दोबारा इस बिल को लाई। जैसा वित्त मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, इसमें संशोधन की बजाय विभाग यह कहता था कि इसमें नियम नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि यह अधूरा एक्ट बना है। चाहिए तो यह था कि एक नया एक्ट बनाने की जगह उसी में संशोधन करते, लेकिन संशोधन करने के बजाय एक नया एक्ट लाया गया। नया एक्ट वर्ष 1988 के बिल की जगह लाया गया, इससे बहुत स्पष्ट स्थिति आज है। हमारे कांग्रेस के मित्र सदन में नहीं हैं, अगर वे यहां होते तो जवाब देते कि उनकी मंशा देश में काले धन को संरक्षित करने की रही है। उनकी मंशा काले धन को संचित करने वालों को प्रोत्साहन देने की रही है, अन्यथा वर्ष 1988 के बाद अगस्त 2011 को नया बिल प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि नया बिल प्रस्तुत करने से उनकी मंशा स्पष्ट हो गई थी कि जो बेनामी सम्पत्ति वाले लोग हैं, वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2011 तक उन्हें एकमुश्त छूट मिल जाएगी। उनकी मुक्तता के लिए यह नया बिल लाया गया था।

श्रीमन, वर्ष 2011 में प्रस्तुत बिल यशवंत सिन्हा जी की कमेटी को सौंपा गया। उस कमेटी ने भी तमाम संशोधन करके अपनी सहमति दी और वह भी जून 2012 में दे दी थी। खड़गे साहब सदन में आ गए हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि जून 2012 के बाद सदन के दो सत्र उसी साल होने थे। वर्ष 2013 के चार सत्र सरकार को मिलते थे। ऐसी कौन-सी विवशता थी कि उस समिति की संस्तुतियों को आपने पास नहीं किया, क्योंकि उनकी मंशा पास करने की नहीं थी इसलिए उसे वैसा ही रखा। पारदर्शिता नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था और कुछ लोगों को संरक्षण देने की स्पष्ट मंशा थी, अन्यथा यह बिल पास हो गया होता। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी, जनता के प्रति जवाबदेही, जिम्मेदार कार्यशैली तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना को साकार करने की मंशा से 28 वर्ष लंबित पड़े इस बिल में संशोधन करने का निर्णय लिया और आज हम इस पर चर्चा करने के लिए यहां खड़े हैं।

15.00 hours

इस बिल में जो प्रावधान हैं, निश्चित रूप से जो कालाधन कमाने वाले हैं और देश को लूटने वाले हैं, पर शिकंजा कसने के लिए और उनको इस कानून के अंदर लाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है, जो अपने आप में सशक्त है। मेरे एक साथी अभी चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि वे इस कानून की एक-एक धारा को वे पढ़ेंगे, तो वे इस बात से सहमत होंगे कि इससे सशक्त कौन-सा कानून लाया जा सकता

है। इस संशोधन बिल को यदि देखा जाए, तो इसकी जो मूल धारा-दो के स्थान पर, जिसमें यह कहा गया था कि संव्यवहार की परिभाषा ही नहीं थी, बेनामी संव्यवहार की परिभाषा नहीं थी।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल की अध्याय 1 में (9)(अ) (क) में है, उसमें बेनामी संव्यवहार को परिभाषित किया गया है, वह बहुत ही साफ तरीके से इस ऐक्ट में आता है। नम्बर एक-

"बेनामी संव्यवहार" से-

(अ) कोई ऐसा संव्यवहार या ठहराव अभिप्रेत है,-

(क) जहाँ किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जाता है या यह उसके द्वारा धारित की जाती है और उस संपत्ति के लिए प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया गया है या संदत्त किया गया है; और

(ख) जहाँ संपत्ति को, उस व्यक्ति के, जो प्रतिफल उपलब्ध कराता है, तुरंत या भावी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, फायदे के लिए धारण किया जाता है,

नम्बर दो-

किसी संपत्ति के संबंध में किसी कल्पित नाम से किया गया कोई संव्यवहार या ठहराव अभिप्रेत है;

जिस पर आप अभी चर्चा कर रहे थे। तीसरा, स्पष्ट परिभाषा है कि-

ऐसा कोई संव्यवहार या ठहराव, जहाँ सम्पत्ति के स्वामी को ऐसे स्वामित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है या वह ऐसे स्वामित्व की जानकारी होने से इंकार करता है।

चौथा, इसमें बहुत ही स्पष्ट परिभाषित किया गया है कि-

ऐसा कोई संव्यवहार या ठहराव, जहाँ प्रतिफल उपलब्ध कराने कराने वाले व्यक्ति का पता नहीं लग सकता है या वह कल्पित व्यक्ति है।

श्रीमन्, जहाँ इसे स्पष्ट किया गया है कि ये बेनामी संपत्ति कौन-सी होगी, वहीं दूसरी ओर यह भी किया गया है, जिस पर बहुत विवाद हो रहा था कि पारिवारिक सम्पत्ति होगी, इस दिशा में परिवार के लोगों की, कुटुंब की, भारत की पारिवारिक संरचना पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं।

इसमें बहुत साफ कहा गया है कि बेनामी संव्यवहार की परिभाषा से अपवर्जित सम्पत्तियां इस प्रकार जो चिन्हित की गयी हैं, वह क्या हैं। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्तियां, जो किसी अविभक्त कुटुम्ब में किसी सहर्दिक द्वारा धारित की जाती हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति या वैश्विक हैसियत में धारित सम्पत्तियां। तीसरा, किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी के नाम या ऐसे व्यक्ति की किसी संतान के नाम से आय के ज्ञात स्रोतों से अर्जित सम्पत्तियां और किसी व्यक्ति द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से भाई या बहन या पारिवारिक पूर्व पुरुष या वंशज के नाम से संयुक्त स्वामित्व में अर्जित सम्पत्तियां। बहुत

साफ कहा गया है कि जो बेनामी होंगे, वह कौन होंगे और जिन पर यह एक्ट लागू नहीं होगा, वह कौन होगा?

श्रीमन्, मैं यह समझता हूँ कि श्री यशवंत सिन्हा की कमेटी ने भी यह महसूस किया था कि वर्ष 1988 का जो बिल था, वह इस दिशा में पूरी तरह से असफल रहा है, इसलिए इस बिल को बहुत अच्छे तरीके से लाया गया है। अभी जो चर्चा की गई कि इसमें किस-किस तरह से किया गया, प्रारंभिक अथोरिटी किया गया, अनुमोदित अधिकारी सुनिश्चित किया गया, प्रशासनिक अथोरिटी सुनिश्चित की गयी, निर्णय देने वाली अथोरिटी सुनिश्चित की गयी। चार स्तम्भों पर तंत्र की स्थापना की गयी, क्योंकि उस कमेटी ने भी यह कहा था कि इस तरीके का कोई तंत्र इस एक्ट में नहीं है, जो लोगों को सुने और उसको सुनिश्चित करे।

मैं यह समझता हूँ कि जिस तरीके से धारा-2 में प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई का है, उस बिल में कहीं भी दूर-दूर तक इसकी स्पष्टता नहीं थी। पुराने एक्ट में तीन साल की जो सजा थी, वर्तमान में उसको भी संशोधित किया गया है और उसमें एक साल से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, सम्पत्ति का जो बाजारी मूल्य होगा, उस पर 25 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है। कोई बेनामी सम्पत्ति को अर्जित करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यदि कोई गलत सूचना देता है तो उसमें क्या प्रावधान हैं। गलत सूचना देने पर छः माह से पांच साल तक की न केवल सजा है, बल्कि सम्पूर्ण सम्पत्ति का बाजारी मूल्यांकन होगा और उसका दस प्रतिशत उस पर अर्थदण्ड लगेगा। इस संशोधन एक्ट में सक्षम अधिकारियों को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जब्त की गयी सम्पत्ति का प्रबंधन और केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था है। पहले यह सब नहीं था कि कौन उसको जब्त करेगा, यदि जब्त करेगा तो वह भारत सरकार में निहित होगी या राज्य सरकार में होगी या किसी संस्था में होगी। यदि होगी तो उसका संचालन कौन करेगा, प्रबंधन कौन करेगा, यह सब उसमें नहीं था। अब इसमें बहुत ही स्पष्ट व्यवस्था है। अपीलीय कोर्ट की व्यवस्था है। संसदीय वित्त समिति ने जिस बात को महसूस किया था कि यदि लोग परेशान होते हैं कि वह कहां अपील करेंगे तो इसमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया है और अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी को लगता है कि वहां उसको ठीक से नहीं सुना गया है तो वह क्षेत्रीय हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है।

इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी पारदर्शिता और जवाबदेही में विश्व स्तर पर इस कानून को लाए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इससे काले धन पर प्रतिबंध लगेगा। जो लोग काले धन के माध्यम

से बेनामी सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, उनकी मंशा पर गहरी चोट होगी। यही कारण है कि हमारी सरकार की विश्व स्तर पर विश्वसनीयता बढ़ी है और उसी का परिणाम है कि आज एफडीआई में पूरी दुनिया में भारत नंबर-1 पर है। आज भारत में 63 अरब डॉलर एफडीआई निवेश हो रहा है, वहीं अमेरिका में 59 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। हमने अमेरिका को भी एफडीआई निवेश में पीछे छोड़ दिया है। यह हमारी सरकार की विश्वसनीयता है।

आज इसी भाव से कि जब यह बिल आज पास होगा तो हिन्दुस्तान में एक नई करवट होगी, एक नया इतिहास होगा। बेईमानी और भ्रष्टाचार दूर-दूर तक कोई करने का साहस नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने वित्त मंत्री जी, अपने प्रधान मंत्री जी और सरकार को बहुत सारी बधाई देता हूँ कि जिस चीज की संकल्पना उन्होंने की थी, आज उस कानून को लाकर देश के सामने प्रस्तुत किया है और इसमें पारदर्शिता लाकर हिन्दुस्तान को सशक्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी की स्थापना हुई है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I wish to express my sincere thanks and gratitude to our beloved leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma for giving this opportunity. Our Amma is taking charge as a Chief Minister of Tamil Nadu for the sixth time and in the second consecutive time. She is a people's leader. That is why, we often say her "Our Amma" for giving this opportunity to speak on the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015.

The Bill seeks to amend the Benami Transactions Act, 1988. The Act prohibits benami transactions and provides for confiscating benami properties.

The Bill seeks to amend the definition of benami transactions; establish adjudicating authorities and an Appellate Tribunal to deal with benami transactions; and specify the penalty for entering into benami transactions.

The Bill amends this definition to add other transactions which qualify as benami, such as property transactions where the transaction is made in a fictitious name. The owner is not aware of it or denies knowledge of the ownership of the property or the person providing the consideration for the property is not traceable.

The Bill also specifies certain cases which will be exempted from the definition of a benami transaction. These include cases when a property is held by a member of a Hindu undivided family, and is being held for his or another family member's benefit, and has been provided for or paid off from sources of that family; a person in a fiduciary capacity; a person in the name of his spouse or child and the property has been paid for from them person's income.

The Standing Committee on Finance after examining the written submissions and hearing the views of the Ministry, institutions, experts and State Governments on the Bill find that there are key issues, concern areas and certain operational difficulties which are required to be squarely addressed before the Bill is enacted.

In the exception to benami transaction as laid down in Section 2(1) of the Principal Act -- (Section 4(9)(i), (iii) and (iv) of the proposed Bill, -- the

expression “out of known sources of income” should be replaced by “out of known sources” so as to bring clarity in cases where loan funds which are not income, are used as consideration for purchase of a property and not be kept out of the purview of the Bill. Further, the words ‘and legal’ may also be inserted after ‘known’ so as to safeguard genuine and *bona fide* transactions. The Government has accepted this recommendation of the Committee.

It has to be ensured that any *bona fide* transaction should not be deemed as ‘benami’, when it involves transfer of immoveable property entered into under (i) a registered agreement to sale (ii) a registered irrevocable General Power of Attorney (GPA), and (iii) a registered Development Agreement on payment of stamp duty in accordance with law applicable thereto.

According to this Bill, a benami property shall not be re-transferred by the *benamidar*, a person who is holding the property to the beneficial owner, who provided the consideration for the transaction or any person representing him. If the benami property is re-transferred, it is considered void. However, in the Amendment Bill, it is said that, if the benami property is disclosed as part of the income disclosure scheme of the Finance Act, 2016, then the corresponding provisions of the Bill will not be applicable.

In a federal set-up like India where land is a State subject, it would be deemed appropriate that the rights of confiscated benami properties vest with State Governments instead of the Central Government has recommended to the Government to re-examine this aspect in the light of the Constitutional provisions.

The Bill seeks to establish four authorities to conduct inquiries or investigations regarding benami transactions: (i) Initiating Officer, (ii) Approving Authority, (iii) Administrator and (iv) Adjudicating Authority.

The Standing Committee has observed that it should be ensured that the provisions of the Bill are not in conflict with the provisions of the existing Tribal Land Acts administered by States in Tribal Areas and Scheduled Areas specified under the Constitution. Ground realities in these specified areas should thus be

considered and duly factored in. The amendment Bill is likely to have very serious impact in rural areas, where because of large number of cash transactions and poor state of land records, even genuine land owners may find it difficult to establish their titles records being non-traceable. As a precaution, therefore, a thorough and serious inquiry by the Initiating Officer becomes essential before the matter goes to the Adjudicating Authority. The time taken for such inquiry should, therefore, be extended from the proposed period of thirty days to thirty months. This would give the affected person adequate time to prove that she/he is the genuine owner of the property in question. I hope this recommendation by the Standing Committee has been incorporated in the Amendment Bill.

The Bill seeks to change the penalty to rigorous imprisonment of one year upto seven years, and a fine which may extend to 25 per cent of the fair market value of the benami property. Certain sessions courts would be designated as Special Courts for trying any offences which are punishable under the Bill.

Time limit for disposing of the appeal by an Appellate Tribunal, say within 2 years from the date of filing of the appeal, should be fixed in the Bill. Any increase in this period should be an exception, made only at the instance of the High Court on an application made by the Tribunal.

The Standing Committee has observed that the provisions of the proposed Bill are silent on the extra territoriality, where the transacting persons standing in fiduciary capacity, benamidar, beneficial owner or the property are situated or located abroad. Similarly, the provisions are also silent on the role of whistle-blowers and their protection, which would be important to detect benami holdings. Adequate provisions in this regard should be incorporated in the Bill.

In the proposed Bill, the appointment of the Adjudicating Authority has been prescribed in clause 9; however, no such mechanism has been provided for appointment of the Initiating Officer and the Approving Authority. The proposed Bill may therefore be restructured by inserting a Chapter on Authorities on the lines of Income Tax Act, wherein Chapter XIII provides for appointment and

control, jurisdiction and power of such Authorities so as to have greater clarity and avoid legal hassles.

In clause 32, for qualification for appointment of Chairperson of the Appellate Tribunal, “experience as a High Court Judge for a period of at least five years” may be inserted with a view to having the services of experienced judges. This has been accepted and incorporated in this amendment Bill.

A provision is needed to be inserted in the proposed Bill for right to representation for a person preferring an appeal before the Adjudicating Authority as provided under clause 48 of the Bill for preferring an appeal to the Appellate Tribunal.

The crux of the whole problem of *benami* transactions lies in transactions being recorded in the names of persons who are not the beneficial owners. To preempt and eliminate this, the Committee has desired that certain consequential amendments in the Transfer of Property Act, 1881 and Registration Act, 1908 should be made, particularly making mandatory online registration of all immovable properties, linkage of Aadhar number and PAN number of all the parties to the transaction and sharing of data by the Registration Authorities with the Central agencies like Income Tax Department.

Stress should be laid on digitalisation of land record and its regular updation. Efforts should be made to deal with the problem systematically to the extent possible without needless discretionary intrusions. There should be complete co-ordination and intelligence sharing between different agencies such as Income Tax, Excise, Customs, Police, Banks, Stock Exchanges, Regulators such as SEBI and RBI, and investigative agencies such as CBI, ED, and SFIO. This aspect should be adequately reflected in the Bill.

The Committee was of the view that this Bill should not become another coercive instrument in the hands of the Central Revenue Department to forcibly collect or mobilise taxes, as the existing Income Tax Act had adequate provisions and teeth to deal with issues such as tax evasion and unaccounted income or

wealth. The Committee believed that multiplicity of authorities should not be created and the existing set up could be utilised for this purpose. The need of the hour is to exercise the existing powers judiciously and in a credible manner.

The Finance Minister in his Budget Speech 2015 had stated the purpose of the Bill was to curb the generation of domestic black money. However, the Standing Committee found that the Statement of Objects and Reasons of the Bill was silent over that significant aspect. The intent of the Government should therefore be clearly mentioned in the Statement of Objects and Reasons of the Bill. It is also necessary that prevention of corruption and tracking of tainted money are also added as supplementary objects of the Bill.

With these words, I conclude my speech. Thank you for the opportunity.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker Sir, the Bill which has come up is the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill. In clause 3, you say, "This Act may be called the prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988." This is what you want to do. Why are you not bringing in a new Bill? Why have you brought this amendment Bill? If the title of the Bill goes, like the 'Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988' why are you amending a Bill titled Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, which is further to amend the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988? You are trying to bring new things into the old Act. If that is so, why are you not replacing it with a completely new Act itself. Through you I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister. It is also a great privilege to have the hon. Law Minister here. It is all the time my privilege whenever both of them are in the House.

The Standing Committee of Finance in Part-II of its 28th Report had exactly recommended for bringing a new Bill itself. There is a total change of characters. What is the requirement of it? Let us see the object behind it. We have heard the speech of the hon. Finance Minister in 2015 regarding stopping of black money. The main thrust was whether these transactions are made through a backdoor process or through the black money. Today, if I have white money and if I transfer a property to anyone, it is not benami. Benami is having the money whose source has not been disclosed and cannot be disclosed because it is earned out of illegal activities. The property purchased out of such transactions is called in different names and it is called benami. I have a little experience about that.

In 1989 I purchased a second-hand car. The car was given to me but the owner said that he would give the documents etc. after a few days. I believed him for that. For two years I was not given those documents and in 1991 that car was stolen by someone. In the competent court naturally the owner has to apply for seized car. I had to take the help of the Police Commissioner. Ultimately it was found that the gentleman who was owner of the car was staying in a remote

village of Bihar. He was the owner's domestic servant. This is the example of a benami property and this has to be stopped.

I now come to Clause 9 of the Bill. It says:

“ (a) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman or a member of the Adjudicating Authority unless he has been a member of the Indian Revenue Service and has held the post of Commissioner of Income-tax or equivalent post in that Service;

The Chairperson or other Members of the Adjudicating Authority shall be appointed by the Central Government.

The Central Government shall appoint the senior-most Member to be the Chairperson of the Adjudicating Authority.”

How can you distinguish the seniority? Seniority can be distinguished within the same cadre. How can you distinguish between the seniority of an income tax officer and a district judge?

As regards income tax tribunal matters, constitutional bench judgement on Chennai matter, you know that if the power is not vested where the judicial officer is and it is given to the administrative officer, then it would be *ultra vires*. One has to ensure who the Chairman would be. When a person from judiciary is there, maybe of district level, then why are you going for an administrative officer?

I would like to know as to why the Department of Revenue is included everywhere. The Income Tax Officer will run after the persons. In our country, they are the most failed persons. Only three per cent people pay income tax in our country. The Income Tax Officer will run after those who are paying income tax. Those who are not paying tax, they will never touch them. If I have to pay advance tax and if I remain in Parliament continuously for three months, then I would get a notice as to why the advance tax is less. But those who are not paying taxes at all, they are never caught by the Income Tax Officers. This is the situation. I would say that instead of Revenue Officers, it should be somebody else

because income tax is not the main question here. The question of property is here.

Under clause 30, you have created an appellate tribunal to hear such appeals. With great respect, I would like to ask where the provision for preferring an appeal is. First, there must be a provision to prefer an appeal. If an appeal is preferred, in how many days it should be preferred. The Bill is silent on that. This provision cannot be made in the rules but it has to be made in the statute itself. If an order is passed by the Adjudicating Authority, kindly consider giving power to the Appellate Tribunal to pass an interlocutory order. Otherwise, everything would be frustrated. Ultimately, when the final appeal would be heard by the High Court, then everything would go. A person should be given justice. One can see that it is benami and one may not see that it is benami. One may suffer from victimisation also. Therefore, this power should be given and certain protection should be given against the order itself. Clause 30 says that the Central Government shall by notification establish an Appellate Tribunal to hear appeals but where is the provision that there is a right of appeal against an order of the Adjudicating Authority.

Then time limit is not there but in the case of the High Court appeal, there is a time limit of 60 days. I will request that in the Bill itself you give the power to the Appellate Authority to pass an interlocutory order.

Sir, the Parliamentary Standing Committee on Finance has submitted a Report in which they have highlighted a ground reality. The ground reality is that in the rural areas lands are purchased in cash and it is being done for decades together. In the rural areas and in case of illiterate persons it is very difficult to find the land deeds etc. So far as the rural areas are concerned, the poor people are concerned, those who have purchased the property, in their cases if the deeds are not available, then care should be taken to see that those properties are not brought within the scope and ambit of this Act. Therefore, I would like to request the hon. Finance Minister to give thrust on the aspect whether the property is purchased or

acquired by reason of any undisclosed money or tainted money. Apart from that, if the property is not bought by tainted money, or money from undisclosed sources, then those properties should not be brought within the scope and ambit of this Act.

Sir, I must say that a number of mechanisms have been created in this Bill. But I would like the hon. Finance Minister to have a re-think on this. I can make a request to him. The hon. Finance Minister has given a completely new thought which I appreciate excepting certain points which I have already pointed out. I appreciate the intention of this Bill. I appreciate the mechanisms that you have created through this Bill. I have no doubt that that. But since he has given a new thought over the entire thing, it is better to bring in a completely new code itself giving details of everything.

Sir, with these words, I conclude.

Thank you.

SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I rise to speak on the Benami Transactions Prohibition (Amendment) Bill, 2015.

The Bill has been brought in to curb the nuisance of illegal transactions that have been plaguing our country. We are all aware that most of the black money generated domestically is due to property dealings and similar such real estate transactions. This Bill deals with it and adds the provision of penalizing those who indulge in such unlawful activities.

Culturally Indians accept what you term as “Benami” now as part of their normal lives. From the days of Zamindars, transactions concerning land holdings have always been executed in the names of different beneficiaries who may or may not be related to the primary money spender.

Sadly, this Bill does not take into account such different cultural compulsions existing in different parts of the country. For example, India has both Matriarchal and Patriarchal norms and fashion of land holdings and they greatly vary in such areas.

This Bill seems to be prepared hurriedly and by someone who does not have a thorough understanding about the culture relating to land ownership in the countryside. For instance, the Indian Judiciary is burdened with excessive number of civil cases which are way above 70 per cent of total litigations in courts that relate to land dispute and ownership. Similarly, a majority of convicts are sentenced to life imprisonment and probably all prisoners across India are implicated in crimes committed to possession of land.

There are a few observations that I have to make regarding this Bill.

I strongly object to Section 8 of the Bill. This Bill has the provision to seize benami property and hand it over to the Central Government. This is against the core spirit of federalism since land is a State subject.

Sir, I want to draw your attention that this Government has been making points in favour of cooperative federalism as *Mantra* for development. Hence, I

want the hon. Minister to give a clarification to this august House. Why this provision has been put in and what is the rationale behind this provision?

Further Section 4, clause 9, changes the very definition of benami transactions. It now seeks to make property which is registered under the name of person 'A' but consideration paid by person 'B' as 'benami'. I would like to thank the Government for taking into consideration the suggestions of the Committee and adding 'family members' as exceptions.

However, there is a small flaw here. In exceptions, you have included spouse and children as exceptions for such illegal transactions. I would suggest adding 'daughter-in-law' and 'son-in-law' as well. This should be allowed.

The Standing Committee has given its Report and this Bill reflects a lot of changes that were suggested. But there are still questions regarding whether or not we need a new Bill for dealing with benami transactions.

I would like to have a clarification from the Minister on whether passing this Bill would lead to conflict with the Income Tax Act, 1961 and his thoughts on why these provisions cannot be simply included in the Income Tax Act itself.

Sir, I would like to conclude by reminding the assurance given by the Government in bringing back black money from abroad and stop such benami transactions domestically as well. Just to cite one example, as of 20th August, 2016, under *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana*, more than Rs. 40,000 crore has been deposited. We feel proud of it. However, after cases like Malya, we are suspicious that these deposited money, as savings of the poor and sundry, may be cheated by these shrewd and fraudulent ones. Are we not giving scope to produce crores of benami transactors? It is because close to six crore accounts have zero balance out of 22.6 crore accounts opened so far.

Hence, my Party feels that this is an incomplete and haphazard Bill which needs to be relooked even though the Standing Committee has already scrutinized it. I believe that this is a delicate subject which needs further thought.

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on a very important and crucial financial piece of legislation which is to curb black money.

I congratulate the hon. Finance Minister especially for bringing about this Bill.

Sir, this Act has been in vogue since 1988, and since then the parent Act has been enacted. After that, this is the amendment to that Act in 2016. I would like to ask the hon. Finance Minister as to what has happened in between. Has the parent Act been able to hook any of the benami transactions? Could you catch hold of any of the benami transactions or benamdaries? Have any such people been caught? Particularly this year, one Income Declaration Scheme has been launched. Under that Scheme, 45 per cent of the property value can be declared and 45 per cent of the tax can be paid and the property can be re-transferred to the benamidar. So, that was the provision made in that Declaration Scheme. I feel that if the Bill is brought when that Declaration Scheme is in vogue, then it will contradict each other. It will create confusion whether that will gain precedence over this or this will prevail upon that. I have no idea about that. The Finance Minister may kindly like to clarify that.

They have, for the first time, appointed Initiating Officer, Approving Authority, Adjudicating Authority and Appellate Tribunal. These four officers are there. All of them are drawn from Income Tax Department. This Bill is talking about benami property. Benami property includes movable, immovable, tangible and intangible. We can understand immovable property. It is like land, etc. We can understand movable property, which are goods and other things. We can understand intangible, which are services, etc. How can the Income Tax officers catch hold of those hawala transactions? How will they have control over the black money which is going out of the country? I have a doubt over this.

Income Tax Department alone cannot deal with this. There may be so many Acts to deal with such actions, like hawala, etc. The NDPS Act is there; the

Enforcement Directorate is there; and the PMLA is there to deal with such a situation. Actually there is a joke, India's benami is Switzerland, and Switzerland is a benami for India. All accumulated money, ill-gotten wealth, from India is being deposited in Switzerland.

स्विटजरलैंड इंडिया के लिए बेनामी है, सैल कंपनी होता है, कुछ कंपनी इसलिए खोला जाता है कि यहां से पैसा निकाल कर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जरिए पैसे का रिसाइक्लाइजेशन होता है। इसे हवाला ट्रांजैक्शन को भी इसमें लागू करना चाहिए था। टांजिबल और इनटांजिबल में कवर करना चाहिए था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हवाला ट्रांजैक्शन कन्फिक्सेशन करता है उसके साथ इसे जोड़ना चाहिए था।

The Customs and Excise Department which is there to see the over invoicing of exports and under invoicing of imports, through which money gets circulated through various means, should also have been integrated so that the black money menace is tackled and the progenitor of the black money, from where the black money is generated can be curbed. We can curb it at the root level.

As our Prime Minister always says, for any country to progress economically or socially, character is more important. The national character is more important. The people who are embezzling the money, who do illegal transactions in a benami way – pseudonymous, anonymous – are nothing but unpatriots. They are actually traitors of the country. They are anti-nationals and they should be hanged to death because they are causing a lot of damage to the country and they are causing damage to the country's reputation also.

Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, always says a country cannot progress without character. These money transactions which are happening illegally reflects how much of bad characters we have. Just imagine the kind of money that is embezzled. It is estimated that every year almost Rs. 20 lakh crore, which we generate as direct taxes, indirect taxes, State taxes, etc., is being embezzled. These are unofficial estimates. The Finance Minister is more well versed with all these things. He must be knowing about it better than me.

So, what I feel is that this Bill is well intended. But what I feel is that this should be integrated with the hawala, customs, drugs, etc. There is another Act,

NDPS Act which deals with drugs. That is the root through which money comes out of illegal trading of drugs.

All these things put together, the Bill should have an integrated approach, an integrated law to deal with the menace of black money of the country, which is afflicting the country. We should take all these Acts together, and make a comprehensive law to stop black money once and for all. *Jai Hindi and Jai Telugu Desam*, Sir.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Deputy Speaker, Sir, I rise to speak on the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015. The very name of the Bill is 'Benami Transactions'. On behalf of CPI(M), we want that benami transactions in the case of property should be totally stopped in our country. This type of law was there earlier. Now, our Government is interested to bring some amendments in the Act but still we are thinking that some loopholes are there in the Act. Hence, we strongly demand that benami transactions should be stopped in the real sense of the term in our country.

For that, the Standing Committee on Finance has recommended some amendments. Their thinking, suggestions and recommendations on the Bill to some extent is related to our thinking. If we go through the intention of the Bill, we can find firstly, the definition of 'benami transactions'; secondly, it is trying to establish adjudicating authorities and appellate tribunals to deal with benami transactions; and thirdly, specifying the penalties for entering into benami transactions. All these three intentions are good. If we look at the Income Tax Act, 1961, there are adequate provisions to deal with issues of tax evasion. Persons who are engaged in benami transactions are those who wanted to hide their income, not to pay taxes to the Exchequer of the country. This has been provided in the Income Tax Act, 1961. Why should we have another law? These loopholes should be plugged. There is some problem in the amendment. Sometimes an individual can purchase the land for the sake of the family and he may sincerely, honestly gift it to other persons. In that case, what would happen has not described in the amendment? This loophole should be plugged.

Sir, it is stated here that the confiscated properties will be vested with the Central Government. But in our Constitution, land is a State subject. So, the property which will be confiscated should not go to the Centre, but that should go to the concerned State Government. This should be included in the amendment.

Then, for initiating and completion of the cases, there should be a fixed time limit. Otherwise, the relation between the authority and the person who does

the benami transaction would not serve the purpose of this Bill, but it would serve the purpose of the person who does the benami transaction. So, a specific time limit should be there by which time the case should be concluded.

Sir, for furnishing information about land, only 30 days time has been given. I think this time for furnishing information can be extended so that it would help the people who are inclined to do this.

Then, in the era of digitalisation, it should be integrated with *Aadhaar* or PAN Card and through this, we can stop benami transactions. So, digitalisation should be included in the amendment.

Sir, why are benami transactions going on in our country? It is stated that Rs. 8.5 lakh crore of black money is there both inside and outside our country. Benami transactions are taking place only to create black money, to keep the black money, for political purposes and also for creating election fund of political parties. These days, our political leaders are also involved in benami transactions in our country. If the political parties and political leaders keep away from benami transactions and not use black money for political purposes, then only benami transactions can be stopped in this country. We hope that this Bill becomes a very strong law which can stop benami transactions in the true sense of the term.

With these words, I conclude.

16.00 hours

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for the opportunity.

Sir, the amendment proposed brings about comprehensive changes in the Benami Transaction (Prohibition) Act, 1988. Essentially, I think, it expands the definition of benami transactions, establishes an Adjudicating Authority and an Appellate Tribunal. It also increases the penalty for those indulging in benami transactions. So, effectively it casts a larger net, it creates an Appellate Authority and has a bigger sword hanging on the heads of those indulging in benami transactions. So, we welcome this step and, on behalf of the *Telangana Rashtra Samiti* we support this Bill.

However, I think this is one subject in which I and my fellow MPs from the *Telangana Rashtra Samiti* can proudly say that we are not experts in this subject.

Last evening, when we were discussing this subject, we were trying to find out what is the English equivalent of this benami transaction. We could not find an English equivalent. So, we concluded, may be this is something unique and prevalent more in India than in any other country.

I was wondering why the benami transactions are so prevalent. I think, it is obvious that one is to hide wealth earned from undisclosed sources or to circumvent certain land ceiling laws. I have exhausted my ceiling, so I will buy in a benami name.

In Karnataka, especially, hon. MP, Shri Muddahanume Gowda mentioned that certain agricultural lands can only be bought by farmers. So, if I am a trader and not a farmer, I circumvented by buying on a poor farmer's name. It is also to bypass some conflict of interest cases. For example, a State Government land allocated for an industry, if I am the allocating officer, I will allocate it to my family members through a benami name. It is also to hide our previous defaults and previous criminal transactions. We hear about chit fund frauds and others. He

does a chit fund fraud in this city. He changes his name and the name of his company and does a chit fund fraud in some other city.

We were also curious what aids or what facilitates benami transactions. I think, Ravindra Babu *garu* had mentioned this, the hon. MP from Andhra Pradesh, it is not just benami, it is facilitated by something else. Of course, it is the black money, it is hawala and yes, certain loopholes in Stamps and Registration Act wherein we can actually buy an expensive property without actually paying the consideration. The buyer will write a cheque, the seller will take the cheque and it will be in sale deed but the cheque will never be encashed. It would not be submitted and never be encashed.

There is also a big difference between the actual value and the Government official prices. But most importantly, I think, some of the ID standards – it is very good that for persons we do have Aadhaar Card – but how do we identify properties? We do not have good identification and valuation of properties and entities. They are not only bought by individuals but they are also bought by benami companies. I think, these are very essential things.

So, by this Act alone, however well it is implemented, I do not think, we can eliminate benami transactions. We need a gamut of reforms and we need those that will eliminate these factors that will aid and facilitate benami transactions. I am glad the Finance Minister and the Government has taken this into cognizance and the Government is simultaneously taking a series of systematic steps and reforms. What are these steps? It is not just this Bill in isolation. It is so many other Bills, the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) Act, the Aadhaar Bill, amendments to the Prevention of Money Laundering Act and the Income Declaration Scheme which is recently launched. All these, in conjunction with this, I think, can be a tough measure against prevention of benami transactions. I wish the Government well in this endeavour.

I discovered one unique thing. Everywhere benami transactions are defined as predicate offences, which proceeds from other criminal activities, is used for benami transactions. So, benami transactions are usually the result of other larger criminal offences like smuggling, trafficking or may be corruption and racketeering and so on. But not all benami transactions are predicate offences. There is a whole clause of benami transactions where the benami transaction itself is a primary crime. For example, the Government allocates a land to a particular industry and the allocating authority gives it to his own family through a benami name. So, benami transaction is used to hide black money generally but in this case it is used to create illegal wealth. So, we have to distinguish these benami transactions as predicate offences and benami transactions as primary crimes.

This also brings us to a yet another very important issue. I think the Standing Committee also mentioned this. If a State Government land is allotted to an ineligible beneficiary through a benami transaction, as in many cases, then can it be confiscated by the Central Government or should it go back to the State Government? To complicate the matters further, if the benami transaction is under investigation and it is being heard by the appellate authority and, at the same time, a GO allocating this land is cancelled, by cancelling the GO, it will go to the State Government. But the verdict of the appellate authority would be that it will go to the Central Government. It creates a legal ambiguity and a potential Centre-State conflict.

The Standing Committee report also touches on this subject without mentioning what land. I submitted an amendment. In benami transactions, where it is predicate offence, the land should go to the Central Government. Benami transactions where the State Government land was illegally allocated to somebody, to favour somebody, then it should go back to the State Government. I think that is fair because in the first case I agree with the Finance Minister because a lot of time it is an income tax evasion. If it is an income tax evasion and the benami transaction is caught, then it should go to the Central Government. If it is

corruption at the Central Government, then, I think, the land in the benami transaction should go back to the Central Government.

As in the case of IMG-Barath – that is in Hyderabad in my constituency – 850 acres of land was allocated at Rs. 50,000 at throwaway price to some beneficiary. I think, there is a stay order; I do not know the current State. But, should this land be declared as a benami transaction? Why should the State of Telangana land go to the Central Government? It should go back to the State of Telangana.

There are so many such cases. It affects not only the State of Telangana, it affects all the States. But, here, it is much more because in Hyderabad there are much more Government lands. There are seven lakh acres of Government lands much more than Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai put together. This is because of historic reason. The district surrounding Hyderabad city is called the *Atraf-I-Balda* district. It is also called *Sarf-e-Khas* land which is the private property of the Nizam. After Independence, this land vested with the then State of Hyderabad and later it was vesting with the State of Andhra Pradesh and now with the State of Telangana. What started as seven lakh acres, now when the State of Telangana is formed, we hardly have less than one lakh acres. Where did the six lakh acres go? We believe, it is through benami transactions and wrongly allocations by the previous Governments to ineligible people. If this land is declared benami land, it should come back. I think, this is one of the reasons. There is another reason. We are having protest by the lawyers for a separate High Court. I think, they are attributing this reason as to why Andhra Government does not want a separate High Court. It is because, which Government will want a High Court in the neighbour State? Will it benefit the poor people to cross the border and go to the neighbouring State? Everybody would want the High Court in the same State. This is one of the reasons that Andhra Pradesh Government probably does not want it. Only a few rich people

want the High Court in Andhra Pradesh to protect their illegal and benami lands. The Government needs to look into this.

One more area which is very susceptible to benami transactions is repatriated land. Another area is directors of infrastructure companies and directors of steel plants. The real owners are somebody. The director is his cook and his driver. They have taken huge loans from the banks and the defaulters are not the real owners. It is the cooks and the drivers. So, I think, this is one more area we need to look into. Some of these are not predicate crimes. So, we need to distinguish them separately and take actions against the real owners; 90 per cent of the shareholding belongs to the families.

We also need to take cognisance of the Standing Committee Report saying that the investigation by the initiating officer should be completed within a specific time frame. It is better if time frame is mentioned.

Then, how do we detect benami transactions? The Income Tax Department is doing a great job. Income tax collections have gone up this year and year after year. They are using information technology. However, information technology has some problems when applied to detecting benami transactions.

We have Aadhar card and PAN card. That is good. The computers can detect it but the computers do not know that in survey number so and so, the land is Rs. 50,000 or Rs. 50 crore per acre. So, land identification, land valuation and location codes should be there. Many countries have location codes. Our country does not have this code. So, standardisation of information relating to land deeds is to be done. Many members have also mentioned about the digitization of land records. Thank you for the opportunity. I have given an amendment. I would request the hon. Minister to consider my amendment.

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Sir, I thank you for permitting me to speak on this Bill which is one of the series of Bills the Government is bringing to clean black money which is pumped into illegal wealth of the country. I welcome this Bill. The Bill, in short, has three main areas. One is the definition of 'benami transactions', the second one is setting up of Appellate Tribunal and other adjudicating authorities and the third one deals with penal provisions.

It is good that the Bill has clearly mentioned as to who constitutes Benami transaction and which property is a Benami property. It is also good that the hon. Minister is bringing this legislation to effectively prohibit benami transactions. But the hon. Minister is equally aware that ground reality is entirely different. In spite of having so many legislations, people with malign intention are finding loopholes and elbowroom in circumventing laws through unfair practices. There is no doubt that you have Inquiry Authority, adjudicating authority, Appellate Tribunal, High Court, etc. But, are you not making, by giving them too many opportunities going from one authority to another and ultimately helping them to prolong dispute. So, I feel that whoever finds guilty of benami transactions be given one or two opportunities, or, at the most they be allowed up to Appellate Authority. It is only then the outcome will be quick and disputes will be resolved early.

The second point I wish to make is this. Now, the Government has opened income declaration scheme and it is likely to be open up to September this year. So, if a person declares his benami properties and transactions under Income Declaration Scheme, will he get immunity under this Bill? It is a big question which is lingering in the minds of many people. So, I request the hon. Minister to give a clarification on this point.

I wish to draw the attention of the hon. Minister to a very important and negative impact of the Benami Act which is causing great harm and injustice to those members of the Indian families, particularly the elderly ones, be it father or mother or elder brother or sister who *bona fide* provide funds while buying an immovable property in the name of a close blood relation, be it son or daughter or

younger brother but lost all rights in them after sometime. It is a normal practice in the Indian families, particularly Hindu families, which may not be technically HUFs, where elders contribute substantial funds out of their PF, gratuity, lifelong savings even if the immovable property is purchased in the name of a younger member of the family under a genuine impression that they will also have a right in the property as well as a right to live in them. But, legally, they will not have any right. So, here, they are not only losing their right to live in such property but also their hard-earned money in the absence of their name as joint owners. The present Bill under clause 2(9)(iv) partially addresses this issue. The clause says:

“any person in the name of his brother or sister or lineal ascendant or descendant, where the names of brother or sister or lineal ascendant or descendent and the individual appear as joint-owners in any document, and the consideration for such property has been provided or paid out of the known sources of income of the individual. ”

I want the hon. Minister to show some way out to this problem and ensure that justice is done to those members of family who provided funds while buying an immovable property. So, I request the hon. Minister to bring an official amendment in such genuine transactions even in case of non-HUF families where name of elder member of the family, who has partly or fully paid for the property, does not occur as joint owner.

Sir, clause 19 of the Bill deals with powers given to authorities. This clause 19(1) clearly says that authorities shall, for the purposes of this Act, have the same powers as are vested in a civil court. Sir, if powers are given to the executive, we know what will happen. The corruption will go up and inspector raj will be back.

So, I request the hon. Minister to look into this clause once again and remove the power given to the authorities.

Finally, penalties prescribed are strong enough, and I welcome them.

With these submissions, I support the Bill and request the hon. Minister to look into the points raised by me and address them to a logical conclusion.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण बिल लेकर वे आए हैं। वैसे तो सदन में जो भी बिल रखे जाते हैं, वे सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में जब वह राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बनता है तो उसके जीवन का लक्ष्य होता है कि वह किन बातों के लिए काम करना चाहता है। मैं अटल जी के समय 9वीं लोक सभा का सदस्य बना था। तब मेरी बहुत छोटी उम्र थी। हम लोग गांव से आए हैं, किसान के बेटे हैं और हमारी आय का दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए इस काले धन पर और बेनामी सम्पत्ति पर हम जैसे लोगों का चिंतित होना बहुत जरूरी है।

मैं सार्वजनिक तौर पर भाषणों में कहता हूँ कि यदि काला धन और बेनामी सम्पत्ति का जाल खत्म नहीं होगा तो ईमानदार तथा मध्यमवर्गीय आदमी चुनावी राजनीति नहीं कर सकता है। राजनीति लोग कर सकते हैं, संगठन की राजनीति कर सकते हैं, साथ मिलकर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार को इसी वजह से बधाई दे रहा हूँ। मैं ऐसे अवसरों पर बोलना अपना सौभाग्य समझता हूँ। बेनामी सम्पत्ति किसे कहते हैं, मैं नहीं मानता कि इसे सदन का कोई सदस्य न जानता हो। मैं सरकार को इसलिए बधाई दूंगा, क्योंकि इसका टाइटल बदला है। हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि नाम बदलने से क्या होता है। नाम बदलने से ही मंशा जाहिर होती है कि हम क्या करना चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है तो इसलिए नहीं दी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। मैंने अपनी भावना आपके सामने रखी है। मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि देश के विकास में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। यह कोई मामूली कदम नहीं है। मैं अटल जी का भाषण इस समय कोट करना चाहता हूँ। वर्ष 1989 में वे इस सदन के सदस्य नहीं थे, राज्य सभा के सदस्य थे। उस समय चन्द्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे। किसी ने उन्हें देशद्रोही कह दिया था। मुझे लगता है कि उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे संसद सदस्यों को जरूर पढ़ना चाहिए, मैंने तो उस भाषण को सुना है। उन्होंने कहा था कि अगर देश की तस्वीर बदलनी है तो क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारी मुद्रा बदलनी चाहिए, इससे काला धन समाप्त हो जाएगा। अगर दुनिया हम पर प्रतिबंध लगाती है तो हमारे पास जो केन्टोन बोर्ड की जमीनें हैं, आने वाले तीस साल के सामरिक महत्व को छोड़ कर, हमारी जरूरत के हिसाब से जमीन छोड़कर बाकी जमीन को नीलाम कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि हमारे देश के लोग ही उस जमीन को खरीदें। आप पूंजी इकट्ठी कीजिए और देश को बचाने का काम कीजिए।

तीसरी बात, उन्होंने कही थी कि बजाय विश्व बैंक के सामने हाथ पसारने के, जो हमारे एनआरआई दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, उनसे निवेदन करो कि देश के लिए मदद करें। वे प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने दो कामों को पूरा किया। यह ऐसा काम है जो मुद्रा बदलने से ज्यादा खतरनाक काम है। राजनीतिक दल जब काम करते हैं तो वे कभी भी इन चीजों को छूना नहीं चाहते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वे अभी बोल रहे थे कि हम इस बिल को लेकर आए थे। आप बेशक इसे लेकर आए थे लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर सके। यही राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है।

महोदय, सवाल यह नहीं है कि कानून क्या कहता है। कानून में और भी संशोधन होंगे। समय बदलेगा, इसमें कुछ खामियां आएंगी, मेरे मन में भी शंका है, उन्हें भी मैं सरकार के ध्यान में लाऊंगा, लेकिन आज का दिन सरकार को बधाई देने का दिन है और उन तमाम लोगों को, जो ईमानदार राजनीति के पक्ष में हैं, मैं दल की बात नहीं करता हूँ, अगर वे मानते हैं कि सरकार बदलने से कुछ फर्क पड़ता है, तो उस बदलाव के कुछ पैमाने हो सकते हैं, ऐसे ही कानून हो सकते हैं, अन्यथा बदलाव का कोई कारण नहीं है। एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति किन क्षेत्रों में कदम उठाता है, ये ऐसे फैसले हैं जो सरकारों को हिला देने वाले फैसले हैं, क्योंकि जिनके पास सम्पत्तियां हैं, वे मामूली लोग नहीं हैं, वे ताकतवर लोग हैं। बेनामी सम्पत्ति का इसमें जो उल्लेख किया गया है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ - लेन-देन नकली नाम से किया गया हो, तो वह बेनामी है। मालिक को मालूम नहीं हो या सम्पत्ति के संबंध में जानकारी होने से मना करता हो, वह बेनामी सम्पत्ति है। सम्पत्ति का भुगतान करने वाले व्यक्ति का पता न हो। ये तीन बातें हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेनामी सम्पत्तियां हैं। मैं सिवनी का सांसद रहा हूँ। हमारे ध्यान में आया है कि 3200 एकड़ जमीन, जिसकी कागज पर सात बार रजिस्ट्री हो गई, लेकिन जमीन है ही नहीं, ऐसी कुल 300 एकड़ जमीन है। दिल्ली में बैठे लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने कागज के आधार पर लोन ले लिया, लेकिन वह जमीन है ही नहीं। मैं रूरल डवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूँ। उसमें कभी दिल्ली में रजिस्ट्री का कम्प्यूटरीकरण करने का काम शुरू हुआ। यह बेहतर रास्ता है, लेकिन एक ही कानून बनाने से बात नहीं बनेगी। इसमें दो-तीन बातें और जोड़नी पड़ेंगी। "आधार नम्बर" को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने के बाद मेरे पास अगर दस सम्पत्तियां हैं तो इस नम्बर पर मेरी दस सम्पत्तियां चिह्नित हो जाएंगी और उसके अलावा मेरे पास अगर बेनामी सम्पत्ति है तो उसका कभी न कभी एक्सपोज़र तो होगा। मुझे लगता है कि तीन चीजें एक साथ होनी जरूरी हैं जैसे आधार नम्बर का रजिस्ट्री से जोड़ना बेनामी सम्पत्ति को उजागर करने का एक कारगर उपाय होगा।

दूसरा उपाय यह है कि हमारे आय कर के जो तौर तरीके हैं, सम्पत्तियों के डिक्लरेशन के जो तौर तरीके हैं, जो हमारे सामने लोकपाल आएगा तो हम चाहे सार्वजनिक रूप से जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी हों, हमें समय सीमा में अपनी सम्पत्ति का डिक्लरेशन करना पड़ेगा। आज नहीं तो एक-आध साल के भीतर शायद हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जो वास्तव में सदन में बैठा हर व्यक्ति चाहता है कि ईमानदार आदमी को कीमत मिलनी चाहिए, बेईमानों को कीमत नहीं मिलनी चाहिए। आज तो उल्टा हो रहा है। अभी भी जिसके पास बेईमानी का धन है, उसके पास ज्यादा ताकत है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि कानून की बातें मैं समझ सकता हूँ लेकिन जो वकालत करते हैं, क्या वे सदन में इस बात का उल्लेख करेंगे कि जो गलत ढंग से पैसा कमाया जाता है, वे बेनामी सम्पत्ति खरीदते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो तीन-चार पीढ़ियों से किसान है, हमारी तो एक डिस्मल जमीन नहीं बढ़ पाई। मुझमें कोई अवगुण नहीं है, लेकिन जो अपराध से पैसा कमाकर गुणात्मक तरीके से बढ़ाकर बेनामी सम्पत्तियां खरीदते हैं, चाहे वे भ्रष्टाचार करते हों, चाहे वे किसी भी प्रकार का गलत धंधा करते हों, हमारे एक मित्र ने कहा था, मैं उनकी बात कोट करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं पच्चीस एकड़ का काश्तकार हूँ, मैं दो टाइम भी अच्छे से रोटी नहीं खा सकता हूँ। बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सट्टा खिलाने वाला हमसे दस गुना नहीं, बल्कि सौ गुना आगे होता है। क्या यह सच्चाई नहीं है? मुझे लगता है कि ये चीजें कभी न कभी तो रुकनी थीं। आप कहोगे कि यह तो सीआरपीसी का मामला है, जी नहीं, यह सीआरपीसी का मामला नहीं है। यह आयकर की चोरी का मामला नहीं है, यह तो देशद्रोह है। उन अपराधों से ज्यादा गंभीर मामला है, इसलिए मैं सरकार को बधाई दूंगा। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। मठों, मंदिरों की सम्पत्तियों का इसमें उल्लेख नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में दो बातें लाना चाहता हूँ कि जैसे आपने हिंदू सम्मिलित परिवार की बात कही है, ऐसे ही हमारे शताब्दियों से ट्रस्ट चले आ रहे हैं, उनके पास तो कागज भी नहीं हैं। राजाओं ने जमीनें दान कर दीं और वे ऐसे ही चले आ रहे हैं। वह भगवान के नाम पर सम्पत्ति है। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि हजारों वर्षों से जो ट्रस्ट काम कर रहे हैं, जिनमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्या उनको सुरक्षा मिल पाएगी? कहीं ऐसा न हो कि जो ट्रस्टी हैं, बाकी लोगों के कारण उन पर कब्जा हो जाए। मुझे लगता है कि इसको भी कहीं न कहीं ध्यान में लाना चाहिए। कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या कम है। अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हुई थी, उनके पास संख्या की कमी है। इसमें बहुत बड़ा अमला लगना है। यह कमी इसको लागू करने में तो दिक्कत पैदा नहीं करेगी, इन बातों की चिंता इसमें की जानी चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो सम्पत्ति जब्त की जाती है, जो प्राधिकारी है, यदि 90 दिन में उसको लगता है कि यह बेनामी सम्पत्ति है तो वह उसे अधिकृत कर सकता है। पीड़ित को अपील करने का अधिकार है, लेकिन 90 दिन के भीतर अगर वह जब्ती बनाता है तो अक्सर जो देखा जाता है कि चाहे हम जितने भी जब्ती के केसेज देखें, चाहे इनकम टैक्स के केसेज देखें या बैंक्स के केसेज देखें, जो सम्पत्ति जब्त होती है, उसका जब तक फैसला होता है, तब तक उसका एक चौथाई भी नहीं बचता है। क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लिस्ट ऑफ मेमोरेण्डम पहले बनाया जाएगा, तभी उस सम्पत्ति की लूट से बचा जा सकता है? क्या इसको सुनिश्चित करने के बारे में कोई प्रावधान इसमें होगा? चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि इंटर स्टेट में कोई पकड़ा जाता है, जैसे दिल्ली में कोई पकड़ा जाता है, लेकिन उसकी बेनामी सम्पत्ति कर्नाटक में है तो उस सम्पत्ति का हकदार कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी या केन्द्र सरकार होगी? यह सब नियम बनाते समय आपने विचार किया होगा। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं।

हमारे मित्र कल्याण बनर्जी जी मुझ से पूर्व बोल रहे थे। वह तो अधिवक्ता हैं, मुझ से ज्यादा समझते होंगे। उन्होंने कहा राजस्व के लोग क्यों होने चाहिए, इनकम टैक्स के लोग क्यों होने चाहिए। जब तक राजस्व का आदमी नहीं होगा, तो इन बारीकियों को पकड़ नहीं सकता है। अगर इनकम टैक्स का अधिकारी इसमें नहीं होगा तो इन ट्रांज़ैक्शन्स के बारे में बहुत आसानी से समझ नहीं सकता है। इसलिए प्राधिकरण के अध्यक्ष को जो अधिकार दिए गए हैं, वह विवेक के अधिकार हैं, वह सिर्फ नियमों के भीतर बंधे हुए अधिकारी नहीं हैं।

मैं सरकार को इसके लिए बधाई देते हुए यह कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी विषय अपील से लेकर नियुक्तियों तक आए हैं, वह इसके लिए बधाई की पात्र है। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा गर्व या प्रशंसा महसूस करता हूँ तो वह इस बात के लिए करता हूँ कि इस सरकार के मुखिया की और सरकार की जो राजनैतिक इच्छाशक्ति है, जिसकी वजह से इस बात की चिंता किए बगैर कि बहुत से ताकतवर लोग इसका विरोध करेंगे, वह देश को मजबूत करने के लिए इस बिल को लाए हैं।

मैं सरकार को बधाई देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ और मैं यह मानता हूँ कि बार-बार कोई नया अधिनियम लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह संशोधन ही ठीक था। आने वाली पीढ़ी के सामने यह इतिहास होगा कि सन् 1882 से हम शुरू हुए थे, लेकिन समाधान के लायक हम वर्ष 2016 में बन पाए और इतिहास कहीं न कहीं इस बात का हिसाब लिखेगा। धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for affording this opportunity to participate in the discussion on this very important Bill. I rise to support this Bill with certain reservations. The main reservation is the Standing Committee on Finance headed by Veerappa Moily Ji had submitted very detailed recommendations for getting the Bill in a better way, but unfortunately, most of the major recommendations of the Standing Committee have not been taken into consideration. They would have improved the Bill in a better way. That is the main reservation which I have and this is my first observation.

Sir, as everybody knows, black money is a menace to the Indian economy and one of the main sources for generation of black money is the benami transaction or benami deal. So, benami deals are one of the major reasons for the proliferation of black money in a big way. So, generation of black money should be restricted. If we want to restrict and prohibit the generation of black money, definitely, the benami transactions should be dealt with seriously and in a very strict manner.

Sir, our country is facing acute poverty, unemployment and inequity. On one side, there is poverty, inequity and unemployment; and on the other, unaccounted wealth is accumulating like anything because of these benami transactions. If we are able to contain and restrict the benami transaction, definitely, the revenue tax which will be going to the exchequer can be very well utilized for development, for poverty eradication and for other purposes, and thus the country can be served in a better way. So, my first submission to this august House is, at any cost, we have to restrict the generation of black money by way of prohibiting these benami transactions or benami deals.

Coming to the background of this Bill, what is the real background of this Bill? The United Nations Convention Against Corruption was a very important Convention, in order to deal with the issue of corruption. It was also the recommendation of the Second Administrative Reforms Commission. These were

the two factors because of which this Bill has been brought before this House. According to the United Nations Convention Against Corruption, India has ratified the Convention in the year 2011.

The United Nations Convention against Corruption is primarily to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more effectively and efficiently. These are the two terms that are used in the Convention document that the issue has to be dealt with and it should be implemented effectively and efficiently. This is the letter and spirit of the Convention document. Article 23 and Article 30 of the said Convention are specific on the benami transactions and also proceeds of crime derived from offences. The detailed examination of this benami transaction, transfer of property and all these issues are well addressed in the UN Convention document. Article 23 and Article 31 are specific on these issues.

This Amendment Bill of 2015, to some extent, helps in achieving the directions of the UN Convention against Corruption and also the fourth Report of the Second Administrative Reforms Commission which was submitted in 2007 also deals with the benami transaction. That also has been taken into consideration in drafting that Bill. Therefore, I would congratulate the Government at least at this time on bringing such a Bill before this House.

Coming to the Bill, I would say that the original Bill is the Benami Transaction (Prohibition) Act of 1988. This Bill was to prohibit the benami transaction and recover the property held by the *benamidar*. This was the intention of the Bill. It may kindly be seen that prior to the enactment of this Bill by this House in the year 1988, an Ordinance was promulgated on 19th May, 1988. What is meant by the promulgation of an Ordinance? Promulgation of an Ordinance means that it is highly essential and there is no time till the House is being summoned. So, an Ordinance had been promulgated called the Benami Transaction (Prohibition) Ordinance, on 19th May, 1988. Subsequent to that Ordinance, it was replaced by the Act of 1988. This is the background. This is the situation. So, it was done in a very urgent way in 1988 and the Bill was enacted.

What happened after passing of the Act in the year 1988? Nothing has happened during these 28 years of our experience. It is quite unfortunate to note this because the Parliament passed an enactment in the year 1988. After 28 years of experience, we could not frame any rules. Nothing has happened on the Benami Transaction (Prohibition) Act. This is the situation. Subsequently, in the year 2011, the then UPA Government started bringing a new comprehensive Bill. That Bill also lapsed because of the dissolution of the 15th Lok Sabha. My point is, what is the *bona fide* behind this Bill? Why is this Bill delayed? No rule is framed; no action is taken on the basis of the provisions of this Act. This Act is actually put in the cold storage. It shows that the Governments were not sincere in the operationalization of the benami law. Therefore, I congratulate the hon. Finance Minister Shri Arun Jaitleyji, because at least, this time this Bill has come before the House for consideration. It is better late than never. At least, we are getting a chance to deliberate on this issue and we are going to pass this Bill also.

Coming to the provisions of this Bill, the Act of 1988 has the provision to prohibit benami transaction and right to recover benami property. But there was no specific provision for vesting the property with the Central Government. There was no appellate mechanism and no powers have been conferred upon the authorities as that of civil courts. There is no rule making provision. These were the four deficiencies noted by the Government during the 28 years of our experience. My simple question to the Government is this because the Government is in continuity. Why are we not able to frame rules? Why are we not able to overcome the deficiencies all these 28 years? The Government has to answer. I apprehend about it because the Government is not interested in executing or implementing the provisions of the benami law. There is no political will power. That is the main reason that I would like to point out.

Almost all the deficiencies have been addressed in the recent Bill. Still, there are some lacunas. Here, the definition of benami transaction is given as the property which is transferred to, or held by a person, and the consideration for such property has been given by some other person for his immediate or future benefit, direct or indirect. Why should we make it immediate or future? It should be mentioned whether it is immediate or future. I have moved such an amendment also.

Secondly, a person denies the knowledge of ownership. Thirdly, the real beneficiary is not traceable or is a fictitious person, and fourthly, what will happen if the property has been transferred in a fictitious name? This definition of benami transaction has to be reviewed once again so that further exemption shall never be made. Exemption has been given for the property held in the name of children or spouse etc. and some other exceptions are given. There is still some discussion going on to have more exemptions because the hon. Minister of Finance also said in his opening remarks that some complaints have been coming from various corners regarding the power of attorney holders and all these things. Please don't enhance the exemptions or expand the scope of exemptions which are available to the benami law.

Coming to mechanism and due procedure, a good mechanism is put in place, that is Initiating Officer, Approving Authority, Administrator, Adjudicating Authority, Appellate Tribunal, appeal to the High Court and Special Court to try the offences are also there. A very good mechanism is put in place and a well-established procedure is also there.

But there are some clarifications which I would like to seek. The first clarification is regarding the application of Code of Civil Procedure. Regarding the application of Code of Civil Procedure, Section 11 and Section 19 are totally contradictory. Section 11 says that Adjudicating Authority shall not be bound by the procedure laid by the Code of Civil Procedure but shall be guided by the principles of natural justice subject to the other provisions of the Act. The

Authority shall have powers to regulate its own procedure. Now kindly go through Section 19. Section 19 is totally reverse to this Section. It says that the Authority shall, for the purpose of this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matters namely, discovery and inspection, enforcing the attendance of a person, compelling the production of books etc. Therefore, the Adjudicating Authority, Administrator etc. are having all these powers. So, the Adjudicating Authority and authorities under the Act are not bound by the CPC as far as the procedure is concerned. But as far as the powers are concerned, they are entitled to all the powers but are not bound by the procedure which is being laid down in the Code of Civil Procedure.

Similarly, in Section 40 clause 1 and clause 2, that is regarding the Appellate Tribunal, the same situation is there. There is total contradiction in clause 1 and clause 2. As per Section 40 clause 1, the Appellate Tribunal shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure 1908 but shall be guided by the principles of natural justice. Section 40 clause 2 says that the Appellate Tribunal shall, for the purpose of discharging its functions under this Act, have the same powers as were vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely summoning and enforcing the attendance of a person and examining him. All powers which are vested with the civil court are also applicable for the Appellate Tribunal. Therefore, they are not bound by the procedure which is being laid.

Further, coming to clause 4 of Section 40, there is a specific provision that notwithstanding anything contained in sub-section 3, the Appellate Tribunal may transmit any order made by it to a civil court having jurisdiction and the civil court shall execute the order as if it were a decree made by the court.

The powers are of the civil court and the execution is by a civil court; the CPC is applicable as far as the powers is concerned for the adjudicating authority

and the appellate tribunal but the procedure of CPC is not applicable. This means, there has to be a clarification by the hon. Minister.

The second clarification is regarding the appeal before the High Court. Against the order of the appellate tribunal, either the Central Government or any party to the *benami* transaction can approach the High Court and seek remedy as the appellate mechanism. That is under clause 49(3), (4), and (5). It is very interesting. This is a very important point on which I would like to seek a clarification from the Government. It says that if the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in that case it shall formulate that question. I think, for the first time in the history of Indian legislation we are restricting the powers of the High Court. Subsequently, the appeal shall be heard only on the question so formulated by the High Court. That question only will be argued and decided and the respondent of the hearing of the appeal shall be allowed to argue only on that question. What is this procedure? The High Court is having inherent powers and discretionary powers. How can we restrict the High Court that it should adjudicate only on the question of law?

In the civil or mofussil courts or lower courts after the written statement and everything the issues will be framed by the lower courts. Similarly, we are giving a direction to the High Court to see what the question of law is. It is an admitted fact that the High Court will entertain an appeal only if there is a question of law. It is an accepted fact. Why are we restricting the right and discretionary powers of the High Court that it should only see the question of law and that should be framed as an issue and only on that question there can be arguments? This is absolutely unnecessary. I think, this is not according to the established provisions of our Constitution on judicial powers.

Another clarification which I would like to seek is regarding section 58. You kindly see clause 58. An exemption is given here again to the definition of *benami* transaction. What is a *benami* transaction? What are the exemptions to the *benami* transactions? These are well explained in section 18. Another provision is

there in clause 58 (1) which says, “The Central Government may by notification exempt any property relating to charitable or religious trusts from the operation of this Act.” What does this mean? This means, the Central Government is taking the discretionary authority to see that by means of a notification it can very well say that though a property is a *benami* property, this Act is not operational as far as the religious trusts and charitable trusts are concerned. What is a *benami* transaction? Almost all the *benami* transactions are in the name of religious and charitable trusts.

Today in the morning also we have passed a legislation. I am not going into the merits of that legislation. It was regarding the Lokpal Bill. There also the point is a little bit controversial. This provision here means that in the name of charitable or religious trusts, this Act itself is not operational. That is the provision in clause 58. They are totally excluded from the purview of the *Benami* Transactions (Prohibition) Amendment Act of 2015. This has to be clarified.

The fourth point on which I would like to seek clarification is section 59. The power of the Central Government to issue instructions, directions and orders to the Authority is very interesting. Kindly see section 59 (1). I am seeing this for the first time. We have passed a number of legislation. This is a new phraseology or a new provision which has come. “The Central Government may, from time to time, issue such orders, instructions or directions to the Authorities or require any person to furnish information as it may deem fit.”

What are the areas where the directions are given? Section 59 (d) says: “Any other criterion that may be specified by the Central Government in this behalf.” Sir, an adjudicating authority is a quasi judicial authority. As per section 59 (1) the Central Government has the power to give instructions, directions in order to adjudicate a matter. Is a judicious mind applied in this provision?

Finally, section 59 (3) says: “No orders, instructions or directions under sub-section (1) shall be issued to (a) require any authority to decide a particular

case in a particular manner, or (b) interfere with the discretion of the Adjudicating Authority in the discharge of its functions.”

This is a very strange provision. In the first provision it is being said that the Central Government is having ample power to issue direction, instruction to the Adjudicating Authority. Why should the Central Government have such a power? The Adjudicating Authority should be independent. Why should the Central Government issue direction and instruction? It is being said that they have to observe and follow the orders, instructions and directions of the Central Government. The Adjudicating Authority is bound to obey the orders, instructions and directions of the Central Government, which mean the judicial capacity of this Authority is being lost. I am only seeking clarifications on section 59.

These are the clarifications which I am seeking from the Government. Operationalisation of this Act definitely depends on the political will of the Government to curb benami transactions and black money. We have lapsed 27 years and during these 27 years we were sleeping over the Act of 1988. I hope that even after 27 years the Bill will be implemented as the document of UN Convention against corruption specifies. This Bill will be implemented more efficiently and I hope that this will be done.

With these words, I once again support this Bill with these reservations and clarifications. Thank you very much.

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Thank you Deputy Speaker, Sir, for giving me this opportunity. I will start by saying that Shri Kalyan Banerjee said as to why the income tax authority at all be involved in the implementation of the Act. I would like to tell him that to train an officer or to create a department it takes years and years. It is not very easy to create an organization exclusively other than the income tax to cater to this new law which is going to be implemented.

Shri N.K. Premachandran said that except only where the issue of law is involved, the case cannot be heard in the High Court. I think he is very correct. On the basis of the facts if one goes to the High Court, it goes on un-ending. If there would not be any stoppage, then the purpose of the Act will be defeated.

मैंने एक इन्कम टैक्स ऑफीसर के रूप में देखा है। थोड़ा-बहुत बेनामी ट्रांजैक्शंस को हम लोग भी पकड़ते थे। A comprehensive Bill is going to come. उसमें होता यह है कि मान लीजिए कि अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो वह इतने कंड्यूइट पैदा करता है कि एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में, दूसरे बैंक से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और चौथे से पांचवें बैंक में भेजता रहता है। इस तरह से, अगर इन्कम टैक्स ऑफीसर या इनिशिएटिंग ऑफीसर या एडज्युडिकेटिंग ऑथोरिटी उसे पकड़ना भी चाहे तो उसके पास इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। इन्कम टैक्स विभाग में अंडर स्टाफिंग बहुत है। इसकी वजह से इस बात के ऊपर हमें बड़ा एप्रीहेन्सन है कि यह एक्ट वास्तव में सक्सीड कर सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि रिक्लूटमेंट बढ़ानी चाहिए। बिना स्टाफ के इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। मैंने इन्कम टैक्स विभाग में वर्कलोड देखा है। They are already burdened. उनके पास इतना ज्यादा काम है कि अगर इस एक्ट को उन्हें इम्प्लीमेंट या मैनेज करने के लिए दे दिया जाएगा तो ऑफीसर्स की और स्टाफ की बहुत कमी होगी, इसलिए रिक्लूटमेंट भी होनी चाहिए।

अगर डिजीटाइजेशन होता है तो बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री का डिजीटाइजेशन पर जोर है, तो मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर में इससे रेवेन्यू की बढ़ोतरी होगी, जिससे देश का विकास होगा। विभिन्न जगहों पर जो एकाउंट खोले जाते हैं या जो ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनके नाम को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब डिजीटाइजेशन की वजह से इसे ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। खास तौर से, मैं अपने विद्वान दोस्त

एन. के. प्रेमचन्द्रन जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्हें इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि ये जो सिविल पावर्स एडज्युडिकेटिंग ऑथोरिटी को दी जा रही हैं, ऐसा अभी नहीं हुआ है, यह ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। इससे संबंधित तीन करोड़ दस लाख केसेज ऑलरेडी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। अगर हम वहां और ज्यादा केसेज भेज कर लिटीगेशन को बढ़ाएंगे तो बेनामी ट्रांज़ैक्शंस के पीछे जो हमारा पर्पज़ है, वह डिफीट होगा।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब वी.डी.आई.एस. स्कीम आई थी तो मैं उस समय असिस्टेंट कमिश्नर, इन्कम टैक्स के पद पर था। लोगों ने उस समय अन-डिस्कलोज्ड इन्कम तो डिक्लेयर कर दी, पर बाद में उनके खिलाफ केसेज खुलने लगे। जो इम्युनिटी दी गयी थी, वह इम्युनिटी इधर-उधर कहीं न कहीं से वॉयलेट हुई। मेरी तमाम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से भी बात हुई है। जब से यह बिल आया है, तब से एक माहौल पैदा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि 30 सितम्बर तक, जो लास्ट डेट है, जिसमें बेनामी ट्रांज़ैक्शंस रियल ऑनर के नाम आएगा और 45% के हिसाब से लोग उसमें टैक्स पे करने वाले हैं, तो उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू की बढ़ोतरी होगी। लेकिन, जो अभी इम्युनिटी दी जा रही है, वह वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों में इस बात का एप्रीहेंसन है कि अगर हमने अपना बेनामी ट्रांज़ैक्शन डिस्कलोज़ कर दिया तो इस स्टेज पर तो नहीं, लेकिन किसी और स्टेज पर इन्कम टैक्स ऑफिसर उसके लिए नोटिस न इश्यू करने लगे, केस को न खोल दें, इस बात पर ध्यान देने के लिए मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

महोदय, मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके बहुत सारे प्रोवीज़ो हैं। मैं इसके प्रोवीज़ो की नहीं, बल्कि इसके व्यावहारिक पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग आम जनता कहीं बैठ कर किसी भी ऑथोरिटी को, चाहे वह इन्कम टैक्स ऑथोरिटी हो, उसे बड़ी आसानी से ब्लेम कर देते हैं। यह ठीक बात नहीं है। यह परम्परा ठीक नहीं है। अधिकारी लोग किस कंडीशन में काम करते हैं, तो हमें उनको एनकरेज भी करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि हमारे यहां जो इन्कम टैक्स अथारिटीज हैं या रेवेन्यू की अथारिटीज हैं, वे एक तरह से लाइबिलिटीज हैं। किसी ने अभी कहा कि अगर इन्होंने ठीक से काम किया होता तो बेनामी ट्रांज़ैक्शंस होते ही नहीं। ब्लैक मनी जब पैदा नहीं होगी तो बेनामी ट्रांज़ैक्शन नहीं होगा।

यह भी एक बात उभरकर आई है कि आठ पर्सेंट रेवेन्यू ही अधिकारियों के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा यहां जेनरेट होता है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि यह समाज वह समाज है जो चार पीढ़ियों के लिए कमाता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, नाती-पोतों के लिए और दूसरे जीवन के लिए, एक तरह से यह सेल्फिश समाज है, स्वार्थी समाज है। अगर इन्कम टैक्स अथारिटी न रहे तो डिटरेन्ट मेजर नहीं

रहेगा। अभी केवल आठ पर्सेन्ट इन्कम टैक्स अथारिटी से जेनरेट हो रहा है, 90-92 पर्सेंट अपने आप हो रहा है, तो वह 90 पर्सेंट भी नहीं होगा। एक भय है, एक डिटरेन्ट मेजर है, जिससे रेवेन्यू आता है, वरना वह भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे अथारिटी डीमोरलाइज होती हैं। वे सोचती हैं कि कितना भी काम कर लिया जाए, हम लोगों को तो ब्लेम करना ही है, पॉलिटिशियन भी ब्लेम करते हैं और दूसरे भी ब्लेम करते हैं। जैसे हम लोग समाज से आए हैं, वे भी समाज से आए हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और फ़ैसिलिटीज भी बढ़ाई जानी चाहिए, जो फ़ैसिलिटीज इस समय हैं, चाहे वे इन्फ़्रास्ट्रक्चर की हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं, ताकि यह एक्ट इंप्लीमेंट हो और हमारे देश का रेवेन्यू बढ़े।

हम रेवेन्यू की बात नहीं करते हैं, खर्च की ही बात करते हैं। रेवेन्यू की बात करने में कुछ लोग डरते हैं। यह जो एक्ट है, वह रेवेन्यू को इनक्रीज़ करेगा और इससे हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बेनामी संव्यवहार संशोधन विधेयक, 2015 पेश हुआ है, इस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

माननीय वित्त मंत्री जी बिल को सदन में लाए हैं। यह एक छोटा प्रयास जरूर है कि बेनामी सम्पत्ति पर कैसे रोक लगाई जाए, लेकिन मूल रूप से एक सम्पूर्ण विधेयक भी आना चाहिए। जो ब्लैक मनी है, चाहे वह अन्दर हो या यहां से बाहर चली गई हो, उस पर सम्पूर्ण रूप से कैसे रोक लगे और कैसे काला धन बाहर से हमारे देश में आए? देश में जो काला धन है, कैसे उस पर रोक लगे? काला धन देश के सामने आए और जनता के बीच में जाए। इस पर एक सोच बनानी चाहिए। शिकंजा कसने के लिए कड़े प्रावधान का भी उपाय किया गया है। इसके लिए सजा का भी इंतजाम किया गया है। यह जरूरी है।

बेनामी सम्पत्ति और बेनामी धन भीतर-भीतर कैंसर की तरह प्रवेश करता है और देश को खाता है, देश की समृद्धि को खाता है। रियल एस्टेट में बड़े कारोबारी चालाकी से पैसे लगा देते हैं। व्यक्ति कोई दूसरा रहता है और संसाधन किसी दूसरे का रहता है। रियल एस्टेट में कानों-कान बात आती रहती है कि रियल एस्टेट में ऐसे पैसे लगा दिए जाते हैं। ये कारोबारी लेन-देन में बड़ी चालाकी और होशियारी करते हैं। मॉल में, सम्पत्ति का मालिक कहीं है और धन किसी का लगा हुआ है। बड़े-बड़े सिनेमा हॉल में, जो फिल्मी दुनिया की इंडस्ट्री है, उसमें भी बड़े पैमाने पर कारोबारी दौलत को लगाने का काम करते हैं। किसान और मजदूर तो एक कमरे के लिए लड़ाई करते हैं और आपस में मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। वे तो एक घर और एक कट्टा जमीन में फंस जाते हैं।

आज जमींदारी खत्म हो गई। उसके बाद भी बेनामी जमीन बड़े-बड़े लोगों के पास है।

17.00hours

आज भी उन्होंने कई तरीके से सम्पत्ति बनाई हुई है। बड़े घराने के लोगों के पास हजारों तरीके हैं। उनके पास बेनामी धन-दौलत भरी पड़ी है। अभी किसी का नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि बिल सामने है। जब काले धन पर बहस होगी, जिसकी बराबर चर्चा होती रही है कि ब्लैक मनी आएगी, हमारा देश समृद्ध होगा और रोजगार के अवसर आएंगे, जब वह आएगा, उस पर बड़े पैमाने पर चर्चा होगी। बड़े उद्योगपति लेन-देन के साथ कारोबार करते हैं और देश की समृद्धि, सुख-शान्ति और गरीब लोगों का धन लूटते हैं। सम्पत्ति की सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि कितनी सम्पत्ति होनी चाहिए। किसी के पास अपार सम्पत्ति है। कोई खाते-खाते मरते हैं और कोई खाने के बिना मरते हैं। इसलिए सम्पत्ति की सीमा भी तय होनी चाहिए।

आज भी बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी हो रही है। कहीं जंगल का क्षेत्र, कहीं पहाड़ का क्षेत्र, कहीं पठारी इलाका, वे वहां पांच हजार एकड़, दस हजार एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। बीस साल बाद उसका दाम पचास गुना बढ़ जाता है। वहां उद्योग जाने लगते हैं, एनएच जाने लगता है, रेल लाइनें जाने

लगती हैं। इस तरह बहुत चालाकी की जाती है। सरकार को सावधान होना पड़ेगा, माननीय वित्त मंत्री जी को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि लोग दिन के उजाले में बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि देश में कितना काला धन आया, कितना फायदा हुआ, कितना रोजगार आया। यह अलग बात है। मैं कहूंगा कि लैंड माफिया, सैंड माफिया, फॉरेस्ट माफिया, आज भी कई मठों में बड़े पैमाने पर हजारों एकड़ जमीन किसी-किसी नाम से है।

माननीय वित्त मंत्री जी से अपेक्षा है कि वे इस पर ध्यान देंगे। जो बेनामी बिल लाया गया है, इसके माध्यम से काली कमाई से बेनामी सम्पत्ति खरीदने पर ब्रेक लगेगी। यह जरूर एक छोटा प्रयास है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, मैं बेनामी संव्यवहार संशोधन विधेयक, 2015 का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने पंथ प्रधान प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को बधाई दूंगा, अभिनन्दन करूंगा। उन्होंने 28 वर्ष बाद इस विषय के बारे में एक महत्वपूर्ण विधेयक लोक सभा में पेश किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज तक कई बातें हो चुकीं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई घोषणाएं की गईं, कई कानून बनाने की घोषणा हुई। इसके बावजूद असल में कानून बनाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है। मैं एक बार फिर वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ।

आज देश में जो सबसे ज्यादा शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका नाम भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हमारे साथ इतने जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ है कि लोग सही व्यवहार को एक तरफ रखते हैं और आड़े मार्ग से जाकर व्यवहार करना पसंद करते हैं। लोग आड़ा रास्ता क्यों पसंद करते हैं। परिणाम है कि इस देश में अलग-अलग तरह का टैक्सेशन सिस्टम, सही तरीके से, मेहनत से पैसे कमाना और घर-संसार चलाना मुश्किल बात हो चुकी है।

सारे लोगों को स्विस बैंक के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। भारत में काला धन कमाने वाले स्विस बैंक में अपना धन रखते हैं। सौभाग्य से पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हिन्दुतानियों के सामने असलियत में इसकी व्याख्या की, कालेधन का आंकड़ा लोगों के सामने रखने के बाद पूरी तरीके से मालूम हुआ कि अगर सही तरह से इस कानून का इस्तेमाल करके कालेधन इस पाबंदी लगाने की सरकार कोशिश करे तो एक दिन हिन्दुस्तान की प्रगति अच्छी तरह से हो सकेगी और हिन्दुस्तान अच्छे रास्ते पर चल सकता है। दुर्भाग्य से वह अभी तक नहीं हो रहा है। आज कालाधन कमाने के अलग-अलग रास्ते हैं लेकिन पिछले कई वर्षों में यह साबित हो चुका है। आज का वर्तमान पत्र हो या मीडिया में हो, राजघराने में काम करने वाले पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काला धन कमाने का आरोप होता है लेकिन यह दुर्भाग्य से साबित हो चुका है, चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो, जिनके ऊपर घूस लेने के वक्त ट्रैप किया गया है, जिन्हें घूसखोरी में अरेस्ट किया गया है, उनमें से ज्यादा से ज्यादा संख्या महसूल विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की है, उसके बाद पुलिस कर्मचारियों की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में सबसे ज्यादा काला धन का निर्माण रिअल स्टेट के माध्यम से हो रहा है, जमीन के माध्यम से हो रहा है, जिस जमीन का रेट बाजार भाव में होता है उससे कई गुणा ज्यादा पैसा देकर कई लोग जमीन खरीदते हैं और लोगों को और सरकार को फंसाने का काम करते हैं। उसके माध्यम से जो पैसा जमा जाता है उसे सरकार के पास नहीं दिखाया जाता है। अगर सही कीमत सरकार को

दिखाने की कोशिश करें तो लोगों को डर लगता है, लोगों का डर होता है, टैक्सेशन में बढ़ोत्तरी होती जा रही है, पन्द्रह टका, बीस टका, पचास टका टैक्स कोई भी ईमानदारी से व्यवहार करता है तो कम से कम उसको प्रोफिट का 55% टैक्स देना पड़ता है। लोग कहते हैं अगर ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश करें तो उसमें से अगर 55% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़े तो व्यवहार को सामने क्यों रखें, इसलिए टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है। ईमानदारी से जो लोग काम करने वाले हैं उनको प्रोटेक्शन देना का काम होना चाहिए।

इस विधेयक में एक अच्छा सुझाव है कि हिन्दू फैमिली की डिफिनेशन को बहुत अच्छा किया है इससे लोगों को राह मिलेगी। इनकम टैक्स वाले जिस तरह से लोगों को डराने का काम करते हैं उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की जरूरत है। इस विधेयक में आपने सिर्फ इनकम टैक्स को इन्वोल्व किया है, कालेधन के व्यवहार करने के कई तरीके हैं इसमें फिल्म इंडस्ट्री है, रेल इंडस्ट्री है, हवाला रैकेट है। इलेक्शन के वक्त तो हवाला से ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। कई कानून अच्छे होते हैं लेकिन उनका इम्पलिमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है इसलिए उसका सही फायदा देश को नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को उसका सही फायदा नहीं हो रहा है और इस देश के लोगों को भी उसका फायदा नहीं हो रहा है। मैं इस विधेयक को अनुमोदन देते हुए, फिर एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और कहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से काले धन के ऊपर प्रतिबन्ध तो होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को भी संरक्षण मिलना चाहिए। यह विनती मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद।

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I have been listening very carefully to all the Members of this august House who have taken time to make certain submissions by way of a debate on an important Bill, the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015.

Each and every Member in this House has supported this Bill. In supporting this Bill, the reason they have given for it is that we are all unanimous that black money is one of the greatest menaces in this country. We all have to fight it together. The hon. Finance Minister when he addressed the House before the debate started that this Bill had been brought earlier by the UPA Government. But because it lapsed, it has to be reintroduced both in Rajya Sabha and in Lok Sabha.

Today the question arises as to why are we supporting this Bill. The earlier 1988 Act had a blanket prohibition that a 'benami transaction' defined hereunder, cannot be allowed, and it is banned. But there was no detailed legislation. We did not know who is going to investigate? Who is going to go after a benami transaction? Most of the cases that have developed in the past, whether by way of the Supreme Court or various High Court orders are always between two individuals; two individuals accusing each other. So, I appreciate the move of the Government. Now, we have proper authorities, proper investigating officers in initiating officers, the approving authority, an administrator and the adjudicating authority.

Few issues that I feel have created some confusion in my mind is that in Section 53(1) which says that any person who is in violation of provisions of this law, shall be prosecuted with rigorous punishment, etc. When you say any persons, the question that arises is - who do we put the *mens rea* on? Are we talking about the person who has transferred the property but indirectly kept it for his benefit? Or are we talking about the person in whose name this property has been parked? That is not clear. I hope the hon. Finance Minister would elaborate on that.

Secondly, and more significantly, where this Government is consistently talked about cooperative federalism, I do not somehow understand why once the property is confiscated, why should it vest in the Central Government and not in the respective State Governments where those properties are today situated? Apart from that, we welcome this Bill. I hope it goes in creating an atmosphere, a legislative atmosphere in the country where not just creation of black money but transacting in black money, parking of black money is seen as a liability and not a windfall profit. Thank you, Sir.

17.14 hours

(Hon. Speaker in the Chair)

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय अध्यक्ष महोदया, देशभर में बेनामी ट्रांजेक्शन्स को रोकने के लिए 1988 में बेनामी प्रोहिबिशन ट्रींजेक्शन एक्ट बनाया गया। मगर यह सच है कि जो सरकार का उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां रह गई थीं। यहां तक कमियां रह गई उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन्स भी फ्रेम नहीं कर पाए, सजा देने की जो व्यवस्था थी वह भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। किसी एक्ट के माध्यम से जो काम करने का उद्देश्य होता है, वह इस एक्ट के पारित होने के बाद पूरा नहीं हो पाया। इसलिए यूपीए-दो सरकार के समय में वर्ष 2011 में एक बिल लाया गया और जो पुराने बिल में खामियां थीं, उन्हें दूर करने के लिए अमेंडमेंट कर के वह बिल लाया गया। लेकिन पोलिटिकल विल न होने के कारण उस समय की सरकार से पास नहीं हो पाया। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, विशेष रूप से माननीय अरुण जेटली जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह आज बेनामी ट्रांजेक्शन (प्रोहिबिशन) अमेंडमेंट बिल, 2015 लेकर आए हैं।

मैं समझता हूं कि देश के लोगों की जो अपेक्षाएं सरकार से थी और लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ होते हुए देश गरीब क्यों है। इकोनामिक सर्वे के अनुसार, बड़े इकोनामिस्ट्स ने राय दी है कि देश का 70 परसेंट धन केवल 10-15 परसेंट लोगों के हाथों में चला गया है जिससे 70 वर्षों में अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि देश का इकट्ठा हुआ काला धन कुछ विदेशों में भेजा गया और यहां कुछ बेनामी प्रापर्टियां खरीदी गईं। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद एक्ट बनने से देश का यह रुझान खत्म होगा, देश में अमीर और गरीब की खाई खत्म होगी। देश का इकोनामिक मॉडल गरीब लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। इसके बहुत फायदे हो सकते हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ क्लेरिफिकेशन्स जरूर चाहता हूं। इनकम टैक्स एक्ट में भी इसके साथ कुछ बदलाव करने की जरूरत है। एचयूएफ की परिभाषा तो दी है, प्रैक्टिकल में माननीय वित्त मंत्री जी को ध्यान देना होगा, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जब वे बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपनी बहन के नाम पर जज़बाती तौर पर पैसे देना चाहता है, कोई अपनी कज़न को पैसे देना चाहता है। मान लीजिए उस व्यक्ति के अपने बच्चे नहीं हैं, उसका कोई कज़न या चचेरा भाई उसकी देखभाल करता है, जब उसे पैसा दिया जाएगा तो उसका क्या होगा? इस बात की क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए।

यह सच है कि हमारे देश में कुछ जमीनें भगवान के नाम पर हैं, कुछ जमीनें गुरुद्वारा साहब की जमीनें गुरु ग्रंथ साहब के नाम पर हैं। यह ठीक है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, फैसला किया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब को व्यक्ति के रूप में, गुरु के रूप में माना जाए। इस बिल में जरूर

क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। इससे पहले लैंड रिफार्म्स हुए, किसी ने बिल्ली, कुत्ते आदि के नाम पर जमीनें की हुई थी। आमदनी की सीलिंग, लैंड सीलिंग, लैंड रिफार्म्स को प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए, मैं चाहता हूं कि इस बिल में काम्प्रिहेन्सिव तौर पर इसकी क्लेरिफिकेशन दी जाए। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेनामी नामों से संपत्ति खरीदने, व्यापार करने, शेयर का लेनदेन करना, गाड़ी खरीदना हमारे देश में आम बात हो गई है। पैसा किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम से होता है। कुछ मामलों में अपने पैसे खुद के नाम पर ली गई संपत्ति को तुरंत अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह सिर्फ कानून की आंखों में धूल झाँकने जैसी बात है।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेनामी ट्रांजेक्शन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 में व्यापक बदलाव पर कठोर एवं प्रशासनिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया है। आज कालेधन के कुबेर अपनी काली कमाई से बेनामी संपत्ति खरीदने के गोरखधंधे में लगे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, कानून बनाने के बाद यह पूर्णरूपेण बंद हो जायेगा, इसमें संदेह है, क्योंकि ये लोग काफी चालबाज होते हैं। इसलिए सरकार को कानून की बारीकी एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म धाराओं को स्थापित करना होगा, तभी इस पर कुछ रोक लग सकती है। देश में सबसे अधिक काला धन रियल इस्टेट में लगता रहा है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र काले धन पर खड़ा है। अगर इस पर थोड़ी कड़ाई होगी, तो रियल इस्टेट क्षेत्र का प्रतिकूल असर दिखेगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक और विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस कानून में सभी प्रकार की सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार केन्द्र के पास होगा, किन्तु जमीन और जायदाद राज्यों का विषय है। अतः इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को भी शामिल करना होगा, अन्यथा कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। इस प्रस्ताव में समय सीमा स्पष्ट नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को अपीलीय प्राधिकरण में कब तक अपील करने का अधिकार है, यह नहीं पता। उसके बाद अपीलीय प्राधिकरण कितने दिनों में अपील करने का निर्णय देता है, यह भी नहीं पता। इसके लिए उच्च न्यायालय में जाने के लिए कम से कम तीन महीने का समय रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, इससे एक समस्या और खड़ी होगी, क्योंकि विशेषकर ग्रामीण इलाके में लोगों के पास जमीन के सही कागजात नहीं हैं। राज्य सरकार के पास भी पूर्ण लैंड का रिकार्ड नहीं है, इसलिए असली हकदार का पता लगाना मुश्किल होता है। पुराने टाइटल और नये टाइटल में विरोधाभास है। अनुसूचित जाति-जनजाति की जमीन को लेकर भी समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि उनके पास टाइटल नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदया, एक समस्या यह भी है कि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और वह यहां किसी बेनामी नामों से सम्पत्ति अर्जित कर लेता है। हमें इन सभी कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना होगा। मैं मानता हूँ कि कानून के बनाने से दीवानी मामले काफी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि किसी भी बेनामीदार को पता चलेगा कि उनके नाम से कहीं सम्पत्ति है, तो फिर वह भी उस सम्पत्ति को हासिल करने के लिए सभी तरह के कानून का सहारा लेगा। इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी।

अतः कानूनी पेचीदगी को सुलझाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि छः महीने की जेल और 25 प्रतिशत तक जुर्माना लगा देने से यह कानून कठोर हो जायेगा, ऐसा नहीं लगता। आप सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार पूर्णरूपेण ले लें। इसके साथ-साथ आये दिने अखबार में आता रहता है कि अमुक अधिकारी के यहां छापा पड़ा और अकूत सम्पत्ति का पता चला। अब तो छोटे-छोटे पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के यहां भी छापे पर अकूत सम्पत्ति मिल रही है। अगर सरकार पिछले दस-पन्द्रह वर्ष पहले से सेवानिवृत्त हो चुके बड़े अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों की शिकायतों पर जांच करे, तो उसकी भी काली कमाई वाली सम्पत्ति का पता चल सकता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाये।

अध्यक्ष महोदया, मैं सशक्त एवं प्रभावी कानून की आशा करता हूँ और माननीय मंत्री जी को इस बिल पर बधाई देता हूँ। धन्यवाद

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Thank you Madam Speaker. The Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015 is brought to bring comprehensive amendments to the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 and to deal with benami transactions effectively.

We know that many of the politicians and bureaucrats in the country are amassing property worth more than their legal income in benami names. The detail of so many such transactions has come to light during the recent search for black money in the country as well as abroad. I think, this Bill will help to check this menace to a great extent if implemented properly.

The Standing Committee had noted that the Income Tax, 1961 has adequate provisions to deal with issues of tax evasion and unaccounted wealth. Certain amendments to this Act, to account for unexplained investments made under benami names, will achieve the objectives of the Bill instead of creating a separate law.

The Committee had also noted that benami transactions could be pre-empted and eliminated by digitalisation of land records. Further, the Bill provides for confiscation of properties which are adjudged as Benami properties. Rights over these properties are vested with the Central Government. The Committee stated that since land is a State subject under the Constitution, rights over confiscated properties should vest with the State Governments instead of the Central Government. So, I would like to know what is the Government's reaction to these issues. I support the Bill. Thank you, Madam.

SHRI C.K. SANGMA (TURA): Thank you, Madam, for giving this opportunity to be a part of this debate. I would, first of all, like to congratulate the Finance Minister and the hon. Prime Minister for bringing this Bill today which was dormant for so many years. Having said that, I would like to add just two points to this.

The first point that I would like to say is that it is so critical that in this particular Bill, or this particular Act that it is going to be, coordination with States must be done. Since land is a State subject, unless and until there is proper coordination between the Centre and the State, it will be very difficult for this Act to be actually implemented at the grass root level.

Let me just give an example of my State. I am sure there are many other States that will have the same kind of situation. My State has an Act called the Land Transfer Act which prohibits outside people, people from outside the State, to buy land. In situations like this, it complicates the entire situation. That is just one of the Acts.

Second, we are a Sixth Schedule area. Being a Sixth Schedule area, the land belongs to the clan; the land belongs to the headman. The land does not belong to any individual. In this particular Act, there is no provision to allow the clan to be exempted from this law. I think, first of all, I would like to say that the local laws and the local land Acts must be taken into consideration when this law is being passed and coordination with the States must be done; otherwise this Act will never be implemented properly at the grass root level.

Another issue about the black money that is coming up is this. This whole law has been brought up for the black money. I think, our hon. Finance Minister is much more aware than us that in North East, most of the tribals are exempted from income tax. When there is an exemption from income tax, at the same time, there are laws like the Land Transfer Act. It is a wonderful scenario for anybody who wants to do benami. It is because, if you want to buy land there, you have to

do it through benami; there is no other way. If a company wants to come and set up a business out there, they have to get it and they have to tie up with local people. Only then can they do it. The income tax not being applicable, there is lot of inflow of cash that is coming in. Therefore, these kinds of situations need to be considered when we pass this Bill.

Another important issue is this. Since we are talking of black money, I want to add, which again the hon. Finance Minister is aware, that North East is a very vulnerable location. There is a lot of fake money that comes in through the borders. We have porous borders with Bangladesh. A lot of counterfeit money is coming in. At the same time, we have got income tax exemptions, and there are land transfer issues. I think, it is a very serious situation. I think the Central Government must make Acts and policies that are very much tailored to the situation at the grass root level. But, having said that, I would not like to say anything against the tribals out here. But, all I am saying is that the Central Government must respect the sentiments of the tribal people and, at the same time, ensure that the Act is implemented in true spirit.

The last point which I would like to mention is this. Multiple laws are there to act against black money. I think the way GST has come to streamline all the taxes, if laws can come to streamline the black money, I think, it would make more sense. Here, you are giving more teeth and more power, of course, to the income tax officers which is a good thing. But, at the same time, it could be misutilized by them. I think, that is very critical and there the Government must make some provisions to ensure that they are not misutilized. ब्लैक मनी की जो बात हो रही थी कि ब्लैक मनी में when the Government is taking steps to abolish the benami transactions, I think black money comes because of the high registration. So, if the registration is cut down, then I think people will come in and give the real value of the land. So, I think black money could be targeted more through registration being lowered.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): I would congratulate the Finance Minister and also the Government. The Bill, which has been lying dormant for the last 27 years, has been brought today for the introduction and also to pass. This shows the will of the Government. Actually, I wanted to speak much on this subject but because of the constraint of time, I would like to stress only on two or three points.

Benami transactions are mostly ज्यादातर बेईमानी होती है, आपको भी पता है। उसको खत्म करने के लिए बिल लाया गया है, लेकिन हरेक आदमी सिर्फ प्रोपर्टी के बारे में बात कर रहा है। There are many assets you can create through benami transactions. जैसे शेयर्स में होता है, कोई आदमी दूसरे नाम पर लगा सकता है। उस विषय पर अभी स्पेसिफिक कुछ भी बात नहीं कही गई है, शायद फाइनेंस मिनिस्टर उसके बारे में कुछ बोलेंगे। दूसरे, जो भी एग्जीक्यूटिव है, वह जज भी है और एग्जीक्यूटिव भी है, हमारा कहना है कि वह दोनों नहीं होना चाहिए। इंकम टैक्स ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, यह आपको मालूम ही है। प्राइम फेसी, कोई किसी प्रोपर्टी को कहे कि यह बेनामी प्रोपर्टी है, आप ट्रांजैक्शन करते हैं। आपको मालूम है कि फिर यदि केस चलता है, उसके बाद वह एपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तब तक 30-40 साल गुजर जाते हैं। तब तक प्रोपर्टी का क्या हाल होता है? कोई घर होने दो, या प्रोपर्टी होने दो, खेत होने दो, my request is that there should be a time limit.

माननीय अध्यक्ष : कितने प्वाइंट्स हैं?

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड: मैडम, केवल तीन-चार प्वाइंट्स हैं। बिसिल पॉवर इसमें आनी चाहिए। अकसर होता यह है कि जिसके नाम प्रोपर्टी रीसेल होती है, उसको पता नहीं है, चाहे वह ड्राईवर हो, सर्वेन्ट हो, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके नाम पर प्रोपर्टी है। अगर बिसिल पॉवर हो, अगर हम उनको थोड़ा इंसेंटिव देंगे, मान लीजिए कि सौ करोड़ रुपये की प्रोपर्टी है, अगर बिसिल पॉवर हम इसमें शामिल करते हैं तो कम से कम दस प्रतिशत या बीस प्रतिशत यदि हम उनको इसमें देते हैं तो बहुत अच्छा होगा।

चौथे, अकसर यह बात रीयल स्टेट में होती है। मैंने देखा है कि एक एक आदमी चार चार अपार्टमेंट्स खरीद सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जिसको चाहिए, वे खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए ज़ीरो-टैगिंग ऑफ दि प्रोपर्टी करें।

अंत में, मैं हमारे वित्त मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं। हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे वित्त मंत्री जी इतने काबिल वकील हैं कि वह किसी मुजरिम को फांसी भी सुना सकते हैं और उसको कंविस भी कर सकते हैं कि उसके लिए फांसी क्यों बनाई गई है।

अंत में, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ईमानदार की रक्षा करिए। बेईमान को शिक्षित करिए।

HON. SPEAKER: Saugata Ji, I think you cannot complete in two minutes.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, today I am over-whelmed with gratefulness towards you that you allowed me again. I agree with you that the House should end at proper time at 6 'o' clock. Your effort in this regard is very much appreciated. Hence, I will be super short.

Already Kalyan Banerjee Ji on our side has made all the points. He is an eminent lawyer. All that I wanted to say is that as a Member of the Standing Committee on Finance, we had eight meetings on the Benami Transaction Bill and we gave an unanimous report in which we said that a fresh law should be brought. I want to ask this to the hon. Minister why is it that you chose to over-ride the unanimous recommendation of the Finance Committee in which your party colleague Shri Nishikant Dubey was also a part, and went ahead with the Bill?

My second question is this. The purpose and the intention of the Minister is good. He wants to end black money. But he very often said that the path to hell is paved with good intentions, and actually by bringing this Act, he is opening the path to hell because in the Statement of Objects and Reasons, the Bill does not state that the purpose is to eradicate black money. Nowhere is it mentioned. Suddenly, he says it is to eradicate black money. That is all.

Here in this Act there is a provision for confiscation under 27(1) and it will vest in the Central Government. But if somebody evades income tax and the money comes or the money comes from smuggling, human trafficking or drug offences, it is all right. Let it vest in the Central Government. But the State Government allocates land like it is done in many townships for residential purpose or for setting up of a factory. Then, why should it not vest in the State Government? It is because it should go back to the State Government which had originally allocated the land.

Lastly, I think this will open a serious problem in rural areas where there are no proper land records and there are cash transactions. Lakhs of people will become homeless. We have said that this will open the road to tax terrorism. The Bill should not become another coercive instrument in the hands of the Revenue

Department to forcibly collect or mobilise taxes as the existing Income Tax Act has adequate provisions and teeth to deal with issues such as tax evasion and unaccounted income.

So, my last appeal to the hon. Finance Minister is this. He is a person with a large heart. He is magnanimous. Maybe, he has brought the Bill but if everybody has said that we support the intention of the Bill, you bring a proper new Bill. We will all support it unanimously. Let him take back the Bill today and come with a new Bill.

HON. SPEAKER: Thank you very much.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I am extremely grateful to a very large number of hon. Members who have spoken on this Bill.

Of course, Mr. Gowda opened the discussion and made some very valid points but one point which has been made across by several Members--Mr. Kalyan Banerjee made this point and Mr. Saugata Roy again raised it—is that the Standing Committee had said that we need a new Bill. The reason why the Standing Committee said that we need a new Bill is that the original 1988 Bill was a small Bill with nine Sections. It provided for acquisition of a property. Now when you acquire, you pay compensation. In any acquisition law, compensation is to be payable. There was no vesting of that property in the Government. It was an acquisition in favour of the Government. Then, the entire procedure, the principles of compensation, the authorities for acquisition and implementing—all was absent in that Bill.

The Law Ministry took a view that the basic principles of the Bill, if all this to be done by the rules, would be *ultra vires* because this would be a case of excessive delegation, and therefore, the rules cannot be framed. From 1988 till today 2016, the rules have not been framed. One of the hon. Members wanted to know whether any properties have been actually acquired. The answer is ‘no’ because the machinery for enforcement itself was not created, though there are two judgements of the Supreme Court which interprets this Act in order to tell us as to what is Benami and what is not Benami.

The 1988 Act also has a provision for prosecution. The provision for prosecution, prohibition and acquisition remained in that Act. So, the prosecution provision under section 3(3) says that whoever enters into any benami transaction shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or both. So, whoever subsequent to 1988 entered into a transaction which was a benami transaction, either of the two parties would be liable for prosecution.

So, if we had accepted the recommendation of the Standing Committee – repealed the 1988 Act and recreated a new law in 2016 – that would have been granting immunity to all people who acquired properties benami between 1988 and 2016. Obviously, the acquisition now cannot take place, but the penal provisions of the 1988 Act also would have stood repealed. When a new Act with a similar provision would have come, it could only apply for a penal provision to properties which are benami and entered into after 2016.

Anybody will know that a law can be made retrospective, but under Article 20 of the Constitution of India, penal laws cannot be made retrospective. The simple answer to the question why we did not bring a new law is that a new law would have meant giving immunity to everybody from the penal provisions during the period 1988 to 2016 and giving a 28-year immunity would not have been in larger public interest, particularly if large amounts of unaccounted and black money have been used to transact those transactions. That was the principal object. Therefore, *prima facie* the argument looks attractive that ‘there is a 9-section law and you are inserting 71 sections into it. So, you bring a new law.’, but a new law would have had consequences which would have been detrimental to public interest.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Since you want to penalise those people, how many cases were registered from 1988 to till date using the Benami Transactions (Prohibition) Act? There have passed so many years since that Act was enacted. Without that, how are you going to do it?

SHRI ARUN JAITLEY: That is precisely the argument because the machinery for enforcing that Act from 1988 was never created. Today, that machinery is being made operative under the present amendment.

One of the questions which Mr. Gowda raised was: What is the protection being granted to the whistleblowers under this Act? I will deal with each one of the substantial questions which the hon. Members have raised. Under this Act, whistleblowers need not get any protection because we have a specific law for

whistleblowers which applies across laws to all whistleblowers irrespective of the whistleblowing that they do. So, a whistleblower can give you information about violation of moneylaundering laws or of FEMA or of Income Tax or of benami transaction. When a whistleblower gives that information, he gets protection under the Whistleblowers Act. So, each of the legislations in relation to which he gives information need not be made specific as far as he is concerned.

Then, Mr. Gowda asked : When offences under this Act are punishable with imprisonment up to seven years - it is a serious offence - why have we made it non-cognizable? This is a violation of a tax law and a violation of a tax law is punishable. It is made non-cognizable because we do not want multiple agencies to come and start harassing people. Immediately the police would also come in and start harassing people. The object is not to harass them; the object is that there must be prosecution if he has violated this particular law.

Now, one of the questions which you raised was that the Standing Committee has made a very valid suggestion that the property or the asset acquired should be out of 'known sources' as against the original phrase 'known sources of income'. You are absolutely right. The Standing Committee suggested that the word should be 'known sources' and not 'known sources of income' because if a person is accused of having acquired a benami property, he can legitimately say, 'that this is not my income, I have borrowed this money from a bank, or I have taken this money from another family member'. If he is able to show that, then that is a legitimate defense. So, the sources would be known, though it would not be sources of his income. It was a correct suggestion which has been made. If you see the list of amendments which the Government has circulated, in accordance with the recommendations of the Standing Committee, in amendment Nos. 3, 4 and 5, I have proposed to the hon. House that the phrase 'of income' in all the three clauses, wherever it is mentioned, should be deleted, and the word in the amended clause would be 'known sources' and not 'known

sources of income'. That suggestion has already been incorporated in the amendments that I have suggested.

You also raised a question, which is a valid question, that at the appellate stage, there is a provision with regard to the right of representation through an authorised representative. Now, there are serious consequences. One of the serious consequences before the adjudicating authority is that a person is liable to lose his property. Since the consequences are severe, we have provided in the original Act a provision for right of representation before the appellate authority, but the original Bill did not provide for a right of representation before the adjudicating authority. Therefore, amendment No. 9 that I have proposed, in accordance with the suggestion that you have said, provides that "the benamidar or any person who claims to be the owner of the property may appear either in person or take the assistance of an authorised representative." So, the exact suggestion which you have made is already there in the amendment that I have proposed.

You then raised this whole issue of why we have these four stages, that is, the initiating officer, the acting officer, the adjudicating officer, etc. The entire object of this is that you must have this case of confiscation of his asset, the vesting, in the Government. Different people must apply themselves; it must go in stages so that there is no misuse of power by any one individual. After all, when there are different authorities at different grades which go and apply their mind, then, obviously, the matter has been seriously gone into. It is a protection in favour of the citizen that there is no unfair action – one person may be vindictive; and with one person, there is a possibility of going wrong. Therefore, if you do it in various stages, obviously, the possibility of error gets significantly reduced.

The hon. Member from the AIADMK raised a question as to why the High Court has been given the power to decide and adjudicate upon issues on which the adjudicating authority or the first appellate authority may not have decided. I think giving the High Court the power is important because if some issue is of significant importance and, in the entire proceedings, has been left out, then it is

obvious that before some higher authority, before a property is acquired because a valuable right is being lost, all issues are thrashed out and, therefore, there is no possibility of any issue having been left unattended, which would have otherwise been a defense which is available. This is the same reason why the power to record evidence is additionally being given to the appellate authority.

It is because if before the adjudicating authority, some evidence is left out and before the appellate authority which is headed by a Judge, a person who is about to lose his property says, "I have a defence to make. Maybe, this document was not considered. So, I want to place this additional document which goes to my defence. In all fairness, it should be allowed to be considered." This is in accordance with the general principles of hearing appeals. Even in the Code of Civil Procedure, Order 41, Rule 27 is very clear that at the appellate stage, the power to introduce new evidence which has been ignored or left out by mistake before the original authority, is always there. That is a part of the justice process itself.

One important question which has been raised by several Members is, as to why should the property vest in the Central Government, why not in the State Government? Under all acquisition laws, there are acquisition laws or vesting laws which are in the States also – the benami transaction law wherein a property is registered in the name of a person who has not made the payment for it or the income-tax law, these are central legislations. For example, we have the PMLA, which is the central legislation; we have the FEMA, it is a central legislation; we have the NDPS, it is a central legislation. Similarly, we have several State legislations where State Governments are empowered. Under all central legislations where vesting of property takes place, it vests in the Central Government. In the case of State legislations, when the vesting takes place, it vests in the State Government. At least, I am not aware of any law which is a central law under which vesting or acquisition takes place but the property rights then go to some other authority. They vest in the Central Government itself.

Shri Kalyan Banerjee wanted to know and that is a legitimate point that he raised, as to the appellate authority not having been given a specific power of staying the order. When an appeal is pending, obviously vesting should not take place. As he knows, being an eminent lawyer himself, when an appellate authority has a power to pass a final order, the authority to pass a lesser order is inherently in that appellate authority. Since you have a power to allow the appeal and release the property from acquisition, inherently an appellate authority, in several legislations, where there is a power of appeal, there is always a power of interim suspension of the order which is inherent in that power of appeal, irrespective of whether it is specifically mentioned or not. There are pronouncements of courts to this effect.

Which is the power and in how many days appeal could be filed? I think, the Act is very clear. There are two provisions in the Act. He wanted to know about the power to file an appeal and in how many days. He has said that it is not mentioned. If he looks at the legislation itself, clause 30 says:

“The Central Government, by notification, may establish an appellate authority to hear appeals against the order of the adjudicating authority.”

So, obviously, the appellate authority will hear appeals. The power to appeal lies to that authority. In how many days will an appeal has to be filed? I think, Section 46 is absolutely clear. It says:

“Any person, including the initiative officer, aggrieved by an order of the adjudicating authority, may prefer an appeal in such form and with such fees as may be prescribed, to the appellate authority against the order passed by the adjudicating authority within a period of 45 days.”

So, even the limitation period is also mentioned in the Act itself.

One of the Members wanted to know about this power under Section 59 to issue directions by the Central Government. Will it interfere in the adjudicating power? The answer is ‘no’. Section 59(3) says that there are certain kinds of

directions for administrative functioning, which can be issued. It very clearly says that no order, instruction or direction under sub-section 1 shall be issued which require the authority to decide a particular case in a particular manner. So, the directions issued have to be in relation to administrative matters and not in relation to other matters.

Is this law in conflict with the Income Tax Act in any way? The answer is 'no'. The Income Tax deals with various provisions of taxation, the powers to levy the procedures etc. This particular law deals with any benami property which is acquired by a person in somebody else's name to be vested in the Central Government. So the two Acts are supplementary to each other as far as this Act is concerned.

A question has been raised with regard to the non-applicability of the Civil Procedure Code under Section 11. But under Section 19 some of the powers which are similar to the Civil Procedure Code have been vested; this is there in all adjudicating Acts. *Ipsa facto*, the whole CPC is not applicable but since you have to hear matters, record evidence etc., there is a defined procedure which has been defined in Section 19 of the Act itself.

एक प्रश्न आपने पूछा था कि जो प्रॉपर्टीज़ रिलीजस डाइटीस के नाम या होली बुक के नाम पर हैं, अब उसका मालिक कौन होगा? कहीं वे तो बेनामी नहीं मान लीज जाएंगी? इसीलिए इसमें सेक्शन 58 है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो चैरिटेबल और रिलीजस ऑर्गनाइज़ेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एग्ज़ेप्ट करने का अधिकार सरकार को है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : As per Section 58, operation of the Act is exempted for the religious institutions as well as charitable institutions. That means, I can very well have this benami property and I can enjoy the property also by having an understanding.

SHRI ARUN JAITLEY: If there is a genuine property which belongs to a church, mosque, gurdwara or a temple, Section 58 says the Government has power to exempt it. But if you make an illegal business out of it, as you are suggesting us

now that the property is your benami property and you create a fake religious sect and start keeping benami properties, then the Government would not exempt it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Section 58 is very clear as far as the religious institutions and charitable institutions are concerned.

SHRI ARUN JAITLEY: But obviously if somebody plays a fraud, the Government has a power not to exempt such a property on which a fraud is played. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Jaitley, you are not supposed to answer something. Shri Premachandran, please take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Shri Premachandran, it is very clear that Section 53 is meant for *bona fide* religious properties, not for religious properties only being used as a pretext of tax evasion.

A question has been raised that under Section 53 who would be liable? Is it the person who acquires the property or the person who sells the property? The language is very clear; whoever enters into benami transaction, and obviously both these people have entered into a benami transaction itself.

Two very important questions have been raised. Several Members have raised a question with regard to power of attorneys and so on or agreements, under which because of some peculiar reasons an arrangement has been entered into, consideration has been paid, property's transfer of possession has taken place but finally the title deeds have not been registered. In the original Bill, they were not covered. But the Committee, which was headed by Shri Moily, who is fortunately here with us, strongly recommended that in accordance with the provisions of Section 53A of the Transfer of Property Act, all these properties which are covered under these arrangements, should also be included in this. The Government has accepted that and introduced an official amendment in accordance with the recommendations of the Standing Committee.

The last question which was raised by the hon. Member Shri Sangma from Meghalaya was with regard to properties in several Schedule areas which are covered by the Fifth Schedule itself. This Act does not exempt those properties. But that exemption would be available in the Article 244 of the Constitution. Article 244 provides for a Fifth Schedule to the Constitution itself.

18.00 hours

The Fifth Schedule, Clause 5 clearly says that wherever those scheduled properties are, the Governor of that State has the power to exempt the operation of any Central legislation to those areas. So, if any such contingency arises, the Governor of the State where the property is located, under clause 5 of the Fifth Schedule prepared under Article 244 has the power to exempt those properties. ...

(Interruptions)

HON. SPEAKER: It is six o'clock. If all of you agree, the time of the House is extended up to this Bill getting passed.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: Thank you.

SHRI ARUN JAITLEY: These were the various queries which were raised. Since it is a technical kind of a Bill, I have attempted to answer some of them. Most of the Members having supported this Bill as an important measure, I commend to this House this Bill for its acceptance.

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

Clause 2 Insertion of new heading before Section 1

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 1

HON. SPEAKER: Amendment No. 11 – Shri Bhartruhari Mahtab is not present.

The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Substitution of new Section for Section 2

Amendments made:

Page 2, line 41, *omit* “of income” (3)

Page 3, line 3, *omit* “of income” (4)

Page 3, line 9, *omit* “of income” (5)

Page 3, *after* line 16, insert –

“Explanation. – For the removal of doubts, it is hereby declared that benami transaction shall not include any transaction involving the allowing of possession of any property to be taken or retained in part performance of a contract referred to in section 53A of the Transfer of Property Act, 1881, if, under any law for the time being in force, --

(i) consideration for such property has been provided by the person to whom possession of property has been allowed but the person who has granted possession thereof continues to hold ownership of such property;

- (ii) Stamp duty on such transaction or arrangement has been paid; and
 (iii) the contract has been registered.” (6)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendments?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes Madam, I am moving Amendment No. 12.

HON. SPEAKER: These are Amendment Nos. 12 to 17. Are you moving all of them together?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

- “Page 2, line 35,
for “immediate or future benefit, direct or indirect” *substitute*
 “direct or indirect benefit.” ” (12)
- “Page 3, line 13, --
after “property is not”
insert “traceable or not”.” (13)
- “Page 3, line 17, --
after “fictitious person”
insert “or a person not traceable”.” (14)
- “Page 3, line 32, --
after “open market”
insert “or the fair value fixed by the Government”.” (15)
- “Page 4, line 37, --
after “transfer of”
add “ownership”. ” (16)
- “Page 4, line 45, --
after “Partnership Act, 2008”
insert “the Negotiable Instruments Act, 1881,
 the Transfer of Property Act, 1882.” ” (17)

HON. SPEAKER: I shall put Amendment Nos. 12 to 17 to clause 4 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 4, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clauses 5 to 7 were added to the Bill.

Clause 8 Substitution of new Sections for Section 5 and 6

Amendment made:

Page 5, *after* line 23, *insert* –

“(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall not apply to a transfer made in accordance with the provisions of section 190 of the Finance Act, 2016.”(7)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 8, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clause 9 Insertion of new Chapters III to VII

Amendment made:

“Page 9, line, 33,
for “served upon the other person who is a beneficial owner”,

substitute “issued to the beneficial owner if his identity is known”.”

(8)

“Page 11, *after* line 33, *insert* –

“(8) The *benamidar* or any other person who claims to be the owner of the property may either appear in person or take the assistance of an authorised representative of his choice to present his case.

Explanation.—For the purposes of sub-section (8), authorised representative means a person authorised in writing, being –

(i) a person related to the *benamidar* or such other person in any manner, or a person regularly employed by the *benamidar* or such other person as the case may be; or

(ii) any officer of a scheduled bank with which the *benamidar* or such other person maintains an account or has other regular dealings; or

(iii) any legal practitioner who is entitled to practice in any civil court in India; or

(iv) any person who has passed any accountancy examination recognised in this behalf by the Board; or

(v) any person who has acquired such educational qualifications as the Board may prescribe for this purpose.”. (9)

Page 13, line 4,

for “he is, or has been a Judge of a High Court”

substitute “he is a sitting or retired Judge of a High Court, who has completed not less than five years’ of service”.” (10)

(Shri Arun Jatiley)

HON. SPEAKER: Shri Premachandran, are you moving Amendment Nos. 18 to 27?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, Amendment No. 17 is regarding many negotiable instruments. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is about Amendment Nos. 18 to 27. I am not asking you to say anything.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, I am moving.

HON. SPEAKER: You may move Amendments No. 18 to 27 together now.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am moving Amendment No. 17.

HON. SPEAKER: Is it only Amendment No. 17. What to do about all the other Amendments, from 18 to 27?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : They are subject of some other sections.

HON. SPEAKER: Now, you may move Amendment Nos. 18 to 27.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

“Page 5, line 36, --
for “the Indian Legal Service”
substitute “the Law Department in the
 Central Government or a State Government”.” (18)

“Page 5, line 37, --
for “equivalent”
substitute “higher”.” (19)

“Page 5, *omit* lines 40 and 41. ” (20)

“Page 6, *for* lines 14 to 17, --
substitute “The Adjudicating Authority shall be bound
 by the procedure laid down by the Code of
 Civil Procedure, 1908”.” (21)

“Page 9, line 4, --
after “extending the same”
add “for a maximum period of another
 three months”.” (22)

“Page 13, lines 6 and 7, --
for “the Indian Legal Service”

substitute “the Law Department in the
Central Government or a State Government”.” (23)

“Page 13, line 7, --
for “equivalent”
substitute “higher”.” (24)

“Page 16, *omit* lines 46 and 47.” (25)

“Page 17, line 9, --
for “formulate that question”
substitute “admit the case”.” (26)

“Page 17, *for* lines 10 to 12, --
substitute “(4) The appeal shall be heard on the question of law,
and the respondents shall, at the hearing of the appeal,
be allowed to argue the case.”” (27)

HON. SPEAKER: I shall put Amendment Nos. 18 to 27 to clause 9 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 9, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

Clause 1 Short Title and Commencement

HON. SPEAKER: The Minister may now move Amendment No.2 to Clause 1.

Amendment made:

Page 1, line 3, *for* “2015”, *substitute* “2016”. (2)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

HON. SPEAKER: The Minister may now move Amendment No.1 to the Enacting Formula.

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* “Sixty-sixth”,
substitute “Sixty-seventh”. (1)

(Shri Arun Jaitley)

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill. ”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 28th July, 2016, at 11.00 a.m.

18.06 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, July 28, 2016/Shravana 6, 1938 (Saka)*
